राष्ट्रीय संस्करण



आज शपथ लेने वाले सभी सहयोगियों को बधाई और उनके मंत्री के रूप में कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे और मजबूत व समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे।
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

वर्ष 5 अंक 28

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 8 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

मोदी मंत्रिमंडल में चौंकाने वाले फेरबदल, जातिगत समीकरण के साथ अनुभव पर जोर

12 मंत्रियों का पत्ता साफ, 36 की एंट्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अक्सर अपने फैसलों से सबको चौंकाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल के पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार में भारी फेरबदल करते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि आज के बाद से सरकार का स्वरूप भी बदलेगा और कार्यशैली भी। फोकस होगा विकास। इसके संकेत प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए भी, जब उन्होंने मंत्रियों को बधाई देते हुए हैशटैग दिया, 'गवर्नमेंट फार ग्रोथ'। दरअसल, विस्तार से पहले ही 12 मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया गया था, जिनमें कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत छह कैबिनेट मंत्री शामिल थे। इस विस्तार में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 28 राज्यमंत्री हैं। सात राज्यमंत्रियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोन्नत किया गया है। 15 नए कैबिनेट मंत्रियों में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हैं।

मंत्रिमंडल विस्तार में जाहिर तौर पर कुछ का पत्ता तो केवल उनके प्रदर्शन के कारण कटा, लेकिन कुछ मंत्रियों का बाहर जाना चौंकाने वाला रहा, क्योंकि वे न सिर्फ अनुभवी रहे हैं, बल्कि अपनी क्षमता भी साबित करते रहे हैं। सरकार अब शायद नए चेहरों और नए जोश के साथ आगे के तीन वर्ष चलना चाहती है। ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट व अधिवक्ता के रूप में अनुभवी लोगों को जहां सरकार में शामिल किया गया है, वहीं ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को बड़ी संख्या में शामिल कर चुनावी और राजनीतिक समीकरण भी साधे गए। कोशिश यह रही कि सरकार में अधिकतर राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद रहें। फिलहाल 25 राज्यों के सांसद सरकार में हैं और पूर्वोत्तर से पांच को अवसर मिला है। यह अब तक का मोदी सरकार का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। पहले कार्यकाल में उनकी सरकार में 70 से कम मंत्री थे।

बुधवार सुबह प्रधानमंत्री ने चाय पर नए मंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें सरकार चलाने के गुर दिए। शाम को हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर राजनीतिक असर दिखा और कुछ हद तक प्रदर्शन सुधारने की कवायद। दरअसल, कोरोना काल के पिछले डेढ़ वर्ष में जहां कुछ मुद्दों पर चुनौती खड़ी हुई है, वहीं कुछ मंत्री खुद को साबित करने में असफल रहे हैं। अगले साल की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और साल के अंत में गुजरात में। ऐसे में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह जताने की कोशिश हुई कि मोदी सरकार सबको साथ लेकर चलती है। लिहाजा, प्रमुख जातियों से इस तरह प्रतिनिधित्व बढ़ा कि अब पीएम समेत 78 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी से हैं, 12 दलित वर्ग से और आठ आदिवासी समुदाय से। अल्पसंख्यकों को लेकर बार-बार सवाल उठाया जाता रहा है, लेकिन मोदी सरकार में अब पांच अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। जाहिर तौर पर चुनावी राज्य उप्र और गुजरात जैसे राज्यों को वरीयता मिली है।

संबंधित खबरें >> पेज 3,4

नए मंत्रियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के पूर्व सीएम सोनोवाल भी शामिल

78 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 27 अन्य पिछड़ा वर्ग, 12 दलित और आठ आदिवासी

चुनावी लिहाज से 25 राज्यों के भी अलग-अलग क्षेत्रों को दिया गया सरकार में प्रतिनिधित्व



1. राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने बुधवार को नए मंत्रियों को शपथ दिलाई 2. नारायण राणे (महाराष्ट्र) 3. सर्बानंद सोनोवाल (असम) 4. वीरेंद्र कुमार (मप्र) 5. ज्योतिरादित्य सिंधिया (मप्र) 6. रामचंद्र प्रसाद सिंह (बिहार) 7. अश्विनी वैष्णव (ओडिशा) 8. पशुपति कुमार पारस (बिहार) 9. मनसुख मांडविया (गुजरात) 10. भूपेंद्र यादव (मप्र) 11. पुरुषोत्तम रुपाला (गुजरात) 12. अनुराग ठाकुर (हिमाचल) 13. मिनाक्षी लेखी (दिल्ली) 14. शोभा करंदलजे (कर्नाटक)

हर्षवर्धन और रविशंकर का भी लिया गया इस्तीफा

हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, डीवी सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, संजय धोत्रे, देबाश्री चौधरी, रतन लाल कटारिया, बाबुल सुप्रियो और प्रताप चंद्र षाड़ंगी। रविशंकर प्रसाद का इस्तीफा चौंकाने वाला रहा। थावरचंद गहलोत को एक दिन पहले ही कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

यूपी से अब 14 मंत्री, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व

उत्तर प्रदेश से सात नए मंत्री बनाए गए हैं। यानी अब प्रधानमंत्री को छोड़कर 14 मंत्री यूपी से हैं। कोशिश रही कि राज्यों के भीतर हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो। लिहाजा पूर्वांचल, अवध, ब्रज, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में लिया गया है। सहयोगी दल से अनुप्रिया पटेल को शामिल किया गया।

नए मंत्रियों में 16 पहली बार बने हैं सांसद

मंत्री बने 16 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार सांसद बने हैं। जबकि एल. मुरुगन और सर्बानंद सोनोवाल ऐसे मंत्री हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। वर्तमान मंत्रिमंडल में अब सिर्फ राजनाथ सिंह ही ऐसे मंत्री हैं जो 1998-2004 के दौरान अटल सरकार में भी मंत्री थे। भूपेंद्र यादव इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है।

पूर्व ब्यूरोक्रेट बढ़े, अब 11 महिला मंत्री

सरकार में पहले तीन पूर्व ब्यूरोक्रेट थे, अब उनकी संख्या बढ़कर सात हो गई है। मंत्रिमंडल में अब 13 वकील, छह डाक्टर और पांच इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के हैं। महिलाओं की बात करें तो बुधवार को सात नई महिला मंत्रियों ने शपथ लीं। अब मंत्रिमंडल में कुल 11 महिला मंत्री हो गई हैं, जिनमें से दो कैबिनेट दर्जे की हैं।

सहयोगी दलों को मिला प्रतिनिधित्व

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार में सहयोगी दलों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। शिवसेना और अकाली दल के जाने के बाद केवल आरपीआइ ही सरकार में शामिल थी। अब बिहार से जदयू, लोजपा और उत्तर प्रदेश से अपना दल सरकार में शामिल है। ज्यादातर मंत्रियों ने हिंदी में शपथ ली, अंग्रेजी में शपथ लेने वाले कुछ ही मंत्री थे।

व्यापक फेरबदल के साथ मंत्रियों के विभाग भी बदले

जेएनएन, नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल के साथ मंत्रियों के विभागों में भी काफी परिवर्तन किए गए हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, एस.जयशंकर, निर्मला सीतारमण, अर्जुन मुंडा व स्मृति ईरानी जैसे कद्दावर मंत्रियों के विभागों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

मनसुख मांडविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। इसी तरह नौकरशाह से नेता बने अश्विन वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है। मांडविया के पास रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी रहेगी। , वैष्णव को संचार, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना तकनीक (आइटी) की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह जानकारी राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी की गई सूचना में दी गई है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को नवगठित सहयोग मंत्रालय की कमान भी सौंपी गई है। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। उनके पास वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की भी जिम्मेदारी रहेगी।

धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री होंगे। उनके पास कौशल विकास और इंटरप्रिन्योरशिप की भी जिम्मेदारी होगी। रामचंद्र प्रसाद नए इस्पात मंत्री होंगे। लोजपा के पशुपति कुमार पारस खाद्य एवं प्रसंस्करण, किरण रिजिजू कानून मंत्री बनाए गए हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के साथ आवास एवं शहरी मामलों की जिम्मेदारी भी देखेंगे।

प्रल्हाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री के साथ कोयला एवं खान मंत्री की जिम्मेदारी निभाएंगे। नारायण राणे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मामलों के साथ आयुष मंत्रालय का भी काम देखेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामलों की जिम्मेदारी दी गई है।

जागरण विशेष

मास्क ऐसा, आंख रहेगी सुरक्षित, नहीं फूलेगी सांस



प्रयागराज : इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की टीम ने एक एंटी कोरोना थ्रीडी प्रिंटेड मास्क बनाया है, जो सेहत के लिए बहुत उपयुक्त है। इससे आंख तो सुरक्षित रहेगी ही, सांस भी नहीं फूलेगी। (पेज-6)

लूटपाट का विरोध करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी की हत्या

नई दिल्ली : राजधानी के पाश इलाके वसंत विहार में अकेले रह रहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पीआर कुमारमंगलम की पत्नी व वरिष्ठ अधिवक्ता किट्टी कुमारमंगलम की मंगलवार रात लुटेरों ने हत्या कर दी। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लूट के 60 हजार रुपये बरामद कर लिए हैं। एक आरोपित फरार है। अक्सर घर पर आने वाले धोबी ने दो साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। (पेज-2)

नंदीग्राम केस से हटे जज

कहा- ममता ने न्याय व्यवस्था को कलंकित किया

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौशिक चंद पर मुख्यमंत्री ने लगाया था भाजपा के करीबी होने का आरोप
- चंद ने कहा, यह जज की छवि बिगाड़ने की कोशिश, ममता को देना होगा पांच लाख रुपये का जुर्माना

कलकत्ता हाई कोर्ट में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नंदीग्राम विधानसभा चुनाव के नतीजे को चुनौती देने वाली याचिका से न्यायाधीश कौशिक चंद ने खुद को अलग करते हुए कहा, ममता बनर्जी ने न्याय व्यवस्था को कलुषित (कलंकित) किया है। उन्होंने ममता पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विस क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले ममता ने हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को पत्र लिखा था, जिसमें उनसे अपने खिलाफ पूर्वाग्रह से बचने के लिए चुनाव याचिका को दूसरी पीठ (जस्टिस कौशिक चंद के अलावा) को सौंपने का आग्रह किया था। ममता ने दावा किया था कि चंद को अक्सर भाजपा नेताओं के साथ देखा गया है।

जस्टिस चंद ने इस मामले की बुधवार को खुद सुनवाई की। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति (जज) किसी राजनीतिक दल के लिए उपस्थित होता है तो यह सामान्य बात है। एक मामले की सुनवाई करते हुए वह अपने पूर्वाग्रह को छोड़ देता है। इसीलिए यह सुझाव देना बेतुका है कि एक जज, जिसके किसी दल से संबंध हैं, वह पक्षपात कर सकता है। यह पूर्व नियोजित ढंग से एक जज की छवि बिगाड़ने की कोशिश के समान है। उन्होंने कहा, न्याय व्यवस्था को कलुषित करने के लिए ममता को पांच लाख रुपये जुर्माना देना होगा। यह राशि स्वयं ममता देंगी, जो वकीलों के कोविड फंड में जमा की जाएगी। अब यह मामला किस कोर्ट में जाएगा, इसका फैसला मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ममता के वकील संजय बसु ने कहा, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमलोग सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं।



ममता बनर्जी। फाइल/इंटरनेट मीडिया

तृणमूल कांग्रेस ने जुर्माना लगाने की निंदा की : तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने ममता पर जुर्माना लगाने के कोर्ट के फैसले की कड़ी निंदा की है।

वायर व क्विंट समेत अन्य को राहत से हाई कोर्ट का इन्कार

नई दिल्ली : नए डिजिटल नियमों को चुनौती देने वाले द वायर, क्विंट और आल्ट न्यूज के स्वामित्व वाली कंपनी प्रावदा मीडिया फाउंडेशन को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इन कंपनियों ने उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम राहत देने की अपील की थी जिसे हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया। (पेज-2)

नौ राज्यों में कोरोना नियंत्रण उपायों को मजबूत किया जाएगा

नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि जिन नौ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उनमें महामारी को नियंत्रित करने के उपायों को मजबूत किया जाएगा। इन राज्यों में जांच और टीकाकरण में तेजी लाना, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की योजना बनाना और प्रभावी क्लीनिकल प्रबंधन जैसे उपाय किए जाएंगे। (पेज-6)

राकांपा नेता खडसे के दामाद गिरीश चौधरी ईडी की गिरफ्त में

मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खडसे के दामाद गिरीश चौधरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धाराओं के तहत पुणे के एक जमीन घोटाला मामले में हुई है। यह मामला उस समय का है जब खडसे भाजपा की देवेंद्र फड़नवीस सरकार में राजस्व मंत्री थे। (पेज-7)

चला गया हिंदी सिनेमा का कोहिनूर

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

- स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते हिंदुजा अस्पताल में थे भर्ती
- राजकीय सम्मान के साथ किए गए सिपुर्द-ए-खाक



मुंबई में बुधवार को अभिनेता दिलीप कुमार को उनकी पत्नी सायरा बानो ने नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। वह आखिरी क्षण तक साए की तरह उनके साथ रहीं। प्रेट्र

मुगल-ए-आजम, मधुमती, देवदास, कोहिनूर और गंगा-जमुना जैसी बेहतरीन फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाने वाले 98 वर्षीय 'ट्रेजडी किंग' दिलीप कुमार का बुधवार सुबह करीब साढ़े सात बजे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके पार्थिव शरीर को पहले बांद्रा स्थित उनके आवास पर लाया गया। जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, फिल्म इंडस्ट्री से शाह रुख खान, करण जौहर, धर्मेंद्र, अनिल कपूर, अनुपम खेर, रणबीर कपूर, विद्या बालन समेत कई नामीगिरामी सितारे उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। उनके निधन से गमगीन पत्नी सायरा बानो फूट-फूटकर रोती नजर आईं। उन्हें सांत्वना देते शाह रुख खान की तस्वीर काफी वायरल हो रही है।

'सौदागर' अभिनेता को अंतिम विदाई देने के लिए उनके फैंस का हुजूम न लगे, इसके लिए पुलिस ने कोरोना प्रोटोकाल के तहत इंतजामात किए थे। इसके बावजूद दिलीप कुमार के पार्थिव शरीर को कब्रिस्तान के भीतर पहुंचने में 15 मिनट का वक्त लगा। अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन उन्हें अंतिम विदाई देने सीधे कब्रिस्तान पहुंचे थे। 29 जून को दिलीप कुमार को सांस संबंधी समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह दूसरी बार था जब जून में ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। दिलीप कुमार का इलाज कर रहे डाक्टर जलील पारकर ने बताया कि 98 वर्ष की उम्र में इंसान को कई तरह की तकलीफें होती हैं। वही तकलीफें दिलीप साहब को भी थीं। उनका इलाज अच्छे से किया गया, लेकिन उम्र का तकाजा था। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि वह अपनी उम्र का शतक लगाएं। उनकी जैसी शख्सियत शायद ही कभी बालीवुड में आएगी।

दिलीप कुमार उभरते भारत का इतिहास खुद में समेटे थे। अभिनेता के आकर्षण ने सभी सीमाओं को पार किया और पूरे उपमहाद्वीप में उन्हें प्यार मिला। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया। दिलीप साहब हमेशा भारत के दिल में रहेंगे। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं।
- राम नाथ कोविन्द, राष्ट्रपति

दिलीप कुमार जी को सिनेमाई लीजेंड के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शक उनके काम पर मंत्रमुग्ध हो गए। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए क्षति है।
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व और प्रमुख हस्तियों ने भी जताया शोक

पेशावर, प्रेट्र : दिलीप कुमार के निधन पर पाक के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, पीएम इमरान खान व अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी शोक जताया है। ज्ञात हो, दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर, 1922 को पाक के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में हुआ था। उनका असली नाम यूसुफ खान था और उन्हें पाक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'निशान ए इम्तियाज' भी प्रदान किया गया था।

यादों की दुनिया (विशेष) पेज>>13
ज्वार भाटा थी पहली फिल्म पेज>>14

राजनीति

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को कैबिनेट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी, गुजरात से तीन और महाराष्ट्र से चार नए चेहरे सरकार में शामिल

विस्तार में चुनावी राज्यों का रखा गया पूरा ख्याल

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- बंगाल से चार नए लोगों को लेकर राज्य को दिया गया पूरा प्रतिनिधित्व

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार से आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले एक-दो वर्षों में किन-किन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक तौर पर जो राज्य जितनी अहमियत रखता है उसे उसी हिसाब से कैबिनेट में तवज्जो दी गई है। साथ ही केंद्र में बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की कम प्रतिनिधित्व की भरपाई भी की गई है। सरकार के लिए बेहद अहम राज्य उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव होने हैं। कैबिनेट विस्तार में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य से है।

उत्तर प्रदेश के लोस व रास के कुल सात सदस्यों को सरकार में शामिल किया गया है। इनके चयन में जातिगत समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री डा. महेंद्र नाथ पांडे समेत आठ मंत्री पहले से ही हैं। अब मोदी सरकार में उप्र का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व हो गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के कुछ माह बाद गुजरात में भी चुनाव है और संभवतः वहां के राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए ही मंत्रिमंडलीय विस्तार में तीन नए चेहरे शामिल किए गए हैं। इसके अलावा गुजरात के दो राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।

उप्र से महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी, मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल, आगरा के सांसद डा. सत्य पाल सिंह बघेल, जालौन के सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा, मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर, खीरी के सांसद अजय कुमार और राज्य सभा सांसद बी एल वर्मा ने राष्ट्रपति भवन में पद व गोपनीयता की शपथ ली। इनमें तीन दलित, दो कुर्मी, एक लोध और एक ब्राह्मण है। पार्टी ने दलितों को विशेष तवज्जो दी है। कुर्मी जाति के दो सांसदों को शामिल करने को भाजपा की तरफ से दो दर्जन से ज्यादा संसदीय सीटों पर दावेदारी मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। ज्ञात हो, बुधवार के विस्तार के बाद मोदी सरकार के 77 मंत्रियों में से 15 उत्तर प्रदेश से हैं।

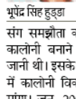
बंगाल से चार नए चेहरे शांतनु ठाकुर, जान बारला, नीतिश प्रमाणिक और सुभाष सरकार को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है, जबकि इस राज्य के दोनों मंत्रियों बाबुल सुप्रियो और देबाश्री चौधरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जिन चार नए चेहरों को शामिल किया गया, उन्हें बंगाल के लिए भाजपा की नई राजनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। मतुआ समुदाय के शांतनु ठाकुर बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में अलीपुरद्वार के सांसद हैं और उन्हें पार्टी इस क्षेत्र की राजनीति में अपना नया चेहरा बनाने की मंशा रखती है। कूचबिहार के सांसद और टीएमसी नेता ममता बनर्जी के पूर्व सहयोगी नीतिश प्रमाणिक को मंत्रिमंडल में शामिल कर भाजपा ने टीएमसी नेता को यह संकेत दिया है कि विधान सभा हार के बाद की राजनीति शुरू हो गई है। प्रमाणिक मोदी सरकार के सबसे युवा मंत्री भी होंगे।

गुजरात में नवंबर-दिसंबर, 2022 में चुनाव होना है और उसके पहले दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना कम ही है। यही वजह है कि राज्य का प्रतिनिधित्व केंद्र में बढ़ाया गया है। तीन नए चेहरे दर्शना विक्रम (सूरत), डा. महेंद्रभाई मुंजापारा (सुरेंद्रनगर) व चौहान देवसिंह (खेड़ा) को शामिल करने के साथ ही दो राज्य मंत्रियों मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र में चुनाव तो दूर है पर वहां से चार लोगों नारायण राणे, भागवत कृष्णा राव कराड, डा. भारती प्रवीण व कपिल मोरेश्वर पाटिल को शामिल किया गया है। 48 लोस सीटों वाले इस राज्य का प्रतिनिधित्व अभी तक मोदी सरकार में कम माना जा रहा था।

हुड्डा की बढ़ी मुश्किलें, रोहतक जमीन मामले की जांच करेगी सीबीआइ

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार में रोहतक में एक बिल्डर को जमीन देने के मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी है। जस्टिस यूयू ललित, अजय रस्तोगी व अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा बुधवार को दिए गए इस आदेश से हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

दरअसल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 2002 में रोहतक में आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्र विकसित करने के लिए हुड्डा सरकार के पास 850 एकड़ जमीन अधिगृहीत करने का प्रस्ताव भेजा था। अप्रैल, 2005 में उसे 422 एकड़ जमीन अधिगृहीत करने का आदेश मिला। इससे एक माह पहले यानी मार्च, 2005 में उद्दार गगन प्रापर्टीज लिमिटेड नामक रियल एस्टेट कंपनी ने कुछ किसानों संग समझौता कर लिया, जिनकी जमीन कालोनी बनाने के लिए अधिगृहीत की जानी थी। इसके बाद कंपनी ने 280 एकड़ में कालोनी विकसित करने का लाइसेंस मांगा। जून, 2006 में राज्य सरकार के से मंजूरी भी मिल गई। इसके बाद संबंधित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया था। बिल्डर को लाइसेंस जारी किए जाने के बाद भूस्वामियों के पावर आफ अटार्नी रखने वालों के माध्यम से जमीन भी उसके नाम कर दी गई।



भूपेंद्र सिंह हुड्डा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को तत्कालीन कांग्रेस सरकार में बिल्डर को जमीन देने की जांच सौंपी

2016 में कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण नहीं करने के फैसले को रद कर दिया था पेज>>4

15 जुलाई तक दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से आक्सीजन भंडारण मामले में स्थिति रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने 1,265 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता होने का दावा किया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 8 जुलाई, 2021

यमुना को प्रदूषित करने वाली 1,068 औद्योगिक इकाइयां होंगी बंद

बड़ी कार्रवाई ▶ स्थिति में सुधार नहीं होने पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिया आदेश

इन इकाइयों के बिजली-पानी के कनेक्शन काटने का भी दिया निर्देश

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने राजधानी की 1,068 औद्योगिक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी इकाइयों के बिजली-पानी कनेक्शन काटने का भी निर्देश जारी किया। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम इन इकाइयों को बंद करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आदेश का पालन नहीं होने पर जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दैनिक जागरण भी पिछले करीब एक सप्ताह से यमुना प्रदूषण को लेकर लगातार समाचार प्रकाशित कर रहा है।

जानकारी के मुताबिक डीपीसीसी ने दिल्ली के 13 विभिन्न औद्योगिक इलाकों में स्थित इन इकाइयों का निरीक्षण किया तो इन्हें सीधे तौर पर जल प्रदूषित करने का दोषी पाया। इन इकाइयों में जो कामन इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) लगे हुए हैं, वे भी या तो खराब पड़े हैं या ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, जिन इलाकों में ये इकाइयां चल रही हैं, वहां सामूहिक स्तर पर लगे बड़े सीईटीपी प्लांट भी प्रदूषित जल का ठीक से शोधन नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा, इन इकाइयों का प्रदूषित जल नालों के जरिये सीधे यमुना में पहुंच रहा है।

डीपीसीसी की टीम ने फरवरी 2019 से फरवरी 2020 के दौरान इन सभी सीईटीपी संयंत्रों से शोधित जल के नमूने उठाए तो वे सभी नमूने तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद पांच अप्रैल, 2021 को इन सभी इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इन पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। बावजूद इसके स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

अंततः यमुना मानिटरिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव हैं, के निर्देश और एनजीटी के भी सख्त रवैये को देखते हुए डीपीसीसी ने मंगलवार शाम उक्त सभी इकाइयां को तत्काल प्रभाव से सील करने के आदेश जारी कर दिए। डीपीसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 ए के तहत निजी बिजली वितरण कंपनियों, जल बोर्ड और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम को इन इकाइयों का बिजली-पानी कनेक्शन काटने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आदेश की अनुपालना कराने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को दी गई है।

13 अलग-अलग इलाकों में मौजूद इन इकाइयों को बंद करने की कार्रवाई एसडीएम करेंगे सुनिश्चित



इन क्षेत्रों में सील होंगी इकाइयां
ओखला, मायापुरी, नारायणा, झिलमिल, बादली, लारेंस रोड, मंगोलपुरी, बवाना, नरेला, जीटी करनाल रोड, एसएमई जहांगीरपुरी, उद्योग नगर।



ख्याला में एक औद्योगिक इकाई का बिजली कनेक्शन काटने और एक अन्य इकाई को सील करने की कार्रवाई करते डीपीसीसी कर्मचारी। सौजन्य : डीपीसीसी

यमुना किनारे अतिक्रमण और अनधिकृत गतिविधियां रोकने को पुलिस की मदद ले डीडीए : उपराज्यपाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- समीक्षा बैठक में डीडीए उपाध्यक्ष को यमुना खादर क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश
- नदी के किनारों पर सुंदरीकरण कार्य को गति देने के लिए समय सीमा तय करने को भी कहा

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष अनुराग जैन को यमुना खादर क्षेत्र में अतिक्रमण और अनधिकृत गतिविधियां रोकने के लिए सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्होंने पुलिस की मदद लेने को कहा है। साथ ही उन्होंने यमुना के किनारों के सुंदरीकरण कार्य को गति देने के लिए हर योजना की समय सीमा तय करने को भी कहा है।

गौरतलब है कि डीडीए वजीराबाद और ओखला बैराज के बीच 22 किलोमीटर लंबे शहरी रिवरफ्रंट का विकास कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य साइकिलिंग ट्रैक, वाकवे, ईको-ट्रेल्स टू वेटलैंड्स जैसी सुविधाएं मुहैया कराना है। इसमें यमुना के बाढ़ ग्रस्त मैदानी क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने की भी परिकल्पना की गई है। बुधवार को उपराज्यपाल ने इसी की समीक्षा बैठक रखी। उन्होंने अभी तक किए गए कायाकल्प कार्यों की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक प्रोजेक्ट को विशिष्ट समय-सीमा दी जानी चाहिए। उसकी प्रभावी निगरानी की जाए और उसे समय पर पूरा करने के लिए सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही बैजल ने यह भी निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में लोगों को ईको फ्रेंडली सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, क्षेत्र में जीरो वेस्ट शौचालय, पीने के पानी, बाहर बैठने के लिए सुविधाएं, सोलर लाइट और साइनेज आदि की व्यवस्था भी की जाए ताकि यहां ज्यादा से लोग आ सकें।

10 हिस्सों में किया जा रहा है विकास

रिवरफ्रंट की इस परियोजना को 10 हिस्सों में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में डीडीए ने अपने बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए 105 करोड़ का प्रविधान किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत वजीराबाद के आसपास पांच किलोमीटर के दायरे में यमुना नदी को विश्व स्तरीय ईकोलाजिकल बनाने की योजना है। इसके चलते यह इलाका पर्यटकों के लिए तो विकसित होगा ही, साथ ही उसे इस तरह से विकसित किया जाएगा कि लोग खुद को यमुना और प्रकृति से जुड़ा महसूस करें। इस प्रोजेक्ट से यमुना को प्रदूषण से बचाने और वन्यजीवों को सहारा देने वाले स्थानीय वातावरण के अनुकूल पौधों की विविध प्रजातियों के विकास में मदद भी मिलेगी। इस इलाके में बड़ा वोटिंग क्लब भी खोला जाएगा और यमुना में गिरने वाले नालों को नदी से अलग कर दिया जाएगा।

न्यूज गैलरी

पांच सितारा होटल 24 घंटे परोस सकेंगे शराब

नई दिल्ली : दिल्ली में अब पांच सितारा होटल एक करोड़ रुपये की फीस देकर 24 घंटे अपने सभी काउंटरों पर शराब परोस सकेंगे। दिल्ली सरकार ने होटल, क्लब, मोटल, बार व रेस्टोरेंट को नई आबकारी नीति के तहत शराब बेचने संबंधी लाइसेंस देने के लिए जो नियम बनाए हैं, उनमें वार्षिक लाइसेंस फीस में भारी इजाफा किया है। इससे दिल्ली सरकार के राजस्व में भारी वृद्धि होने की संभावना है। इसी क्रम में राजधानी के दो स्टार होटल के बार या रेस्टोरेंट में शराब परोसने के लिए वार्षिक फीस दस लाख रुपये, तीन व चार स्टार होटल के बार के लिए पंद्रह लाख रुपये देना होगा। राजधानी के सौ कमरे के गेस्ट हाउस या बजट होटल में शराब परोसने की लाइसेंस फीस 2.5 लाख तय की गई है। (राब्यू)

जोर पकड़ने लगी जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी खोलने की मांग

नई दिल्ली : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जेएनयू छात्रसंघ के नेतृत्व में छात्रों ने बुधवार को लाइब्रेरी परिसर में धरना प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग थी कि लाइब्रेरी को तत्काल खोला जाए। शोधार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्र लाइब्रेरी अधिकारी से मिलने की गुजारिश कर रहे थे। वहीं जेएनयू ने एक दिशानिर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि जब तक सरकार से दिशानिर्देश नहीं मिलता, तब तक लाइब्रेरी नहीं खोली जाएगी। परिसर में 12 जुलाई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। (जासं)

जल संकट को लेकर आज भाजपा करेगी प्रदर्शन

नई दिल्ली : जल संकट को लेकर भाजपा ने बृहस्पतिवार को पूरी दिल्ली में तीन हजार से ज्यादा स्थानों पर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ ही सभी पदाधिकारी, सांसद व विधायक अलग-अलग स्थानों पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर दिल्ली सरकार से जल संकट दूर करने की मांग करेंगे। भाजपा नेताओं का कहना है कि पानी की समस्या हल करने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। प्रदेश भाजपा महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की लापरवाही से इस गर्मी में दिल्ली के कई इलाकों में लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। (राब्यू)

मनी लांड्रिंग मामले में यूनिटेक समूह के गुरुग्राम स्थित तीन भूखंड जब्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बताया कि उसने यूनिटेक समूह व उसके प्रवर्तकों संजय चंद्रा व अजय चंद्रा के खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में हरियाणा स्थित 106 करोड़ रुपये से ज्यादा के भूखंडों को जब्त किया है।

ईडी ने एक बयान में बताया कि गुरुग्राम में स्थित तीन अचल संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत आदेश जारी हुआ था। इन संपत्तियों की कीमत 106.08 करोड़ रुपये आंकी गई है। केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, 'इन संपत्तियों को चंद्रा की दो मुखौटा कंपनियों इरोड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड व कोरे कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था। जांच के दौरान पता चला कि इन संपत्तियों को अपराध के जरिये अर्जित संपत्ति से खरीदा गया है। दोनों कंपनियों को यूनिटेक समूह के प्रवर्तक नियंत्रित करते हैं और अपराध की कमाई को इनके जरिये सिंगापुर व केमैन द्वीप भेजा गया।' पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत यूनिटेक समूह और उसके प्रवर्तकों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि समूह के प्रवर्तकों ने 2,000 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि अवैध तरीके से साइप्रस व केमैन द्वीप भेजी है।

द वायर, क्विंट व आल्ट न्यूज को राहत देने से हाई कोर्ट का इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने की वेब पोर्टल ने की थी मांग, पीटीआइ ने भी नए आइटी नियमों को दी चुनौती

नए डिजिटल नियमों को चुनौती देने वाले द वायर, क्विंट और आल्ट न्यूज के स्वामित्व वाली कंपनी प्रावदा मीडिया फाउंडेशन को हाई कोई से कोई राहत नहीं मिली है। इन कंपनियों ने उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम राहत देने की अपील की थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया।

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इसके साथ ही मामले में सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सूचित किया कि उसने मामले को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की है। मुख्य पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से पूछा कि क्या स्थानांतरण याचिका को प्राथमिकता दी गई है। बनर्जी का जवाब हां में रहा। इसके बाद पीठ ने तीनों की याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

पोर्टलों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने पीठ से अंतरिम सुरक्षा का आदेश पारित करने का आग्रह किया, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक डिजिटल मीडिया पोर्टलों की तरफ से दायर याचिकाओं का जवाब नहीं दिया है। वहीं, एडिशनल सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि 1,700 डिजिटल मीडिया संस्थानों ने डिजिटल नियमों के तहत अपनी सूचना उपलब्ध कराई है।

पीटीआइ ने कहा, भय के युग की होगी शुरुआत : प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया (पीटीआइ) ने भी नई डिजिटल नीति को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नई डिजिटल नीति के माध्यम से केंद्र सरकार डिजिटल न्यूज मीडिया को विनियमित करने की कोशिश कर रही है। याचिका में नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। कहा है कि आइटी नियम निगरानी और भय के युग की शुरुआत करेंगे।



20 अगस्त तक के लिए स्थगित की सुनवाई।

लूटपाट का विरोध करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारमंगलम की पत्नी की हत्या

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- घर में आने वाले धोबी ने दो साथियों के साथ मिलकर की हत्या
- दो आरोपित गिरफ्तार, तीसरे की लोकेशन राजस्थान में मिली

राजधानी के पाश इलाके वसंत विहार में अकेले रह रहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पीआर कुमारमंगलम की पत्नी व वरिष्ठ अधिवक्ता किट्टी कुमारमंगलम की मंगलवार रात लुटेरों ने हत्या कर दी। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लूट के 60 हजार रुपये बरामद कर लिए हैं। एक आरोपित फरार है। अक्सर घर पर आने वाले धोबी ने दो साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।

मालूम हो कि पीआर कुमारमंगलम नरसिंह राव सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। वह भारतीय राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रहे। उनकी 2000 में ब्लड कैंसर से मौत हो गई थी। दक्षिण-पश्चिमी जिले के पुलिस उपायुक्त इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे इलाके का धोबी राजू कपड़े लेने घर आया था। दरवाजा खोलकर घरेलू सहायिका मिथिला कपड़े लेने चली गई। तभी राजू के दो अन्य साथी सूरज और राकेश घर में घुस गए। राजू ने एक कमरे में मिथिला को बंधक बना लिया। सूरज और राकेश ने किट्टी कुमारमंगलम को काबू कर लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनों ने तकिये से मुंह दबाकर उनकी हत्या कर दी और गहने व रुपये लूटकर तीनों भाग गए।

मिथिला की सूचना पर पुलिस पहुंची तो कमरे में बुजुर्ग महिला का शव मिला। पुलिस ने मिथिला के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपित राजू को भंवर सिंह कैंप स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर राकेश को भी गिरफ्तार कर उससे लूट के 60 हजार रुपये बरामद कर लिए। तीसरे आरोपित सूरज की लोकेशन राजस्थान में मिली है। उसकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमें राजस्थान पहुंच चुकी थीं। राजू ने बताया कि उसने मिथिला का भी तकिये से दम घोंटा था, लेकिन वह लगातार संघर्ष कर रही थी। इसलिए वह जल्दबाजी में उसे छोड़कर भाग गया।

घरेलू सहायिका भी जांच के घेरे में : पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मिथिला ने पांच दिन पहले ही किट्टी के घर में काम करना शुरू किया था। वारदात के बाद मिथिला के पति व देवर अजय ही सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे। अजय ने ही पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मिथिला से भी पूछताछ कर रही है।

वरिष्ठ नागरिकों की सूची में नहीं थीं किट्टी : पुलिस उपायुक्त ने बताया कि किट्टी पुलिस के अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सूची में शामिल नहीं थीं। उनकी बेटी अक्सर उनके पास रहती थीं। उनके बेटे के आधार कार्ड में भी वसंत विहार का ही पता रजिस्टर्ड है। इसीलिए उन्हें इस सूची में पंजीकृत नहीं किया गया था।



किट्टी कुमारमंगलम फोटो। सौजन्य- दिल्ली पुलिस

जूही चावला की याचिका को जज ने कहा 'सबसे बेकार आवेदन'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली



हाई कोर्ट ने जुर्माना राशि एक सप्ताह में जमा करने का निर्देश दिया

देश में 5जी नेटवर्क के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला समेत अन्य आवेदनकर्ताओं के आवेदन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। बुधवार को सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति जेआर मिधा की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बेकार आवेदन है। कोर्ट फीस और जुर्माना राशि जमा करने के मामले पर पीठ ने कहा कि वे आवेदनकर्ताओं के व्यवहार से स्तब्ध हैं कि वे जुर्माना राशि जमा करने को भी तैयार नहीं हैं। पीठ ने कहा कि चावला और अन्य पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाते समय अवमानना की कार्रवाई न करके अदालत ने नरम रुख अपनाया था।

पीठ कहा उन्होंने अपने न्यायिक करियर में ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं देखा जो अदालत की फीस का भुगतान करने को तैयार नहीं है। पीठ ये प्रतिक्रिया तब दी जब चावला की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मीत मल्होत्रा ने जुर्माना राशि को माफ करने के आवेदन वापस लेते हुए कहा कि जुर्माना राशि एक सप्ताह के अंदर या तो भर दी जाएगी या फिर इसके खिलाफ कानूनी राहत ली जाएगी।

जूही समेत आवेदनकर्ताओं ने अधिवक्ता मंजुल बाजपेयी के माध्यम से आवेदन दाखिल कर कोर्ट फीस वापस करने, जुर्माना में छूट देने और फैसले में खारिज शब्द को निरस्त से बदलने की मांग की है। पीठ ने कहा कि इस आवेदन को कोर्ट फीस जमा करने के बाद ही न्यायमूर्ति संजीव नरुला के समक्ष सूचीबद्ध करेंगे। इस दौरान चावला की तरफ से पेश हुए एक अन्य अधिवक्ता दीपक खोसला ने पीठ को सूचित किया कि कोर्ट फीस जमा कर दी गई है। इस पर पीठ ने इसे 12 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में होगी कोरोना के नए वैरिएंट की जांच

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोक नायक अस्पताल में जीनोम सिक्वेंसिंग सुविधा का किया उद्घाटन

अब दिल्ली सरकार के अस्पताल में कोरोना के नए वैरिएंट डेल्टा प्लस आदि की जांच हो सकेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को लोक नायक अस्पताल और मौलाना आजाद मेडिकल कालेज की संयुक्त जेनेटिक लेबोरेटरी में सार्स सीओवी-2 जीनोम सिक्वेंसिंग (अनुक्रमण) सुविधा का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। उत्तर भारत में इस तरह की यह तीसरी सुविधा है।

सीएम ने कहा कि इस तरह के मामलों में अभी तक हमें सैंपल केंद्र सरकार की एनसीडीसी लैब भेजने पड़ते थे, लेकिन अब हम अपनी लैब में जांच कर पाएंगे। जेनेटिक एनलाइजर मशीन से विश्लेषण कर नए वैरिएंट का पता लगाया जा सकेगा जब वैरिएंट का पता चल जाएगा, तो हमें उससे निपटने के लिए रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि यह मशीन संभावित तीसरी लहर में बहुत मददगार साबित होगी और कोरोना खत्म होने के बाद भी इससे दूसरी बीमारियों का विश्लेषण किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकनायक अस्पताल में जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए जेनेटिक एनलाइजर मशीन खरीदी गई है। उन्होंने लैब जल्दी शुरू करने के लिए, अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डा. सुरेश कुमार और उनकी टीम को बधाई दी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के आइएलबीएस अस्पताल में एक और लैब का कल उद्घाटन किया जाएगा। यानी दिल्ली के अंदर अब लोकनायक और आइएलबीएस में दो लैब खुल जाएंगी। सीएम ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम लोगों ने काफी गतिविधियां खोल दी हैं, बाकी गतिविधियों को हम चरणबद्ध तरीके से खोलना चाहते हैं।

दिल्ली में बंद रहे 72 फीसद टीकाकरण केंद्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना के टीके की कमी के कारण दिल्ली में बुधवार करीब 72 फीसद टीकाकरण केंद्र बन रहे। इस वजह से टीका लगवाने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ा। सिर्फ 22,289 लोगों को ही टीका लग पाया। जबकि पिछले सप्ताह में प्रतिदिन औसतन डेढ़ लाख से अधिक लोगों को टीका लग रहा था। इस लिहाज से 85 फीसद तक टीकाकरण कम हो गया। हालांकि, छह जुलाई की रात कोविशील्ड व कोवैक्सीन की डोज दिल्ली पहुंची है। उम्मीद है कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ेगी।

भंडार बनाए तो आक्सीजन क्यों नहीं रखते : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : भविष्य में दिल्ली में मेडिकल आक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए भंडारण की व्यवस्था करने के बावजूद आक्सीजन नहीं रखने के पीछे दिल्ली सरकार के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि भंडारण की व्यवस्था की है तो आक्सीजन क्यों नहीं रखते। पीठ ने पूछा क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वैज्ञानिक रूप से इसका विश्लेषण कर रहा है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा हो।

पीठ ने कहा कि जब आक्सीजन दिल्ली लानी थी, तब आपके पास टैंकर नहीं थे और फिर भंडारण की व्यवस्था नहीं थी। आपात स्थिति में सभी राज्यों को आक्सीजन की जरूरत होने पर आपको बाहर से आक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली तो खाली पड़े भंडार बेकार साबित होंगे। उक्त टिप्पणी करते हुए पीठ ने दिल्ली सरकार को इस संबंध में 15 जुलाई को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

अध्ययन

ग्रीनपीस इंडिया ने किया देश की आठ सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की राजधानियों में नाइट्रोजन डाइआक्साइड सांद्रता का विश्लेषण

दिल्ली का एनओ 2 प्रदूषण एक साल में 125 फीसद बढ़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर और लखनऊ में भी एनओ 2 प्रदूषण में वृद्धि हुई, लेकिन दिल्ली में हुआ सबसे अधिक इजाफा
- इस प्रदूषण से श्वसन तंत्र और मस्तिष्क होता है प्रभावित

ग्रीनपीस इंडिया का एक नया अध्ययन बताता है कि अप्रैल 2020 और अप्रैल 2021 के बीच दिल्ली में एनओ 2 (नाइट्रोजन डाइआक्साइड) प्रदूषण में 125 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अध्ययन में देश के आठ सर्वाधिक आबादी वाले राज्यों की राजधानियों में एनओ 2 सांद्रता का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि सभी आठ राजधानियों- मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर और लखनऊ में एनओ 2 प्रदूषण में वृद्धि हुई है, लेकिन दिल्ली में सबसे अधिक इजाफा देखा गया है।

गौरतलब है कि एनओ 2 एक खतरनाक वायु प्रदूषक है जो ईंधन के जलने पर निकलता है। इसका मुख्य स्रोत मोटर वाहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक इकाइयां हैं। इस वायु प्रदूषक एनओ 2 का एक्सपोजर सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इससे श्वसन तंत्र और मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है।

अध्ययन के मुताबिक सैटेलाइट इमेजों से पता चलता है कि एनओ 2 प्रदूषण अप्रैल 2020 के मुकाबले अप्रैल 2021 में 125 फीसद तक बढ़ गया है। बिहाइंड द स्मोकस्क्रीन : सैटेलाइट डेटा नामक इस अध्ययन रिपोर्ट से पता चलता है कि यह वृद्धि और भी अधिक (146 फीसद) होती अगर मौसम की स्थिति 2020 के समान होती।

अप्रैल 2021 की तुलना में मुंबई में एनओ 2 प्रदूषण 52 फीसद, बेंगलुरु में 90 फीसद, हैदराबाद में 69 फीसद, चेन्नई में 94 फीसद, कोलकाता में 11 फीसद, जयपुर में 47 फीसद और लखनऊ में 32 फीसद बढ़ा है। जीवाश्म ईंधन से संबंधित वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य प्रभाव गंभीर है और कई रिपोर्टों में बार-बार परिलक्षित होता है।

ग्रीनपीस इंडिया कहना है कि बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि अभी भी ज्यादातर शहरों में जहरीले वायु प्रदूषण के साथ जुड़ी हुई है। इन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक है। जीवाश्म ईंधन जलाने पर हमारी निर्भरता के लिए शहर और लोग पहले से ही एक बड़ी कीमत चुका रहे हैं, यह व्यवसाय हमेशा की तरह जारी नहीं रह सकता है। ग्रीनपीस इंडिया के वरिष्ठ जलवायु प्रचारक अविनाश चंचल ने कहा कि राष्ट्रव्यापी लाकडाउन के दौरान लोगों ने साफ आसमान देखा और ताजी हवा में सांस ली, हालांकि यह महामारी का एक अनपेक्षित परिणाम था।

चंचल के मुताबिक जीवाश्म ईंधन की खपत पर आधारित मोटर वाहन और उद्योग भारतीय शहरों में एनओ 2 प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। सरकारों, स्थानीय प्रशासन और शहर के योजनाकारों को निजी स्वामित्व वाले वाहनों से एक कुशल, स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में बदलाव की पहल करनी चाहिए।



खतरनाक प्रदूषण से बचना है जरूरी। फाइल फोटो

आनलाइन कक्षा में शिक्षिका पढ़ा रही थी नफरत का पाठ

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

सेक्टर-10 स्थित यूरो इंटरनेशनल स्कूल की आनलाइन कक्षा में शिक्षिका ने विद्यार्थियों को मौजूदा सरकार के बारे में भड़काऊ बातें कहीं। इस पर अभिभावकों ने आपत्ति जताई और स्कूल प्रबंधन से शिकायत कर दी। अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन ने बुधवार को शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस दिया। इसके जवाब में शिक्षिका शोभा दास ने माफीनामा लिखते हुए स्वयं स्कूल से इस्तीफा दे दिया। स्कूल प्राचार्य निधि कपूर ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को अभिभावकों की शिकायत पर शिक्षिका को स्कूल बुलाया था। प्राचार्य ने बताया कि उन्होंने शिक्षिका का पक्ष जानने के लिए उन्हें स्कूल में तलब किया था, लेकिन उन्होंने माफीनामा देते हुए सीधा इस्तीफा दे दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया है।

वायरल हुआ वीडियो : स्कूल की आनलाइन कक्षा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 10वीं के समाजशास्त्र विषय की आनलाइन कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों यह कहती सुनी जा सकती हैं कि भाजपा सरकार देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है, जबकि कांग्रेस सरकार देश को काफी आगे लेकर गई। शिक्षिका ने आगे कहा कि यह सरकार जो सीएए कानून लेकर आई है, उससे अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान हो रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षिका ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार जो राम मंदिर बना रही है, वह हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए बना रही है।

अभिभावकों का कहना है कि इस तरह से कट्टरता फैलाना और बच्चों को गुमराह करना सही नहीं है। बच्चों का यह भी कहना था कि शिक्षिका पाठ्यक्रम की चीजें पढ़ाने के बजाय इस तरह की बातें करती थीं।



उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव है। भाजपा ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से सात मंत्री बनाए गए हैं।

43 चेहरों को मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल किया गया है। साथ ही कुछ मंत्रियों को पदोन्नत किया गया है।

खराब प्रदर्शन बना विदाई का आधार

ढिलाई पड़ी भारी : निशंक, हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा और संतोष गंगवार का पत्ता मंत्रिमंडल से कटा

नीलू रंजन • नई दिल्ली

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुए पहले बड़े फेरबदल में रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक, हर्षवर्धन और प्रकाश जावडेकर समेत 12 मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर हो गए। निशंक और हर्षवर्धन जैसे मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने के पीछे उनके खराब प्रदर्शन को अहम कारण बताया जा रहा है। लेकिन, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावडेकर के इस्तीफे इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं। ये दोनों न सिर्फ 2014 से मंत्री थे, बल्कि कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी बखूबी संभाल भी रहे थे। माना जा रहा है कि इन दोनों को संगठन के लिए सरकार से मुक्त किया गया है।

हर्षवर्धन की स्थिति मोदी सरकार एक से ही डांवाडोल रही है। पेशे से डाक्टर और पोलियो उन्मूलन अभियान की रूपरेखा तैयार करने में उनके योगदान को देखते हुए 2014 में उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन दो साल में ही उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय से हटाकर अर्थ साइंस मंत्रालय में भेज दिया गया और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को सौंपी गई। 2019 में उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ-साथ विज्ञान व तकनीक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। कोरोना जैसे वैश्विक संकट के दौर में इन दोनों मंत्रालय की अहम भूमिका थी। लेकिन हर्षवर्धन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी भूमिका तराशने में विफल रहे। इसकी जगह नीति आयोग के सदस्य डाक्टर वीके पाल और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डाक्टर विजय राघवन ने आगे बढ़कर कमान संभाल ली। प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट में उनके पास बताने के लिए कुछ खास नहीं था। इसीलिए इस बार उन्हें मंत्रिमंडल से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया।

शिक्षा मंत्री के रूप में कई प्रयोगों के बाद जब रमेश पोखरियाल निशंक को लाया गया, तो उम्मीद की गई कि वे देश की शिक्षा प्रणाली भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप लागू करने में सफल होंगे। कई पुस्तकों के लेखक और भारतीय संस्कृति के जानकार के रूप में उनसे ऐसी अपेक्षा अनुचित भी नहीं थी। लेकिन, नई शिक्षा नीति के अंतिम रूप देने के अलावा उनके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। कोरोना के कारण देश की पूरी शिक्षा प्रणाली अस्त-व्यस्त रही। शिक्षा के क्षेत्र में कोई नवाचार लाकर उसे नई दिशा देने की जगह निशंक उससे निपटने के लिए संघर्ष करते दिखे।

शिक्षा मंत्रालय की सभी संस्थाओं पर उनकी पकड़ इतनी कमजोर दिखी कि उन विभागों द्वारा वित्त प्रदत्त पत्रिकाओं में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगला जाता रहा और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला जानकारी में आने के बाद भी वे तत्काल कार्रवाई करने में विफल रहे। शिक्षा मंत्रालय के हालात को लेकर प्रधानमंत्री की नाराजगी को इस बात से समझा जा सकता है कि वहां निशंक के साथ-साथ उनके राज्यमंत्री संजय धोत्रे को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

इसी तरह रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में सदानंद गौड़ा कोरोना काल में जरूरी दवाओं और उनके लिए जरूरी बल्क ड्रग की सप्लाई सुनिश्चित करने में विफल रहे। इसकी जिम्मेदारी सचिवों की उच्च स्तरीय समिति को निभानी पड़ी। यही स्थिति श्रम मंत्रालय में संतोष गंगवार की भी रही। कोरोना काल में श्रमिकों के बड़े पैमाने पर पलायन और उनकी दुश्वारियों को दूर करने के लिए एक पोर्टल बनाने की घोषणा की गई, लेकिन अभी तक यह बनकर तैयार नहीं हो पाया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार की फटकार भी लगा चुकी है। इस्तीफा देने वाले एक अन्य मंत्री थावरचंद गहलोत को सम्मानजनक विदाई दी गई और उन्हें पहले ही कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया।

2019 में जीत के बाद सादगी के लिए चर्चा में आने के बाद प्रधानमंत्री ने प्रताप चंद्र षड़ंगी को राज्यमंत्री बनाकर उन पर अपना भरोसा भी जताया, लेकिन पिछले दो सालों में उनका योगदान शून्य रहा। कुछ यही हाल राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो, रतनलाल कटारिया और देवाश्री चौधरी का भी रहा।



केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने वाले (ऊपर की पंक्ति में बाएं से) डॉ. हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर और रमेश पोखरियाल निशंक। (बीच की पंक्ति में बाएं से) थावरचंद गहलोत, डीवी सदानंद गौड़ा, संतोष कुमार गंगवार और रतनलाल कटारिया। (नीचे की पंक्ति में बाएं से) बाबुल सुप्रियो, प्रताप चंद्र षड़ंगी, धोत्रे संजय शामराव और देवाश्री चौधरी • फाइल फोटो/एएनआइ

विस्तार के बाद मोदी मंत्रिमंडल का स्वरूप

नरेंद्र मोदी	प्रधानमंत्री (कार्मिक, जनशिकायतें, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सभी नीतिगत मामले और अन्य सभी मंत्रालय जो किसी के पास न हों)

कैबिनेट मंत्री

नाम	मंत्रालय
राजनाथ सिंह	रक्षा
अमित शाह	गृह और सहकारिता
नितिन गडकरी	सड़क परिवहन व हाईवे
निर्मला सीतारमण	वित्त और कारपोरेट अफेयर्स
नरेंद्र सिंह तोमर	कृषि व किसान कल्याण
डा. एस. जयशंकर	विदेश
अर्जुन मुंडा	आदिवासी मामले
स्मृति ईरानी	महिला व बाल विकास
पीयूष गोयल	वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा
धर्मेंद्र प्रधान	शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता
प्रल्हाद जोशी	संसदीय कार्य, कोयला, खदान
नारायण राणे	सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
सर्बानंद सोनोवाल	पोत परिवहन और जलमार्ग, आयुष
मुख्तार अब्बास नकवी	अल्पसंख्यक मामले
वीरेंद्र कुमार	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
गिरिराज सिंह	ग्रामीण विकास, पंचायती राज
ज्योतिरादित्य सिंधिया	नागरिक उड्डयन
रामचंद्र प्रसाद सिंह	इस्पात
अश्विनी वैष्णव	रेल, संचार, इलेक्ट्रानिक एंड इन्फार्मेशन टेक्नालाजी
पशुपति कुमार पारस	खाद्य प्रसंस्करण
गजेंद्र शेखावत	जलशक्ति
राजकुमार सिंह	ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय
मनसुख मांडविया	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक
भूपेंद्र यादव	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार
महेंद्र नाथ पांडेय	भारी उद्योग
पुरुषोतम रूपाला	मत्स्य और पशुपालन एवं डेयरी
जी किशन रेड्डी	संस्कृति, पर्यटन, पूर्वोत्तर विकास
अनुराग ठाकुर	सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले, खेल

स्वतंत्र प्रभार

राव इंद्रजीत	सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन, प्लानिंग, कारपोरेट अफेयर
जितेंद्र सिंह	विज्ञान एवं तकनीक, पृथ्वी विज्ञान, पीएमओ, कार्मिक एवं पेंशन, एटामिक एनर्जी, अंतरिक्ष

राज्य मंत्री

श्रीपद नाइक	पोत परिवहन और जलमार्ग, पर्यटन
फग्गन सिंह कुलस्ते	इस्पात, ग्रामीण विकास
प्रह्लाद सिंह पटेल	जलशक्ति, खाद्य प्रसंस्करण
अर्जुन राम मेघवाल	संसदीय कार्य, संस्कृति
वीके सिंह	सड़क परिवहन, राजमार्ग, नागरिक उड्डयन
अश्विनी कुमार चौबे	उपभोक्ता मामले, वन व पर्यावरण
कृष्णपाल	ऊर्जा, भारी उद्योग
दानवे राव साहब	रेलवे, कोयला, खदान
रामदास आठवले	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
साध्वी निरंजन ज्योति	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण, ग्रामीण विकास
संजीव कुमार बाल्यान	मत्स्य, पशुपालन, डेयरी
नित्यानंद राय	गृह
पंकज चौधरी	वित्त
अनुप्रिया पटेल	व्यापार एवं उद्योग
एसपी सिंह बघेल	कानून एवं न्याय
राजीव चंद्रशेखर	कौशल विकास, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना तकनीक
शोभा करंदलजे	कृषि तथा किसान कल्याण
भानुप्रताप सिंह वर्मा	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
दर्शन विक्रम	कपड़ा, रेल
वी. मुरलीधरन	विदेश, संसदीय कार्य
मीनाक्षी लेखी	विदेश, संस्कृति
सोमप्रकाश	व्यापार एवं उद्योग
रेणुका सिंह सरूता	आदिवासी मामले
रामेश्वर तेली	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, श्रम एवं रोजगार
कैलाश चौधरी	कृषि, किसान कल्याण
अन्नपूर्णा देवी	शिक्षा
ए. नारायणस्वामी	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
कौशल किशोर	शहरी विकास, आवास
अजय भट्ट	रक्षा, पर्यटन
बीएल वर्मा	पूर्वोत्तर विकास, सहकारिता
अजय कुमार	विदेश
देवूसिंह चौहान	संचार
भगवंत खूबा	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, केमिकल एवं उर्वरक
कपिल मोरेश्वर पाटिल	पंचायती राज
प्रतिमा भौमिक	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
सुभास सरकार	शिक्षा
भागवत कृष्णा राव	वित्त
राजकुमार रंजन सिंह	विदेश एवं शिक्षा
भारतीय प्रवीण पवार	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
बिश्वेश्वर टुडू	आदिवासी मामले और जलशक्ति
शातंनु ठाकुर	पोत, बंदरगाह एवं जलमार्ग
मंजू पारा महेंद्रभाई	महिला एवं बाल विकास तथा आयुष
जान बारला	अल्पसंख्यक मामले
एल. मुरुगन	मत्स्य, पशुपालन और डेयरी, सूचना एवं प्रसारण
निशिथ प्रमाणिक	गृह, युवा एवं खेल

मिशन यूपी पर नजर, दलित-पिछड़े सिर आंखों पर

जितेंद्र शर्मा • लखनऊ



महराजगंज के सांसद पंकज चौधरी और लोकसभा सदस्य कौशल किशोर • जागरण आर्काइव

पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से 15 मंत्री

सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का दबदबा अब नजर आया है। मोदी कैबिनेट से सांसद संतोष गंगवार के इस्तीफे के बाद भी अब कुल 15 मंत्री यूपी से हो गए हैं। इनमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, डा. महेंद्र नाथ पांडेय, जनरल वीके सिंह, संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति और हरदीप पुरी (उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य) पहले से हैं। इस तरह अब छह सवर्ण, छह पिछड़ा वर्ग और तीन अनुसूचित जाति से हो गए हैं।

देश की राजनीति का गेट-वे उत्तर प्रदेश कहा जाता है, लेकिन भाजपा के रणनीतिकारों ने फिलहाल मिशन-यूपी के लिए दिल्ली में तोरण-द्वार सजाया है। सबका साथ, सबका विकास की नीति को विधानसभा चुनाव-2022 की रणनीति का हिस्सा बनाते हुए मोदी मंत्रिमंडल में सात नए चेहरे शामिल किए गए हैं। इन नए राज्य मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 15 मंत्रियों की भागीदारी से केंद्र सरकार में यूपी का दबदबा पहली बार इतना बढ़ा है।

पिछड़े और दलितों को सिर-आंखों पर बिठाने के साथ क्षेत्रीय संतुलन पर भी सधी नजर रही है। मोदी सरकार-2 के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के साथ ही चर्चा शुरू हो गई थी कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो दी जा सकती है। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के हिसाब से ही कई नाम दावेदारी में चलने लगे थे। बुधवार को जब नए मंत्रियों की शपथ का सिलसिला शुरू हुआ तो संदेश मिल गया कि भगवा खेमे के रणनीतिकारों ने दिल्ली के दरबार में यूपी चुनाव को देखते हुए भी बिसात बिछाई है। मोहरों का चयन पूरी तरह नाप-तौल कर किया गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही भाजपा के पाले में आ खड़े हुए यूपी में सर्वाधिक आबादी वाले पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग को तीन नए मंत्री बनाकर साथ और विकास का संदेश दिया है। यह दांव पिछड़ों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रही समाजवादी पार्टी के दांव को बेअसर करने वाला माना जा रहा है।

इसी तरह बसपा के माने जाते रहे लगभग 21-22 फीसद अनुसूचित जाति के वोट में भी भाजपा अच्छी सेंध लगा चुकी है। इस वर्ग पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए दलित वर्ग से भी तीन मंत्री शामिल किए गए हैं। टीम मोदी में यूपी कोटे के मंत्रियों में पांच सवर्णों की भागीदारी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, डा. महेंद्र नाथ पांडेय, जनरल वीके सिंह, स्मृति ईरानी और हरदीप पुरी की पहले से है। अब एक और ब्राह्मण को शामिल कर यूपी में विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे ब्राह्मणों से भेदभाव के मुद्दे को भी कुंद करने का प्रयास किया गया है। जातीय संतुलन के साथ क्षेत्रीय संतुलन का भी पूरा ध्यान इस विस्तार में रखा गया है। पिछड़ा वर्ग में देखें तो भाजपा के सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल मीरजापुर से सांसद हैं। मोदी सरकार-1 में स्वास्थ्य राज्यमंत्री रहीं अनुप्रिया का पूर्वांचल के कुछ जिलों में कुर्मी समाज पर अच्छा प्रभाव है। मोदी के मंत्रिमंडल में उनकी वापसी के साथ ही पूर्वांचल के ही महराजगंज से पंकज चौधरी को पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। वह भी कुर्मी नेता हैं।

छठवीं बार सांसद चुने गए हैं तो क्षेत्र में प्रभाव और पकड़ लाजिमी है। इसी तरह संघ की पृष्ठभूमि वाले राज्यसभा सदस्य बीएल वर्मा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं से आते हैं। लोधी-राजपूत समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। अलीगढ़, एटा, फर्रुखाबाद सहित कुछ जिलों इस समाज का अच्छा-खासा वोट है। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विपक्ष ने कृषि कानून विरोधी आंदोलन से गर्माने की कोशिश की, वहां का प्रतिनिधित्व बदायूं की तरह आगरा के सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल को दलित कोटे से मंत्री बनाकर बढ़ाया है। सपा और बसपा में रह चुके बघेल भाजपा में आने के बाद योगी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। पाल-बघेल समाज के प्रभावशाली नेताओं में शामिल हैं। इसी तरह अवध क्षेत्र के लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह पहले ही केंद्रीय कैबिनेट में हैं। अब इसी क्षेत्र की मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर को दलित कोटे से राज्यमंत्री बनाया है। यह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वहीं, खीरी सांसद अजय मिश्रा को मंत्री बनाकर ब्राह्मण को भी साथ और विकास का संदेश दिया गया है। विस्तार में जिस तरह उत्तर प्रदेश को तरजीह मिली है उससे यह साफ हो गया है कि भाजपा ने राजनीतिक रूप से सबसे अहम इस राज्य में अपनी तैयारियां निर्णायक दौर में पहुंचा दी हैं।

ये बने नए कैबिनेट मंत्री

नारायण राणे



उम्र : 69
शिक्षा : एसएससी

कोंकण क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले नारायण राणे ने शिवसेना के शाखा प्रमुख के तौर पर राजनीति की शुरुआत की थी। फिलहाल महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य हैं। छह बार एमएलए और एक बार एमएलसी भी रह चुके हैं। प्रदेश में जब पहली बार शिवसेना की सरकार बनी थी तब इन्हें मनोहर जोशी की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। इनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन पार्टी सत्ता में नहीं लौट सकी। राणे को एमएसएमई मंत्रालय मिला है।

सर्बानंद सोनोवाल



उम्र : 59
शिक्षा : एलएलबी

डिब्रूगढ़ से ताल्लुक रखने वाले सोनोवाल ने छात्र नेता के तौर पर अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। भाजपा का दामन थामने से पहले वह असम गण परिषद से जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पांच साल पहले प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखी थी, तब उन्होंने सोनोवाल को इस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए चुना था। हिमंता बिस्व सरमा को कुर्सी सौंपने से पार्टी में उनका कद और बढ़ा है। सोनोवाल आयुष मंत्री बनाए गए हैं।

डॉक्टर वीरेंद्र कुमार



उम्र : 67
शिक्षा : पीएचडी

डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सातवीं बार संसद पहुंचे हैं। पूर्व में महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक राज्यमंत्री रह चुके हैं। लगभग चार दशकों से सार्वजनिक जीवन में हैं। वीरेंद्र कुमार ने बाल श्रम में पीएचडी की है। वह बचपन से ही राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी भाग लिया। वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया



उम्र : 50
शिक्षा : एमबीए

पिछले साल ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। इसके बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। फिलहाल वह प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। ग्वालियर के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सिंधिया पांचवीं बार संसद पहुंचे हैं। उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे। वह मनमोहन सिंह सरकार में ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे। वह अपने पिता की तरह नागर विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे।

आरसीपी सिंह



उम्र : 63
शिक्षा : एमए

यूपी कैडर के आइएएस रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह (आरसीपी सिंह) को जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बाद नंबर दो का नेता माना जाता है। पिछले दिनों नीतीश ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा तो उत्तराधिकारी के तौर पर आरसीपी उनकी पसंद बने। वह बिहार से राज्यसभा सदस्य हैं। दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। आरसीपी 1996 में केंद्रीय मंत्री बेनीप्रसाद वर्मा के निजी सचिव हुआ करते थे। नीतीश जब रेलमंत्री बने तो आरसीपी को उन्होंने विशेष सचिव बनाया। वह अब इस्पात मंत्री होंगे।

अश्विनी वैष्णव



उम्र : 50
शिक्षा : एमटेक

मूलरूप से राजस्थान के मारवाड़ से ताल्लुक रखते हैं और ओडिशा से राज्यसभा सदस्य हैं। 1994 बैच के पूर्व आइएएस अधिकारी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पीपीपी मोड को लाने का वैष्णव को ही दिया जाता है। जनरल इलेक्ट्रिकल्स और सीमेंस जैसी कंपनियों में बड़े पदों पर रहे हैं। आइआइटी कानपुर से एमटेक करने के साथ ही वार्टन स्कूल से एमबीए किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में उप सचिव भी रहे। वैष्णव रेल के साथ आइटी मंत्रालय संभालेंगे।

पशुपति कुमार पारस



उम्र : 68
शिक्षा : बीए और बीएड

पारस बिहार के हाजीपुर से लोकसभा सदस्य हैं। पूर्व में प्रदेश सरकार में मंत्री रहने के साथ ही सात बार एमएलए और एक बार एमएलसी रह चुके हैं। लोकजनशक्ति (पार्टी पारस गुट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पारस के करियर का ज्यादातर समय उनके दिवंगत भाई और केंद्रीय मंत्री रहे राम विलास पासवान के साये में बीता है। पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।

भूपेंद्र यादव



उम्र : 52
शिक्षा : एलएलबी

मूलरूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन पले-बढ़े है राजस्थान में। अजमेर में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। विद्यार्थी परिषद से लेकर राजस्थान भाजपा की राजनीति में उनका नाम गहरी पकड़ रखने वाले नेताओं में माना जाता है। राजस्थान से दूसरी बार राज्यसभा सदस्य बने हैं। लगभग 25 संसदीय समितियों में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के साथ विभिन्न आयोग में सरकार की तरफ से पक्ष रखते हैं। उन्हें पर्यावरण के साथ वन एवं श्रम मंत्रालय दिया गया है।

किरण रिजिजू



उम्र : 49
शिक्षा : बीए, एलएलबी

लोकसभा में अरुणाचल वेस्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरी बार संसद पहुंचे हैं। वर्तमान में खेल राज्यमंत्री का कामकाज देख रहे थे। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में इनका जन्म हुआ है। उन्होंने 2004 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन 2009 में सफलता हासिल नहीं कर पाए थे। 2014 में फिर जीत हासिल की और मोदी मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री बनाए गए। रिजिजू को ताजा विस्तार में कानून मंत्री बनाया गया है।

पुरुषोत्तम रूपाला



उम्र : 66
शिक्षा : बीएससी, बीएड

गुजरात से राज्यसभा सदस्य हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रभावशाली कडवा पाटीदार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में कृषि एवं पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनकी पदोन्नति को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने 1977 से 1983 तक हमारपुर हाईस्कूल में बतौर प्रिंसिपल काम किया। वह मंत्रिमंडल विस्तार में मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री बनाए गए हैं।

हरदीप पुरी



उम्र : 69
शिक्षा : एमए

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें आवास और शहरी विकास के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोरोना महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए चलाए गए वंदे भारत मिशन की काफी सराहना हुई। पुरी वर्ष 1974 में भारतीय विदेश सेवा के लिए चुने गए थे। उन्हें शहरी विकास और आवासन के साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी गई है, जो उनके बढ़ते कद का प्रतीक है।

आरके सिंह



उम्र : 69
शिक्षा : बीए, एलएलबी

बिहार की आरा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। पूर्व आइएएस अधिकारी सिंह ने रथ यात्रा करते हुए बिहार पहुंचे भाजपा के तब के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था। वह उस समय समस्तीपुर के डीएम थे। 2014 में पहली बार लोकसभा का चुनाव आरा सीट से लड़े और जीत हासिल की। इस सफलता के बाद वह केंद्र में राज्यमंत्री बनाए गए। उन्हें अब ऊर्जा मंत्रालय की पूरी तरह जिम्मेदारी दी गई है।

अनुराग ठाकुर



उम्र : 47
शिक्षा : बीए

हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथी बार संसद पहुंचे हैं। ठाकुर मई 2016 से फरवरी 2017 के बीच बीसीसीआई अध्यक्ष रहे। इससे पहले वह बोर्ड के सचिव और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) के अध्यक्ष भी थे। वे बुधवार को कैबिनेट फेरबदल से पहले निर्मला सीतारमण के तहत राज्य वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। ताजा फेरबदल में उन्हें सूचना एवं प्रसारण के साथ खेल और युवा मामलों की जिम्मेदारी दी गई है।

मनसुख मंडाविया



उम्र : 49
शिक्षा : एमए

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से आने वाले मंडाविया राज्यसभा सदस्य हैं। विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। गुजरात में सबसे कम उम्र का विधायक चुने जाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। उन्हें पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में पांच जुलाई, 2016 को सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे।

जी किशन रेड्डी



उम्र : 57
शिक्षा : डिप्लोमा इन टूल डिजाइनिंग

आंध्र प्रदेश की सिकंदराबाद लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। रेड्डी ने युवा नेता के तौर पर राजनीति की शुरुआत की थी। वर्ष 2002 से 2005 के बीच भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वर्ष 2004 में हिमायतनगर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए। वर्ष 2009 में उन्हें आंध्र प्रदेश विधानसभा में भाजपा की ओर से नेता सदन बनाया गया। वह अब संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का कामकाज देखेंगे।

भाजपा में शिवसेना का जवाब हैं राणे

ओमप्रकाश तिवारी • मुंबई



राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद की शपथ लेते नारायण राणे • एएनआइ

मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए मंत्रियों में बुधवार को सबसे पहले पुकारा जानेवाला नाम महाराष्ट्र के नारायण राणे का था। राणे को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाकर भाजपा ने अपने खेमे में एक तेजतर्रार मराठा नेता को तो जोड़ा ही है, शिवसेना के गढ़ समझे जानेवाले कोंकण में उसका जवाब भी तलाश लिया है।

नारायण राणे मूलतः शिवसैनिक ही रहे हैं। शिवसेना संस्थापक बालासाहब ठाकरे के भरोसेमंद रहे नारायण राणे को शिवसेना-भाजपा गठबंधन की पहली सरकार में मनोहर जोशी के बाद सिर्फ छह माह के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। लेकिन, अपने उसी छोटे से कार्यकाल में राणे ने अपनी प्रशासनिक क्षमता की गहरी छाप छोड़ी थी। लेकिन दुर्भाग्य से राणे को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। यहां तक कि शिवसेना में उनकी उद्धव ठाकरे से पटरी भी नहीं खाई और उन्हें शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में जाना पड़ा। तब की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रभाराव उन्हें कांग्रेस में इस आश्वासन के साथ लाई थीं कि उन्हें जल्दी ही मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन, कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हुआ।

14 जून को पशुपति कुमार पारस को लोजपा संसदीय दल का नेता नियुक्त किए जाने संबंधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आदेश को चिराग पासवान ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 8 जुलाई, 2021

मोदी के जंबो मंत्रिमंडल में घटी हरियाणा की हिस्सेदारी

अनुराग अग्रवाल • चंडीगढ़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारी भरकम मंत्रिमंडल में उम्मीदों के विपरीत हरियाणा की हिस्सेदारी कम हो गई है। संभावना जताई जा रही थी कि मंत्रिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल को शामिल किया जा सकता है। शाम होते-होते बीरेंद्र सिंह की लाबिंग धरी रह गई और सुनीता दुग्गल की उम्मीद टूटकर बिखर गई। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का मंत्री पद भी छिन गया है।

रतनलाल कटारिया अंबाला से सांसद हैं और दलित कोटे में मोदी कैबिनेट में हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बताया जाता है कि कटारिया की परफारमेंस संतोषजनक नहीं थी। दो साल के कार्यकाल में कटारिया खास नतीजे नहीं दे पाए। पार्टी के प्रति उनकी वफादारी को देखते हुए भविष्य में उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

हरियाणा भाजपा की सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। अन्नपूर्णा झारखंड के कोडरमा से सांसद हैं और बिहार व झारखंड से चार बार विधायक तथा कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। अन्नपूर्णा के केंद्रीय मंत्री बनने से प्रदेश में निश्चित रूप से उनका राजनीतिक रुतबा बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम मूल के भाजपा नेता राजस्थान से राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव को मोदी कैबिनेट में भागीदारी मिली है।

बीरेंद्र सिंह ने दिया था मनोहर लाल को रात्रिभोज


बृजेंद्र सिंह

इसी तरह बृजेंद्र सिंह के पास जब शाम तक कोई फोन नहीं आया तो उनके समर्थकों की बेचैनी बढ़ गई। अपने बेटे बृजेंद्र के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने तगड़ी लाबिंग की हुई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को रात्रिभोज भी दिया। बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में रहते हुए उत्तर प्रदेश का प्रभार देख चुके हैं। ऐसे में उन्हें लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को आधार बनाते हुए बृजेंद्र सिंह को मोदी कैबिनेट में एंट्री मिल सकती है, मगर ऐसा नहीं हो पाया है।

कटारिया के इस्तीफा देते ही बंधी थी दुग्गल को आस

मोदी कैबिनेट में इस बार शामिल होने की हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल की हसरत पूरी नहीं हो पाई है। रतनलाल कटारिया के मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे दलित कोटे से सुनीता दुग्गल को मंत्री बनाया जा सकता है। इसी सिलसिले में वह पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंची हुई थी, लेकिन सुनीता दुग्गल की उम्मीदों पर पानी फिर गया।

राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर की बढ़ेगी अहमियत


कृष्णपाल गुर्जर


राव इंद्रजीत

मोदी कैबिनेट में हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर का कद नहीं बढ़ गया, जबकि दोनों मंत्रियों का रुतबा बरकरार रहा। प्रदेश में अब दो ही मंत्री रह जाने की वजह से उनका राजनीतिक वजन बढ़ेगा। उम्मीद की जा रही थी कि राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर में से किसी एक को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए राव इंद्रजीत अधिक लाबिंग करते नजर आ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एनसीआर से आने वाले इन दोनों मंत्रियों का मौजूदा रुतबा ही बरकरार रखा। राव इंद्रजीत गुरुग्राम से और कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से सांसद हैं। दोनों जनता के बीच लोकप्रिय हैं। दोनों का अपना बड़ा राजनीतिक कद है।

खास बातें

- कयास के विपरीत नहीं बढ़ा मंत्रिमंडल में हरियाणा का रुतबा
- मोदी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे रतनलाल कटारिया की मंत्री पद से छुट्टी
- बीरेंद्र सिंह की बेटे बृजेंद्र के लिए सेट की गई फिल्डिंग नहीं आई काम
- राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर का रुतबा रहा बरकरार
- सांसद सुनीता दुग्गल की शपथ लेने की तैयारी धरी की धरी रह गई
- हरियाणा भाजपा की सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी को मिला मंत्रालय
- गुरुग्राम मूल के भाजपा नेता भूपेंद्र यादव की मोदी कैबिनेट में भागीदारी

ज्योतिरादित्य को मिला इनाम

- मोदी कैबिनेट में मप्र से मंत्रियों की संख्या पांच से बढ़कर हुई छह
- सिंधिया के नाम की काफी समय से हो रही थी चर्चा

नईदुनिया, भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया और डा. वीरेंद्र कुमार के शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ गई है। पहले प्रदेश से पांच मंत्री थे, अब छह हो गए हैं। सिंधिया का नाम काफी समय से केंद्रीय मंत्री के तौर पर तय माना जा रहा था, लेकिन डा. वीरेंद्र कुमार का नाम शामिल कर जातिगत संतुलन साधा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाने का इनाम मिला है। वहीं, थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त करने के बाद रिक्त हुए अनुसूचित जाति वर्ग के चेहरे की भरपाई के तौर पर डा. वीरेंद्र कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के समय से ही सिंधिया को राज्यसभा में भेजने और फिर केंद्रीय मंत्री बनाने की चर्चा रही है। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद बुधवार को मोदी कैबिनेट में शामिल होने के साथ ही दोनों चर्चाएं सही साबित हुईं। सिंधिया के कारण ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना संभव हुआ था। इसी कारण सिंधिया और उनके समर्थकों का महत्व प्रदेश की सत्ता और संगठन में हमेशा बरकरार रखा गया। अब सिंधिया के केंद्र में मंत्री बनाने से यह संदेश भी दिया गया है कि अन्य दलों से भाजपा में आने वालों को पार्टी के पुराने नेताओं के समान ही अधिकार और सम्मान दिया जा रहा है। प्रदेश में भी राजनीतिक लिहाज से सिंधिया का कद बढ़ा है।

अभी तक थावरचंद गहलोत देश में पार्टी की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग का चेहरा थे। उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है।

राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए गहलोत हुए तैयार

माकन से मुलाकात में मंत्रियों के साथ संसदीय सचिव बनाने पर भी हुई चर्चा

15 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार

जागरण संवाददाता, जयपुर


अशोक गहलोत फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

आखिरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां करने को लेकर सहमत हो गए हैं। हालांकि, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की मांग के हिसाब से पांच से छह मंत्री उनके कोटे से बनाने को लेकर सीएम तैयार नहीं हैं। सीएम चाहते हैं कि पायलट खेमे के दो से तीन विधायकों को ही मंत्री बनाने के साथ ही कुछ नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से उपकृत किया जाए।

गौरतलब है कि पायलट और गहलोत दो खेमों में राजस्थान कांग्रेस बंटी हुई थी। ऐसे में दोनों खेमों को संतुष्ट कर कलह को खत्म करने को पार्टी आलाकमान प्रयासरत था। इसी कड़ी में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर सहमति बनाने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने बुधवार को दूसरे दिन सीएम से मुलाकात की। इससे पहले मंगलवार को भी माकन और गहलोत के बीच दो घंटे तक बैठक हुई थी। दो दिन के मंथन में राजनीतिक गतिरोध खत्म करने पर सहमति बनी है। गहलोत के विश्वस्त एक मंत्री का कहना है कि 15 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राजनीतिक नियुक्तियों का काम इसी महीने शुरू हो जाएगा। आधा दर्जन संसदीय सचिव बनाने को लेकर भी गहलोत की माकन से बात हुई है । बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों को संसदीय सचिव बनाने पर सहमति बनी है । मीडिया से बात करते हुए माकन ने कहा कि सरकार में होने वाले फैसलों पर काम हो रहा है। शीघ्र ही सबके सामने आ जाएगा ।

सोनिया गांधी से बात करेंगे गहलोत: जानकारी के अनुसार माकन से मुलाकात में गहलोत ने कहा कि वह मंत्रिमंडल विस्तार व राजनीतिक नियुक्तियों से पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात करेंगे । गहलोत सोनिया के समक्ष बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों के साथ ही 13 निर्दलियों को सरकार में शामिल करने पर अपना पक्ष रखेंगे। निर्दलियों को सरकार में शामिल करने को लेकर माकन और पायलट सहमत नहीं हैं।

पायलट समर्थक विधायक ने दिखाई तेवर : उधर, पायलट समर्थक विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने बुधवार को मीडिया से कहा कि हम अपने हक की आवाज उठाने के लिए दिल्ली और मानेसर (हरियाणा) गए थे। अगर दिल्ली और मानेसर जाना राजनीतिक आत्महत्या है तो वह हम कर चुके हैं । उन्होंने हम आलाकमान से अपनी बात कहने गए थे । अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर दिल्ली जाने को तैयार हैं ।

माकन का घेराव करने पहुंचे भाजपा सांसद : माकन बुधवार को एक होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे कि अचानक भाजपा के राज्यसभा सदस्य डा. किरोड़ी लाल मीणा आदिवासी महिलाओं और बच्चों को लेकर उनके पास पहुंच गए । माकन का घेराव करने के लिए पहुंचे मीणा को बाद में पुलिस अधिकारियों व कांग्रेस नेताओं ने समझाया तो वे ज्ञापन देने के लिए तैयार हो गए । उन्होंने माकन से कहा कि आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं । इनके लिए बनाई गई योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा । आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार इस मामले को कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

गुजरात में अब जनजाति वर्ग ने की मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : पाटीदार व ओबीसी समुदाय के बाद अब जनजाति वर्ग के नेताओं ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर दावा किया है। बीटीपी अध्यक्ष व विधायक छोटू वसावा ने कहा कि 16 फीसद आबादी वाले जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि को राज्य का अगला सीएम होना चाहिए।

भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) की ओर से गुजरात महाआदिवासी एकता मंच के बैनर तले मंगलवार को आयोजित एक सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक छोटू वसावा के साथ कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रभा तावियाड, विधायक अनिल जोशीयारा व विधायक अनंत पटेल भी शामिल हुए।

छोटू वसावा ने कहा कि प्रदेश में जनजाति समुदाय के करीब एक करोड़ लोग रहते हैं, इसलिए अगला मुख्यमंत्री इसी समुदाय से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवड़िया में स्टैच्यू आफ यूनिटी बनाने के बावजूद आसपास रहने वाले जनजाति समुदाय को उसका लाभ नहीं मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अनिल जोशीयारा ने भी जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि को सीएम पद दिए जाने की मांग की। विधायक अनंत पटेल की भी कमोबेश यही राय रही।

गौरतलब है कि मंगलवार को ही गुजरात के दिग्गज जनजाति नेता एवं पूर्व मंत्री मंगूभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वह गुजरात के आदिवासी समुदाय से राज्यपाल बनने वाले पहले नेता हैं। हालांकि, कांग्रेस नेता अमर सिंह चौधरी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले पाटीदार व ओबीसी समुदाय भी सम्मेलनों के जरिये मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी जता चुके हैं।

हर्षवर्धन को मिल सकती है संगठन में जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- संभव है कि दिल्ली भाजपा की कमान उन्हें सौंपी जाए


डा. हर्षवर्धन जागरण आर्काइव

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन के इस्तीफे से उनके समर्थक सकते में हैं। उन्हें इसका अंदेशा भी नहीं था कि उनके नेता का मंत्री पद चला जाएगा। अब उनकी नई भूमिका को लेकर भी कयास लगने लगे हैं। चर्चा है कि उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। संभव है कि आने वाले दिनों में दिल्ली भाजपा की कमान उन्हें सौंपी जाए।

डा. हर्षवर्धन को नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। बाद में उनकी जगह जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें इसकी जगह विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया था। इस तरह से पहले कार्यकाल में पूरे पांच साल वह मंत्री बने रहे। चांदनी चौक से दूसरी बार सांसद चुने जाने के बाद उन्हें एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के समय इनके काम की सराहना भी हुई। वहीं, दूसरी लहर के समय इन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। चर्चा है कि इसी वजह से इन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है।

वहीं, कई लोगों का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी देने के उद्देश्य से कई मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया है। आने वाले दिनों में संगठन में फेरबदल संभव है। डा. हर्षवर्धन को भी जल्द ही नई भूमिका दी जाएगी। पहले भी वह दिल्ली की कमान संभाल चुके हैं। वर्ष 2013 में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया था और पार्टी को 31 सीटों पर जीत मिली थी। उसके बाद हुए दो विधानसभा चुनावों पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। दिल्ली में वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ी थी। उससे पहले भी वह दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसे ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि पार्टी उनका उपयोग संगठन को मजबूत करने में करेगी।

हर्षवर्धन के बहाने कांग्रेस ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा : प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि कोरोना में लोगों की जान बचाने में नाकाम रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के केजरीवाल अपना इस्तीफा कब देंगे? प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोरोना काल में सैकड़ों मौतों के जिम्मेदार हर्षवर्धन तथा केजरीवाल दोनों का इस्तीफा मांग रही थी।

पारस के मंत्री बनते ही भाजपा के बंधन से चिराग मुक्त

दीनानाथ साहनी, पटना : लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) में टूट और आंतरिक कलह पर अब तक खामोश भाजपा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति कुमार पारस को शामिल कर चिराग पासवान को एक तरह से राजग से भी मुक्त कर दिया है। इसके बाद भाजपा के मोह-माया में पड़े चिराग के लिए भी असमंजस की स्थिति खत्म हो गई, लेकिन उनके लिए चुनौतियां भी बढ़ गईं। गठबंधन की राजनीति के मौजूदा दौर में फिलहाल चिराग अकेले पड़ गए हैं पर उन्हें एक अवसर भी मिला है खुद को साबित करने और खुलकर राजनीति करने का। इस बीच उन्हें पार्टी सिंबल को लेकर भी चुनाव आयोग से लेकर न्यायालय तक में लंबी लड़ाई के लिए खुद को तैयार रखना होगा। इधर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल पशुपति पारस को भी अब भाजपा के हिसाब से वैसे ही चलना होगा जैसे अब तक चिराग पासवान चलते रहे।

हाल-फिलहाल बिहार में कोई चुनाव नहीं होना है। ऐसे में चिराग आने वाले चुनावों के लिए लोजपा को कितना संगठित और मजबूत कर पाते हैं, यह उनके राजनीतिक कौशल पर निर्भर करेगा क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि पारस के केंद्र में मंत्री बनने से रामविलास पासवान के समर्थकों (पासवान वोट) पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। पार्टी और परिवार में टूट से सबसे बड़े सियासी संकट का सामना कर रहे चिराग पर यह निर्भर करेगा कि ताकतवर सत्तारूढ़ दलों की सियासी दांव-पेच की काट कैसे निकाल पाते हैं।

ममता सरकार ने पांच वर्ष में डेढ़ करोड़ नौकरियों का किया वादा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- सूबे में तीसरी बार सरकार बनने के बाद पेश किया गया पहला बजट


ममता बनर्जी फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता में आई ममता बनर्जी की सरकार ने बुधवार को अपना पहला बजट पेश किया। इसमें महंगाई की मार झेल रही जनता को राज्य सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए यात्री परिवहन वाहनों पर दिसंबर तक रोड टैक्स माफ करने की घोषणा के साथ रोजगार को लेकर बड़ा वादा किया। पांच वर्ष में डेढ़ करोड़ लोगों को नौकरियां देने की बात कही।

उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल 3.08 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने अगले पांच सालों में डेढ़ करोड़ नौकरियों का वादा किया। सात करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की भी घोषणा की।

वित्त मंत्री अमित मित्रा के अस्वस्थ होने के कारण उद्योग मंत्री ने बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान पार्थ ने देश में ईंधन की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना भी की।

लक्ष्मी भंडार योजना भी जल्द शुरू करेगी ममता सरकार

विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार बहुत जल्द लक्ष्मी भंडार योजना भी शुरू करेगी। इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति महीने 500 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे। ममता ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका वादा किया था।

सौमित्र ने भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष का पद छोड़ा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल भाजपा में एक बार फिर असंतोष उजागर हुआ है। बांकुड़ा के विष्णुपुर से सांसद सौमित्र खां ने बुधवार को अचानक भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, उनका कहना है कि अपने दायित्व में असफल रहने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है।

इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष तथा नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व को गलत जानकारी दे रहे हैं। इससे राज्य में भाजपा का भला नहीं होगा। उन्होंने साथ ही कहा है कि वह भाजपा में हैं और रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता बताया है। हालांकि, ऐसी खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिए जाने को लेकर वह नाराज हैं और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। दरअसल, बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल के हुए विस्तार में बंगाल से चार सांसदों को शामिल किया गया है। वहीं, सौमित्र खां बुधवार दोपहर तक भाजपा हाईकमान से फोन आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

मानवाधिकार आयोग की टीम ने बंगाल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की टीम ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

जानकारी के मुताबिक, आयोग की टीम में शामिल सदस्यों ने अलग-अलग हिस्से में बंटकर बुधवार को मालदा व नदिया जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। टीम के सदस्यों ने शिकायतों की पड़ताल के लिए विभिन्न गांवों में जाकर स्थिति का आकलन किया और पीड़ित परिवारों के साथ बातचीत की।

पेट्रोल-डीजल की दर के खिलाफ 38 किमी साइकिल चला विस पहुंचे बंगाल के श्रम मंत्री

राज्य ब्यूरो, कोलकाता


बंगाल के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना साइकिल चलाकर कोलकाता स्थित विस पहुंचे। एएनआइ

पेट्रोल-डीजल की दर के खिलाफ बुधवार को बंगाल के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने साइकिल से 38 किलोमीटर का फासला तय किया।

अनोखे अंदाज में किए गए उनके इस विरोध-प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बुधवार सुबह आठ बजे मन्ना हुगली के सिंगुर रतनपुर स्थित अपने निवास स्थल से साइकिल लेकर विधानसभा के लिए रवाना हुए। साइकिल रैली में आगे मंत्री व पीछे उनके सहयोगी थे। मन्ना ने कहा कि पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में की जा रही लगातार बढ़ोतरी से लोगों के जीवन पर काफी असर पड़ा है।

नियुक्तियों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट में उठा सवाल

- सीआइसी-एसआइसी में नियुक्तियों में देरी
- 2019 के आदेश पर अमल को लेकर केंद्र व राज्यों से रिपोर्ट तलब


सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और राज्यों को सूचना के अधिकार कानून (आरटीआइ) के तहत एसआइसी की राज्य समितियों और सीआइसी में सूचना आयुक्त के पदों पर समय सीमा के तहत नियुक्तियां करने के 2019 के उसके आदेश के अनुपालन पर स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

जस्टिस एस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा, केंद्र और राज्यों को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) व राज्य सूचना आयोग (एसआइसी) में रिक्तियों की जानकारियां चार सप्ताह के भीतर देनी होंगी। साथ ही इन पदों पर नियुक्तियों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देनी होगी।

कोर्ट आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में कानून के तहत सीआइसी और एसआइसी में नियुक्तियों पर 2019 के आदेश को लागू करने का अनुरोध किया गया है।

भारद्वाज ने सरकारी प्राधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया। कोर्ट ने सरकार को एक निर्धारित समयसीमा के भीतर और पारदर्शी तरीके से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने भारद्वाज की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण को भी मामले में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। भूषण ने कहा,विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने चयन समिति की बैठक के दौरान सीआइसी और एसआइसी के लिए चयन मानदंड प्रदान नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया था।

'चयन मानदंड व आवेदकों के नाम रिकार्ड पर होने चाहिए'

भूषण ने यह भी कहा कि केंद्र को सीआइसी और एसआइसी के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के नामों को छांटने के लिए मानदंड और मौजूदा रिक्तियों और पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के नाम जैसी जानकारी रिकार्ड करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक और बंगाल जैसे राज्यों में एसआइसी में रिक्तियां हैं और इस अदालत के निर्देशों को पूरी तरह से लागू करने की जरूरत है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीआइ के तहत लगभग 75,000 और 36,000 मामले क्रमशः महाराष्ट्र एसआइसी और सीआइसी में लंबित हैं। इस तरह से मामले लटकाने की प्रवृत्ति आरटीआइ कानून को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास है। भूषण ने चयन मानदंड रिकार्ड में लाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सीआइसी के पद पर एक 'फर्जी पत्रकार' की नियुक्ति की गई। इसके अलावा ऐसी नियुक्तियों के लिए केवल नौकरशाहों के नाम पर विचार किया जा रहा है।

इस पर असिस्टेंट सालिसिटर जनरल (एएसजी) ने भूषण द्वारा इस्तेमाल किए गए 'फर्जी पत्रकार' शब्द का विरोध किया और उनसे केंद्र से प्रतिक्रिया मांगने के लिए इस आशय का एक हलफनामा दाखिल करने को कहा।

उल्लेखनीय है शीर्ष अदालत ने 2019 में कहा था कि सीआइसी और एसआइसी के लिए सूचना अधिकारियों के चयन में सिर्फ नौकरशाहों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों को शामिल किया जाना चाहिए।

2016 में कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण नहीं करने के फैसले को रद कर दिया था

प्रथम पृष्ठ से आगे

2016 में शीर्ष अदालत ने उक्त जमीन का अधिग्रहण नहीं करने के फैसले को रद कर दिया था और हुडा के पक्ष में जमीन का लाइसेंस हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मार्च, 2018 में इस मामले की सीबीआइ से जांच कराने की बात कही थी, लेकिन बाद में वो इससे पीछे हट गए। बाद में राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त जज से मामले की जांच का कराने आदेश दिया था। 2017 में सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी राजन गुप्ता ने इस मामले की जांच की थी और इस मामले के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए इसे व्यवस्थागत खामी बताया था।

बिजली बनेगी पंजाब विधानसभा चुनाव में मुद्दा

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बिजली मुद्दा बनेगी। इस साल कटों से आम जनता व उद्योग जगत परेशान है और इस कारण कांग्रेस सरकार के प्रति नाराजगी सामने आ रही है। कटों के साथ ही सरकार बिजली समझौतों के विषय पर भी निशाने पर है। विपक्ष ही नहीं, कांग्रेस के अपने नेता ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।

धान के सीजन में बिजली की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाने, मानसून में देरी और प्राइवेट थर्मल प्लांटों से हुए समझौते को मौजूदा बिजली संकट का कारण माना जा रहा है। लेकिन राजनीतिक मुद्दा तीन प्राइवेट थर्मल प्लांटों के साथ शिअद-भाजपा सरकार के समय हुए समझौतों को लेकर कांग्रेस के दावे बन रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में आने पर इन समझौतों को रद करने की बात कह रही थी। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा था कि समझौते के कारण पावरकाम को जो बिजली 2.86 रुपये प्रति यूनिट में मिलनी चाहिए वह छह से सात रुपये प्रति यूनिट मिल रही है। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इन समझौतों को रद किया जाएगा, लेकिन साढ़े चार साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि समझौतों को इस तरह रद नहीं किया जा सकता। इससे भविष्य में बड़े निवेशक सरकार पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने मार्च 2020 के बजट सत्र में श्वेत पत्र लाने की बात कही थी कि लेकिन 15 माह से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद सरकार ऐसा नहीं कर पाई। अब अकाली दल, भाजपा और अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ-साथ अपनी ही पार्टी के नवजोत सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा जैसे बड़े नेता सरकार व मुख्यमंत्री को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस ने गरीबों को दो सौ यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे पर अमल करने के लिए मुख्यमंत्री को कहा है। उधर, आम आदमी पार्टी तीन सौ यूनिट मुफ्त देने का एलान कर चुकी है।

सोनिया के बाद पीके से मिले कैप्टन, मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल के संकेत

कैलाश नाथ, चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पंजाब मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। मंगलवार को सोनिया से मुलाकात के बाद बुधवार को कैप्टन ने अपने प्रधान सलाहकार व प्रमुख चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) के साथ नई दिल्ली में बैठक की। करीब एक घंटे चली इस बैठक में भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री का विरोध करने वाले माझा के तीन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जबकि कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी का कद बढ़ाकर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।

10 जुलाई को ग्रामीण विकास का जायजा लेने लद्दाख जाएगा संसदीय दल। दल के सदस्य बैठक और दूर-दराज इलाकों का दौरा करेंगे। इससे पहले शिक्षा के बुनियादी ढांचे का जायजा लिया जा चुका है।

न्यूज गैलरी

देश के 51 टाइगर रिजर्व में होगी बाघों की गणना

रामनगर (नैनीताल) : देश के टाइगर रिजर्व में एनटीसीए (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) द्वारा बाघों की गणना कराई जाएगी। इस संबंध में एनटीसीए के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालकों व टाइगर रिजर्व के निदेशकों से आनलाइन बैठक कर दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। एनटीसीए हर चार साल में बाघों की गणना कराता है। (संसू)

कल्याण सिंह का ब्लड प्रेशर और शुगर नियंत्रित

लखनऊ : एसजीपीजीआइ (संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ) में भर्ती उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत स्थिर है। उनका रक्तचाप और ब्लड शुगर नियंत्रण में है। शरीर में संक्रमण भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। उन्हें चार जुलाई को क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट के आइसीयू में भर्ती किया गया था। (जासं)

अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचेगी बिजली

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिजली विभाग को शहरों और कस्बों के लिए बिजली की बेहतर आपूर्ति के लिए व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक बजली पहुंचाने के लिए भी व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। (राब्यू)

विमानों के धूमीकरण पर केंद्र से तलब की रिपोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विमानों में मच्छरों से मुक्ति के लिए किए जाने वाले धूमीकरण में कीटनाशकों के इस्तेमाल से यात्रियों की सेहत पर पड़ने वाले असर का आकलन करने वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने यह आदेश अतिरिक्त सालिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के बयान के बाद दिया। (प्रेट्र)

गगनदीप के स्वजन से भी पूछताछ करेगी एनआइए

मेरठ : केएलएफ (खालिस्तान लिबरेशन फोर्स) से जुड़े मेरठ के रामराज निवासी गगनदीप से एनआइए ने मोहाली जेल में पूछताछ की। गगनदीप ने एनआइए की टीम को कई अहम जानकारी दी हैं। एनआइए की टीम मान रही है कि गगनदीप के खातों में रकम भी आई है। अब एनआइए ने गगनदीप के मेरठ के बैंक खातों की डिटेल मांगी है। (जासं)

कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआइ करेगी

जयपुर : राजस्थान के चर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआइ करेगी। उसने बुधवार को मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के लिए सीबीआइ की टीम बुधवार को बाड़मेर पहुंच गई। बाड़मेर जिले में 23 अप्रैल की रात को प्रजापत को पकड़ने गई पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई थी। (जासं)

नहीं रहे शिवगिरी मठ के पूर्व प्रमुख स्वामी प्रकाशानंद

वरकला, प्रेट्र : केरल के वरकला स्थित शिवगिरी मठ के पूर्व प्रमुख स्वामी प्रकाशानंद का उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से निधन हो गया। वे 99 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उनके निधन पर दुख जताया है। मठ सूत्रों ने बुधवार को बताया कि स्वामी प्रकाशानंद ने नारायण मिशन अस्पताल में आखिरी सांस ली। शिवगिरी मठ के संस्थापक श्री नारायण गुरु के दर्शन से उन्होंने होकर प्रकाशानंद 23 साल की उम्र में मठ में शामिल हो गए थे। पहले उनका नाम कुमारन था। 35 साल की उम्र में उन्होंने स्वामी शंकरानंद से दीक्षा ली। वर्ष 1970 में श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट के सचिव बने और 1995-97 तक अध्यक्ष रहे।


शिवगिरी मठ के पूर्व प्रमुख स्वामी प्रकाशानंद। फाइल फोटो/एएनआइ

जम्मू-कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए हर वर्ग से ली राय

- परिसीमन आयोग के सदस्यों ने पहलगाम का किया दौरा, विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के 55 लोग आयोग से मिले

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और उनके युक्तिकरण के मिशन में जुटे परिसीमन आयोग के सदस्यों ने बुधवार को पहलगाम में दक्षिण कश्मीर के राजनीतिक दलों व अन्य संगठनों की राय ली। इसके बाद परिसीमन आयोग ने वादी के सभी जिला उपायुक्तों के साथ भी परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर बैठक कर समीक्षा की।

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही परिसीमन आयोग का मार्च, 2020 में गठन किया था। परिसीमन आयोग को मार्च, 2022 तक या उससे पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करना है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा 107 निर्वाचन क्षेत्रों को बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कुछ निर्वाचन क्षेत्रों का युक्तिकरण भी होना है।

जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित परिसीमन आयोग मंगलवार को पहली बार जम्मू कश्मीर के चार दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचा था। वीरवार को आयोग के सदस्य किश्तवाड़ का दौरा करने के बाद जम्मू पहुंचेंगे। वहां विभिन्न राजनीतिक दलों और जम्मू संभाग के विभिन्न जिला उपायुक्तों से मुलाकात भी होगी। शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले आयोग के सदस्य कुछ और संगठनों से भी मिल सकते हैं। बता दें कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने परिसीमन आयोग का बहिष्कार कर रखा है। सुबह करीब सवा ग्यारह बजे परिसीमन आयोग के सदस्य दक्षिण कश्मीर के प्रमुख पर्यटनस्थल पहलगाम पहुंचे। पहलगाम क्लब में ही आयोग ने दक्षिण कश्मीर के चारों जिलों कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा और शोपियां के जिला चुनाव अधिकारियों से मुलाकात कर परिसीमन से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श किया। इसी क्लब में उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। करीब 55 लोग विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के रूप में आयोग से मिले।

जिओ टावर से नेटवर्क कार्ड चोरी कर भेजते थे चीन, वहां से फिर भारत में बिकने आ जाते

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

लोनी पुलिस व क्राइम ब्रांच ने जिओ के टावरों से नेटवर्क कार्ड व माडम चोरी करने वाले पांच शातिरों को गिरफ्तार किया है। आरोपित दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल टावरों से नेटवर्क कार्ड चोरी कर चीन में भेज देते थे। पुलिस ने आरोपितों के पास से दो करोड़ रुपये के कार्ड, 105 मोबाइल फोन व अन्य उपकरण बरामद किए हैं। आरोपित अब तक दिल्ली-एनसीआर से करोड़ों रुपयों की कीमत के 200 से अधिक नेटवर्क कार्ड व माडम चोरी कर चुके हैं। दिल्ली के करोलबाग से कोरियर के जरिये कार्ड चीन में भेजे जाते थे। चीन की कंपनियां इन्हें नया रूप देकर वापस भारत की कंपनियों को बेच देती थीं। कार्ड की कीमत के बदले चीन से हवाला के जरिये यहां बैठे गिरोह के सदस्यों को अन्य माल उपलब्ध होता था।

बुधवार को पुलिस लाइन में एसपी ग्रामीण डॉ. ईरज राजा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित दिल्ली के प्रसाद नगर निवासी सौरभ अग्रवाल, गोकुलपुरी दिल्ली निवासी जहांगीर आलम, लोनी के ट्रानिका सिटी निवासी मुहम्मद सरफराज सिद्दीकी, कदीम और दिल्ली दयालपुर निवासी मोनी उर्फ शादाब मलिक हैं। इनके दो साथी सलमान व सोनू को कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और दिल्ली मुस्तफाबाद निवासी मुन्तियाज अभी फरार है। सौरभ का करोलबाग में मोबाइल के उपकरणों का थोक का काम है और सौरभ ही कार्ड व अन्य सामान चीन में कोरियर के माध्यम से भेजता था। जहांगीर आलम का कबाड़ का बड़ा काम है, वह माडम को तोड़कर उपकरणों को अलग-अलग कर एकत्र करता था।

पांच शातिर गिरफ्तार


आरोपितों से बरामद जिओ टावर से चोरी हुए नेटवर्क कार्ड। जागरण

कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष कमांडर ढेर, 12 लाख का था इनामी

आतंक से जंग ▸ हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई जमकर मुठभेड़

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

सुरक्षाबलों ने बुधवार तड़के उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के पाजीपोरा, हंदवाड़ा में हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 12 लाख के इनामी आतंकी मेहराजुदीन हलवाई उर्फ उबैद को मार गिराया। कश्मीर में वह बीते 10 साल से सक्रिय था। मेहराजुदीन हलवाई अत्याधुनिक संचार उपकरणों के इस्तेमाल में माहिर था। इसका इस्तेमाल वह न सिर्फ आतंकियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने में, बल्कि नए कैडर की भर्ती के लिए भी करता था। उसने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा ही, साथ ही मुखबिरी के शक में हुर्रियत समर्थकों और पूर्व आतंकियों का भी कत्ल किया। उसकी मौत उत्तरी कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन व लश्कर-ए-तैयबा को बड़ा झटका और सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी है। वह आतंकी डबल-ए श्रेणी का आतंकी था।

2012 में बना आतंकी : उत्तरी कश्मीर में बारामुला जिले के खुशहालमट्टू-सोपोर का रहने वाला मेहराजुदीन हलवाई 2012 में लश्कर का सक्रिय आतंकी बना था। वह 29 अक्टूबर, 2015 को मारे गए लश्कर के पाकिस्तानी कमांडर अबु कासिम का करीबी था। कासिम ने ही अगस्त, 2015 में ऊधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला कराया था। कासिम ने कश्मीर में सुरक्षाबलों पर 2012 से 2015 तक करीब छह आत्मघाती हमले कराए थे। कासिम के मारे जाने के बाद मेहराजुदीन हलवाई ने हिजबुल मुजाहिदीन का दामन थाम लिया था और 2016 में वह नजर आना बंद हो गया था। वह भूमिगत रहते हुए ही विभिन्न आतंकी संगठनों के बीच तालमेल, उनके वित्तीय नेटवर्क और नए कैडर की भर्ती को अंजाम दे रहा था। इसके अलावा उत्तरी कश्मीर और श्रीनगर-बारामुला-कुपवाड़ा राजमार्ग पर आतंकी हमलों के पीछे भी उसका ही दिमाग था। सुरक्षाबलों का दबाव बढ़ने पर वह कुछ समय के लिए पाकिस्तान भी भाग गया था।

नाके पर पकड़ा गयाः आइजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मेहराजुदीन हलवाई की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम को हंदवाड़ा पुलिस ने एसएसबी के जवानों के साथ वतयन इलाके में नाका लगाया था। इसी दौरान नाका पार्टी को एक देखकर एक व्यक्ति ने जांच से बचने का प्रयास किया। इसके बाद सुरक्षाबलों ने उसे बचाव का कोई मौका दिए बगैर पकड़ लिया। उससे एक ग्रेनेड मिला। उसे उसी समय निकटवर्ती पुलिस चौकी पर ले जाया गया, जहां उसकी पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल मेहराजुदीन हलवाई के रूप में हुई। उसने हंदवाड़ा के पाजीपोरा में अपने एक ठिकाने की जानकारी देते हुए बताया कि वहां हथियारों का एक बड़ा जखीरा है।

- हुर्रियत समर्थकों और पूर्व आतंकियों के कत्ल में भी रहा था शामिल


जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में बुधवार को मुठभेड़ में मारा गया हिजबुल मुजाहिदीन का 12 लाख का इनामी आतंकी मेहराजुदीन हलवाई उर्फ उबैद। फाइल फोटो/एएनआइ

जब उसके ठिकाने पर ले जाया गया

सुरक्षाबलों का एक दल उसे लेकर बुधवार तड़के करीब सवा दो बजे पाजीपोरा पहुंचा। मेहराजुदीन हलवाई ने वहां एक जगह हथियार होने का दावा किया। सुरक्षाबलों ने जब वहां तलाशी शुरू की तो हलवाई ने अचानक ही एक जगह से एके-47 राइफल निकाली और जवानों पर फायरिंग कर दी। जवानों ने भी खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। करीब 15-20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इसमें हलवाई मारा गया।

नौशहरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम

जागरण संवाददाता, राजौरी : सरहद पर शांति का ढोंग रचकर पाकिस्तान आए दिन जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने की साजिश रच रहा है। बुधवार शाम करीब छह बजे आतंकवादियों के दल ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ का बड़ा प्रयास किया। सेना की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। दो जवान घायल हो गए जिनमें से एक की गंभीर हालत है। सरहद से सटे क्षेत्र में सेना ने तलाशी अभियान भी चलाया।

सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि शाम को मौसम खराब होने की आड़ में आतंकवादियों के एक समूह ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर के कलाल क्षेत्र की नैनी पोस्ट के पास से भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया। सभी आतंकी हथियारों से लैस थे। सेना के जवानों ने आतंकियों को देख रुकने की चेतावनी दी। इसे अनसुनाकर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने एक आतंकी ढेर कर दिया। अन्य आतंकी वापस भाग गए। सेना ने मारे गए आतंकी का शव बरामद कर लिया है। उसके पास से एक एके 47 राइफल, एके 47 की चार मैगजीन और दो ग्रेनेड बरामद किया।

उप्र और मप्र के बंधन से चित्रकूट को कराएं मुक्त

- संघ प्रमुख व सरकार्यवाह से मुलाकात में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने रखी बात
- कहा, दो प्रांतों में बंटे चित्रकूट के एकीकरण से आएगी बेहतरी

जागरण संवाददाता, चित्रकूट

प्रभु श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट को उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के बंधन से मुक्त कराएं। दोनों प्रांतों के बीच बंटे क्षेत्र का एकीकरण कराने से बेहतरी आएगी। तुलसी जन्मस्थली राजापुर भी उपेक्षित है। यहां के संपूर्ण विकास के लिए इसकी जरूरत है। ये बातें बुधवार को तुलसीपीठाधीश्वर पद्मभूषण जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने चित्रकूट प्रवास के दूसरे दिन उनसे मिलने पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत से कहीं। दोनों के बीच करीब एक घंटे की मुलाकात में कई अन्य मसलों पर भी चर्चा हुई।

जगद्गुरु ने संघ प्रमुख से कहा कि चित्रकूट का समग्र विकास बाधित है। इसकी मुख्य वजह, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र का बंटा होना है। इसका एकीकरण होना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार ही पहल कर सकती है। उन्होंने तुलसी जन्मस्थली राजापुर के भी उपेक्षित होने का उलाहना दिया। कहा कि जिन्होंने भगवान राम को घर-घर पहुंचाया, उनकी नगरी का विकास अब तक नहीं हुआ है। पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की बातें हुईं, लेकिन सटीक कदम नहीं बढ़े। इसके अलावा जगद्गुरु ने राष्ट्रीयता के मुद्दे पर चर्चा की। कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा और उनके लिए कुछ अलग करने की दिशा में और कदम बढ़ें। लोगों में राष्ट्रवादी भावना कैसे जागृत हो, इस पर भी दोनों दिग्गजों के बीच चर्चा हुई।

संघ प्रमुख से मिले सरकार्यवाह, कई और पदाधिकारी पहुंचे

प्रांत प्रचारकों की बैठक

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : प्रभु श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चार दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक को लेकर बुधवार को सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत कई और पदाधिकारी पहुंचे। सरकार्यवाह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से आरोग्यधाम में मुलाकात की। इससे पहले सभी पदाधिकारियों का चित्रकूटधाम कर्वी रेलवे स्टेशन पर स्वागत हुआ।

बुधवार सुबह करीब छह बजे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले कर्वी स्थित रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां जिले की सीमा से सटे मध्यप्रदेश के सतना जिला अंतर्गत दीनदयाल शोध संस्थान (डीआरआइ) के राष्ट्रीय संगठन सचिव अभय महाजन और भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे के साथ ही संघ और भाजपा के तमाम पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सरकार्यवाह ने डीआरआइ के प्रकल्प आरोग्यधाम पहुंचकर संघ प्रमुख से शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भय्याजी जोशी, सुरेश सोनी, अनिल समेत अन्य पदाधिकारी भी चित्रकूट पहुंच गए हैं।

नोएडा से बेंगलुरु तक चार बार बेची गई रांची की युवती

- बेंगलुरु से छुड़ा कर लाई गई रांची, सिल्ली के पूर्व विधायक ने निभाई अहम भूमिका
- नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और बेंगलुरु में काम दिलाने के नाम पर सौदा

जागरण संवाददाता, रांची

मानव तस्करी के लिए बदनाम रहे झारखंड में एक बार फिर एक युवती को काम दिलाने के नाम पर उसके रिश्तेदारों द्वारा बेचे जाने का मामला सामने आया है। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो की पहल पर रांची के सोनाहातू की इस 21 वर्षीय युवती को बेंगलुरु से वापस रांची लाया गया है। पीड़िता के अनुसार, तीन साल के दौरान उसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और बेंगलुरु में चार बार बेचा गया। बुधवार को पूर्व विधायक अमित महतो युवती का रेस्क्यू कराकर बेंगलुरु से विमान के जरिये रांची लेकर पहुंचे।

पीड़िता ने पूर्व विधायक अमित महतो का नंबर किसी तरह प्राप्त करने के बाद बेंगलुरु से फोन कर उनसे बचा लेने की गुहार लगाई थी। युवती के अनुसार, उससे घर का काम कराने के साथ मारपीट भी की जा रही थी। जबरदस्ती नशीले पदार्थों का भी सेवन कराया जा रहा था।

ममेरी बहन ने ही बेच दिया था युवती को

अमित महतो ने बताया कि सिमडेगा की रहने वाली पीड़िता की ममेरी बहन ने ही उसे बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाने के बाद अलग-अलग लोगों के हाथ बेच दिया। आरोपित महिला पति के साथ दिल्ली में रहती है। तीन वर्ष पहले उसने युवती को दिल्ली बुलाया था। कुछ दिनों अपने साथ भी रखा। पीड़िता को बड़े शहरों में रहने और नौकरी के एवज में अच्छी-खासी रकम दिलाने के सपने दिखाए। खरीदार उसे मेहनत-मजदूरी के एवज में पैसे नहीं देते थे और हर तरह से शोषण करते थे। मारपीट की जाती थी।

सरकारी नौकरी का झांसा देकर हजारों को ठगने के आरोप में आठ गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : हजारों लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाने का वादा करके उनसे ठगी करने के आरोप में आठ लोगों को बंगाल के पूर्व बर्द्धमान जिले से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बुधवार को बताया कि राज्य के कम से कम 3,000 लोगों से करोड़ों रुपये ठगे गए। फ्यूचर इंडिया नाम की कंपनी ने लोगों को राजमार्गों की सुरक्षा के लिए सरकारी नौकरियां दिलाने का वादा करके प्रत्येक से 55,000 रुपये से एक लाख रुपये तक लिए। लोगों का भरोसा हासिल करने के लिए आरोपित उन्हें सड़क सुरक्षा पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कथित हस्ताक्षर वाले कुछ दस्तावेज दिखा देते थे। उत्तर 24 परगना जिले में निमता पुलिस थाना इलाके में विराति में स्थित कंपनी के मुख्यालय में सड़क सुरक्षा पर प्रशिक्षण भी दिया जाता था। सोमवार की रात को कंपनी के आठ अधिकारी संभावित उम्मीदवारों से अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने के लिए के पालसित में एक रेस्त्रां में एकत्रित हुए। सूचना मिलते ही पहले ठगे जा चुके लोग घटनास्थल पर पहुंच गए।

लव जिहाद : बढ़ाई एससी-एसटी एक्ट की धारा

जागरण संवाददाता, आगरा

आगरा में पूर्व आइएएस अधिकारी की बेटी को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उत्पीड़न करने के आरोपित आरिफ हाशमी पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पीड़िता के कोर्ट में बयान कराने के बाद बुधवार को पुलिस ने मुकदमे में एससी-एसटी एक्ट की धारा भी बढ़ा दी। अब केस की विवेचना सीओ सदर करेंगे। 10 वर्ष तक उत्पीड़न करने के सुबूत के तौर पर पुलिस पुराने फोटो और वीडियो के साथ पीड़िता के इलाज के पेपर भी संकलित कर रही है।

पूर्व आइएएस अधिकारी की विवाहित बेटी को लखनऊ के ताल कटोरा में राजाजीपुरम निवासी आरिफ हाशमी ने लव जिहाद के जाल में फंसाया था। पार्टी में मुलाकात के बाद उसने साझा कारोबार का झांसा दिया। उसने अपना नाम आदित्य आर्य बताया था। दबाव बनाकर उसने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इसके एक वर्ष बाद उसने महिला का मतांतरण करा निकाह भी कर लिया। इसके बाद ज्यादती करने लगा। अब पीड़िता ने परेशान होकर सदर थाने में उसके खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी, मारपीट, जानलेवा हमला, विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मेडिकल के बाद सोमवार को ही पीड़िता के कोर्ट में बयान करा दिए। मंगलवार को विवेचक इंस्पेक्टर सदर ने अवलोकन किया और बयानों को विवेचना में शामिल कर लिया।

दावत-ए-इस्लामी ने रोका तबलीग का काम

जासं, कानपुर : सूफी इस्लामिक बोर्ड के आरोपों के बाद दावत-ए-इस्लामी संगठन के सदस्य सतर्क हो गए हैं। सड़क पर जगह-जगह लोगों को एकत्र कर तबलीग (धार्मिक जानकारी देने) का काम फिलहाल नहीं किया जा रहा है। अभी तक नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को मजहबी जानकारी दी जा रही थी। कई जगहों पर लगाए गए डोनेशन बाक्स भी हटा लिए गए हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता सूफी कौसर हसन मजीदी ने दावत-ए-इस्लामी पर मतांतरण कराने व चंदा एकत्र कर उसका प्रयोग गलत कार्यों में करने के आरोप लगाए हैं। दावत-ए-इस्लामी पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को प्रार्थनापत्र भी दिया जा चुका है। कोई कार्रवाई न होने पर सूफी इस्लामिक बोर्ड के सदस्य सीएम से मुलाकात का समय मांग रहे हैं।

मतांतरण व निकाह कराने वाला ट्रस्ट पिछले साल हुआ था पंजीकृत

जासं, पूर्वी दिल्ली : कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में वकील के चैंबर में मतांतरण और निकाह कराने वाले काजी ने पिछले साल ही ट्रस्ट का पंजीकरण कराया था। उससे पहले वह दूसरे संगठनों के सहारे इन गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पटपड़गंज में रहने वाले व्यक्ति की बेटी का मतांतरण व निकाह कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में वकील के चैंबर में कराया गया था। इसी चैंबर को मजार वाली मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अब निकाह ट्रस्ट चलाने वाले काजी मोहम्मद अकबर दहलवी ने मतांतरण व निकाह कराया था। काजी ने पिछले वर्ष इस ट्रस्ट को पंजीकृत कराया था। सूत्रों की मानें तो ट्रस्ट बनाने के बाद से उसकी सक्रियता कोर्ट परिसर में बढ़ गई थी। इससे पहले उसे मतांतरण प्रमाण पत्र और निकाहनामा देने के लिए दूसरे संगठनों का सहारा लेना पड़ता था।

टूटा वादा

सालभर पहले गलवन घटना के बाद चीन आयातित सामान के बहिष्कार का चला था अभियान, अब बाजार में फिर धड़ल्ले से बेचे और खरीदे जा रहे चीन निर्मित उत्पाद

वक्त के साथ आक्रोश पड़ा ठंडा, फिर चल पड़ा चीन का धंधा

राजेश डडवाल, ऊना

गत वर्ष जून माह में गलवन में चीनी सैनिकों ने जिस तरह भारतीय सैनिकों पर कायराना हमला किया था, उसने पूरे देश को चीन के खिलाफ आक्रोश और गुस्से से भर दिया था। व्यापारियों के साथ तमाम धार्मिक संगठनों ने इस कृत्य की कड़ी भर्त्सना करते हुए चीन को सबक सिखाने के उद्देश्य से चीन आयातित सामान के बहिष्कार करने की ठानी थी, लेकिन वक्त के साथ आक्रोश ठंडा पड़ गया है। ऐसे में चीन का धंधा फिर चल निकला है।

चीन की कायराना हरकत के बाद हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चला। धूर्त पड़ोसी को जोरदार आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारियां हुईं। चीनी सामान के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'भारतीय सामान-हमारा अभिमान' अभियान शुरू किया गया। लेकिन, समय बीतने के साथ सारा आक्रोश ठंडा पड़ता गया। अब चीन निर्मित सामान फिर धड़ल्ले से बेचा और खरीदा जा रहा है। आयातित सामान जिले के बाजारों में बदस्तूर पहुंच रहा है।

प्रथम चरण में चीन आयातित सामान में 50 फीसद तक गिरावट का था लक्ष्य: केंद्रीय व्यापार परिषद के बहिष्कार अभियान के तहत 100 से अधिक वस्तुओं की सूची तैयार की गई थी, जिसके तहत ऐसे उत्पाद चिह्नित हुए थे, जो चीन से भारत के बाजारों में आते थे। इनके बहिष्कार का फैसला स्थानीय व्यापार संघ ने केंद्रीय व्यापार परिषद के निर्देश पर किया था। अभियान के प्रथम चरण में चीनी उत्पादों की कुल खपत का 50 प्रतिशत हिस्सा कम करने का लक्ष्य रखा गया था।

चीनी सामान की लगातार बनी हुई है मांग: स्मार्टफोन की मांग पर असर न तब था और न अब है। जिले में चीन की प्रमुख स्मार्टफोन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स विवेक ने बताया कि मांग में कहीं कोई कमी नहीं है। अलबत्ता, कोरोना कर्फ्यू के बाद चीनी सामान की बिक्री बढ़ गई है और स्टाक जल्द खत्म हो रहा है। आनलाइन बिक्री पर नजर रखने वालों के हवाले से भी यही सामने आया कि इन प्लेटफार्म पर चीनी वस्तुओं या चीन से आए सामान की बिक्री में कोई कमी नहीं आ रही है। मांग लगातार बनी हुई है।

व्यापारियों से चीन निर्मित सामान के बहिष्कार का किया आग्रह: स्वदेशी जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सहित कई सामाजिक संगठनों ने व्यापारियों से आग्रह किया है कि चीन निर्मित सामान की खरीद और बिक्री को नजरअंदाज करें। साथ ही शहरवासियों से भी अपील की है कि वे भी चीन का सामान न खरीदें, जिससे उसे आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके। चीन भारत से ही कमाकर हमारे ही देश के सैनिकों के खिलाफ उस धन का प्रयोग करता है, जिसे रोका जाना चाहिए।


बाजार पर चीनी माल का कब्जा। फाइल फोटो

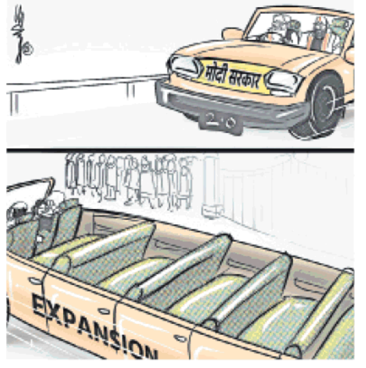
यदि हमें चीनी सामान के उपयोग को बंद करना है तो पहले उसके विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। दूसरी तरफ सरकार को घरेलू व्यापार एवं उद्योग को सक्षम बनाने के लिए कोई ठोस नीति बनानी होगी, ताकि कम दाम पर क्वालिटी के उत्पाद देश में भी बनें।
-विनय कक्कड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्यापार मंडल ऊना।

70 फीसद तक बढ़ी चीनी वस्तुओं की मांग

गलवन घटना के बाद रिटेल कारोबार में चीनी सामान की मांग में करीब 35 फीसद की कमी आई थी। अब चीनी सामान की बाजार में मांग 70 फीसद तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा खपत इलेक्ट्रानिक सामान की है। अकेले ऊना जिले में एक माह में करीब 40 करोड़ रुपये का कारोबार चीन आयातित वस्तुओं से हो रहा है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी



जागरण विशेष

मास्क ऐसा, आंख रहेगी सुरक्षित, नहीं फूलेगी सांस

आपदा में अवसर : इलाहाबाद विवि के बायोकेमेस्ट्री विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर मुनीश की टीम ने किया कमाल

गुरुदीप त्रिपाठी • प्रयागराज

कोरोना काल में मानवता के हित में विज्ञानियों ने बढ़-चढ़ कर नवोन्मेष किए हैं। ऐसी ही एक पहल इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (इविवि) में बायोकेमेस्ट्री विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डाक्टर मुनीश पांडेय के निर्देशन में हुई है। उनकी टीम ने एंटी कोरोना थ्रीडी प्रिंटेड मास्क का डिजाइन तैयार किया है। डाक्टरों ने भी इसे सेहत के अनुकूल माना है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कोलकाता स्थित कंट्रोलर जनरल आफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क ने 20 साल के लिए इस मास्क के पेटेंट को मान्यता दी है। जल्द ही यह मास्क बाजार में सुलभ होगा।

कोरोना की पहली लहर के दौरान मास्क लोगों की जरूरत बना और दूसरी लहर में अनिवार्यता। यह तथ्य भी सामने आया कि सामान्य मास्क पहनने से सांस फूलने की समस्या होती है। ऐसे लोग जो चश्मा लगाते हैं, उन्हें चश्मे के कांच पर मुंह से निकलने वाली भाप की परत परेशान करती है। डा. मुनीश बताते हैं कि इन्हीं समस्याओं को देखते हुए ऐसे मास्क पर काम शुरू हुआ जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रदूषण से बचाए। इविवि में बायोकेमेस्ट्री डिपार्टमेंट की टीम ने आठ महीने की अवधि में एंटी कोरोना थ्रीडी प्रिंटेड मास्क की डिजाइन तैयार कर ली।



इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री विभाग की लैब में थ्रीडी प्रिंटेड मास्क की डिजाइन तैयार करते डाक्टर मुनीश पांडेय • जागरण



मेडिकल दृष्टिकोण से यह थ्रीडी मास्क कोरोना से बचाव के लिए बहुत कारगर होगा। आंखों के लिए कवच का काम करेगा। कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। लैब में जांच के बाद इसको मंजूरी मिली तब पेटेंट के लिए आवेदन किया गया।
डा. शिवाकुमार



मानवीय दृष्टिकोण से यह मास्क काफी बेहतर रहेगा। आम मास्क से केवल मुंह ढंका जा सकता है। थ्रीडी मास्क से पूरे चेहरे के साथ आंख को ढंका जा सकेगा। यह सुरक्षा देने के साथ जनमानस के लिए ज्यादा असरदार होगा।
डा. शैलेंद्र कुमार मिश्र

पांच लेयर वाला है यह मास्क: डा. मुनीश बताते हैं कि पांच लेयर वाले थ्रीडी मास्क में आंखों की सुरक्षा सुनिश्चित रखने के लिए ग्लास भी फिट किया जा सकेगा। दरअसल कई लोग मास्क के साथ फेसशील्ड पहन रहे हैं। इससे गर्मी लगती है। इस समस्या से भी यह मास्क राहत दिलाएगा। सांस लेने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए फिल्टर लगाया गया है। इसकी खास डिजाइन आंख की सुरक्षा भी करेगी। वह बताते हैं कि डिजाइन थ्रीडी प्रिंटेबल तकनीक से तैयार की गई है और काफी प्रचलन में है। वैसे डिजाइन के अनुरूप मास्क बनाने की दिशा में अभी किसी कंपनी ने पहल नहीं की है। दरअसल, पहले यह पेटेंट गजट में प्रकाशित होगा। इसके बाद यदि कोई एजेंसी अथवा कंपनी संपर्क करती है तो उसे डिजाइन सौंप दी जाएगी। अनुमान है कि बाजार में इसकी कीमत करीब 200 रुपये होगी।

ऐसे तैयार हुई डिजाइन करने वाली टीम: डा. मुनीश तकरीबन 15 साल पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के रमन फेलो के तहत एक वर्ष शोध के लिए अमेरिका के ओहियो स्टेट स्थित क्लीवलैंड क्लीनिक गए थे। वहां नारायण ट्रांसलेशन रिसर्च सेंटर और नारायण मेडिकल कालेज नेल्लौर के डा. शिवाकुमार से मुलाकात हुई। वह नैनो मैटेरियल साइंस में शोध कर रहे थे। शिवाकुमार के साथी पुडुचेरी के डा. पी कार्थिगेयन इंजीनियरिंग से जुड़े हैं। कोरोनाकाल में मास्क डिजाइन करने पर चर्चा हुई तो दोनों टीम में शामिल किए गए। इविवि में बायोकेमेस्ट्री विभाग के प्रोफेसर एसआइ रिजवी और विभाग के डा. ऋषभ कुमार, डा. शंभूशरण त्रिपाठी तथा मानवीय दृष्टिकोण से इविवि मानव विज्ञान विभाग के डा. शैलेंद्र कुमार मिश्र को शामिल किया गया।

उत्तर प्रदेश में डेल्टा प्लस की दस्तक, दो रोगी मिले

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कोरोना के नए वैरिएंट डेल्टा प्लस ने उप्र के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस वैरिएंट से संक्रमित दो रोगी मिले हैं। इनमें एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा ठीक हो चुका है। इनके संपर्क में आए लोगों समेत करीब 100 से ज्यादा लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग में नया वैरिएंट नहीं मिला है। इंस्टीट्यूट आफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलाजी, नई दिल्ली से जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने के बाद सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। कई राज्यों में कोरोना के नए वैरिएंट डेल्टा प्लस मिलने के मामले पहले ही सामने आ चुके हैं। प्रदेश में यह पहला मामला है। जिन दो मरीजों में डेल्टा प्लस वैरिएंट की पुष्टि हुई है, उनमें से एक देवरिया व दूसरा गोरखपुर का निवासी है। देवरिया निवासी 66 वर्षीय बुजुर्ग की 29 मई को मौत हो चुकी है।

न्यूज गैलरी

मौत के खतरे को 82 फीसद कम करती है सिंगल डोज

नई दिल्ली: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने में कोरोना वैक्सीन बहुत कारगर पाई गई हैं। तमिलनाडु के पुलिसकर्मियों पर किए गए अध्ययन में पाया गया है कि वैक्सीन की सिंगल डोज मौत के खतरे को 82 फीसद कम करती है। परिषद ने ट्वीट किया, 'अध्ययन से सामने आया है कि वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स में मौत को रोकने में कारगर है।(प्रेट्र)

राजस्थान में महिला को एक मिनट में लगाए दो टीके

जयपुर: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। जिले के बाकरा गांव निवासी माया देवी को एक मिनट दो टीके लगा दिए। जब माया देवी का टीका लगवाने का नंबर आया तो नर्स मोबाइल पर बात कर रही थी। बात करते हुए ही उसने करीब आधा दर्जन लोगों के टीके लगाए। टीके लगाते समय महिला नर्सिंगकर्मी मोबाइल पर बात कर रही थी। कलेक्टर ने रिपोर्ट मांगी है। (जासं)

एंफोटेरिसिन-बी और रेमडेसिसिवर पर हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने फंगस रोगियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंफोटेरिसिन-बी की उपलब्धता और रेमडेसिविर के आयात पर केंद्र से रिपोर्ट मांगी है। कोरोना से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि विदेश से मंगाए गए एंफोटेरिसिन-बी की मात्रा एवं आने वाली दवा के बारे में जानकारी दें। (जासं)

नौ राज्यों में कोरोना नियंत्रण उपायों को और मजबूत किया जाएगा : सरकार

तैयारी ▸ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने लिखा पत्र, जांच और टीकाकरण जैसे उपायों पर जोर

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि जिन नौ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उनमें महामारी को नियंत्रित करने के उपायों को मजबूत किया जाएगा। इन राज्यों में जांच और टीकाकरण में तेजी लाना, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की योजना बनाना और प्रभावी क्लीनिकल प्रबंधन जैसे उपाय किए जाएंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इन राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, त्रिपुरा और सिक्किम को लिखे पत्र में चिंता पैदा करने वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया है।

भूषण ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों को जांच और टीकाकरण, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की योजना बनाना, कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करना और प्रभावी क्लीनिकल प्रबंधन आदि उपाय करने चाहिए। देश भर में 73 जिलों में संक्रमण दर 10 फीसद से ज्यादा है, इनमें से 45 जिले पूर्वोत्तर के राज्यों के हैं। इसको देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भी बुधवार को पूर्वोत्तर के राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के हालात की समीक्षा की। गृह सचिव ने पांच सूत्रीय रणनीति यानी जांच, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोरोना से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार पर बल दिया।



कोलकाता में बुधवार को एक टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे लोगों ने कोरोना रोधी टीका लगवाया। इन्हें कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक दी गई। प्रेट्र

देश के 174 जिलों में मिले वैरिएंट आफ कंसर्न के मामले

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 174 जिलों में वैरिएंट आफ कंसर्न यानी कोरोना वायरस के चिंताजनक वैरिएंट के मामले पाए गए हैं। इनके सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, बंगाल और गुजरात में मिले हैं। भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (इंसकाग) ने सामुदायिक सैंपल में वैरिएंट आफ कंसर्न (वीओसी) के मामले पाए हैं। वीओसी में कोरोना वायरस के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस आते हैं। डेल्टा वैरिएंट को भारत में दूसरी लहर का कारक माना जाता है और इसी में म्यूटेशन होने के बाद डेल्टा प्लस वैरिएंट बना है। डेल्टा, जिसे पहले डबल म्यूटेंट वैरिएंट के नाम से भी जाना जाता था, सबसे पहले महाराष्ट्र में पाया गया था। महाराष्ट्र के कई जिलों में डेल्टा वैरिएंट से संक्रमित मामले मिले थे। अब देश के कई राज्यों के साथ ही कई देशों में इसके मामले मिले हैं।

देश में फिर बढ़े संक्रमण के मामले: इन राज्यों के चलते देश में कोरोना संक्रमण की तस्वीर फिर बदलने लगी है। संक्रमण के मामले 40 हजार से नीचे आ गए थे, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 40 हजार से ऊपर चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में नौ से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। वहीं, केरल से मिले आंकड़ों के मुताबिक वहां 14 हजार से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं और डेढ़ सौ के करीब मौत भी हुई है।

भारत में लांबा वैरिएंट नहीं मिला

कोरोना वायरस का लांबा वैरिएंट भारत में नहीं मिला है। अभी तक यह 30 देशों में पाया गया है। सबसे पहले पिछले साल दिसंबर में यह पेरू में सामने आया था। कई देशों में बड़ी संख्या में इससे संक्रमित मामले मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह बहुत संक्रामक है।

कोरोना/वैक्सीन मीटर

भारत	
24 घंटे में नए मामल	43,733
कुल सक्रिय मामले	4,59,920
24 घंटे में टीकाकरण	36.05 लाख
अब तक कुल टीकाकरण	36.13 करोड़

मंगलवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति

नए मामले	43,733
कुल मामले	3,06,63,665
मौतें	930
कुल मौतें	4,04,211
कुल सक्रिय मामल	4,59,920
ठीक होने की दर	97.18 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.29 फीसद
मृत्यु दर	1.32 फीसद
जांचें (मंगलवार)	19,07,216
कुल जांचे	42,33,32,097

टीके से घुटने का दर्द दूर तो किसी को मिली नींद भरपूर

अजय जैन, भोपाल

कोरोना से बचाव के लिए जब टीकाकरण शुरू हुआ था तो कुछ लोग इसके दुष्प्रभावों की आशंका से डरे हुए थे, लेकिन जब टीके लगना शुरू हुए तो लोग इसके फायदे गिनाने लगे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं, जिनका कहना है कि टीका लगने के बाद उनकी वर्षों पुरानी बीमारियां भी ठीक हो गईं। इनमें घुटने के दर्द से लेकर अनिद्रा और एलर्जी से जुड़ी बीमारियों के मरीज अधिक हैं।

विदिशा के क्रांति चौक में रहने वाले सीमेंट व्यवसायी गिरीश शर्मा बताते हैं कि उनके दादा-दादी को पिछले माह कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं। इसका फायदा यह हुआ कि दोनों के घुटनों का दर्द गायब हो गया है। उनके 80 वर्षीय दादाजी कोमल प्रसाद शर्मा बताते हैं कि वह और 75 साल की उनकी पत्नी विमला बाई करीब 20 साल से घुटनों के दर्द से परेशान थे। काफी इलाज के बाद भी आराम नहीं मिला। वह बिना लाठी के सहारे के एक कदम भी नहीं चल पाते थे, लेकिन जबसे टीका लगवाया है, उनकी लाठी छूट गई है। अब वह छत की सीढ़ियां तक बिना सहारे के चढ़ जाते है। कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ स्टेनो राकेश श्रीवास्तव बताते हैं कि दो साल पहले उनके दिल का आपरेशन हुआ था। उसके बाद से अनिद्रा की बीमारी थी। उन्हें रात में दो से तीन बजे तक नींद नहीं आती थी। पिछले माह 23 जून को उन्होंने कोरोना का पहला टीका लगवाया। इसके बाद से अनिद्रा की बीमारी दूर हो गई। 39 वर्षीय कंप्यूटर इंजीनियर संयोग श्रीवास्तव बताते हैं कि उन्हें 10 साल से एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या थी। दूसरा टीका लगने के बाद बीमारी दूर हो गई।



विदिशा के 80 वर्षीय कोमल प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी 75 वर्षीय विमला बाई को टीके की दोनों खुराक दिए जाने के बाद घर की सीढ़ियां बिना किसी सहारे के चढ़ और उतर सकते हैं। नईदुनिया

हो सकता है वायरल इन्फेक्शन में लाभ हुआ हो

विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कालेज के डीन डा. सुनील नंदेश्वर का कहना है कि इस वैक्सीन से शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ही एंटीबाडी विकसित होती हैं। हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन संबंधी कुछ बीमारियों में फायदा हुआ हो, लेकिन घुटनों का दर्द दूर हो जाना शोध का विषय है।

इस संबंध में अभी कोई शोध नहीं हुआ है। इस कारण यह कह पाना मुश्किल है कि कोरोना के खिलाफ एंटीबाडी बनने से और भी फायदे हो सकते हैं। निश्चित रूप से यह शोध का विषय है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को ब्रांड एंबेसडर बनाएं।
- डा. सरमन सिंह, निदेशक, एम्स भोपाल

'सरकार मदद नहीं करेगी, तो क्या लोग जमीन बेचकर इलाज कराएं'

राज्य ब्यूरो, रांची

▸ ब्लैक फंगस संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोटने की मौखिक टिप्पणी

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने ब्लैक फंगस संबंधी एक मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब सरकार इलाज में मदद नहीं करेगी तो क्या लोग अपनी जमीन बेचकर अपना इलाज कराएंगे। अदालत ने रिम्स में पीड़िता उषा देवी का समुचित इलाज नहीं होने पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पीड़ित को पैसे देकर इलाज में मदद करता।

अदालत ने सरकार से पूछा कि जब ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, तो उससे निपटने के लिए राज्य सरकार की नीति क्या है। ऐसे मरीजों के इलाज के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि 15 जुलाई से पहले सरकार शपथ पत्र के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी दे। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। अदालत ने यह भी पूछा है कि पीड़ित महिला के इलाज की क्या व्यवस्था की गई है।

सुनवाई के दौरान झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि रिम्स में ब्लैक फंगस मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल उषा देवी को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर बाहर भेज जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ऐसे मरीजों का सीमित संसाधनों में बेहतर इलाज करने का प्रयास रही है। रिम्स निदेशक डा. कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सारी तैयारी पूरी है। उक्त महिला का इलाज एक मेडिकल टीम कर रही है। इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। अदालत ने कहा कि केवल उषा देवी का ही नहीं, बल्कि ब्लैक फंगस से पीड़ित सभी मरीजों का समुचित इलाज की व्यवस्था रिम्स में की जाए।

हिल स्टेशनों में वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने पर विचार करे सरकार : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नैनीताल

हाई कोर्ट ने नैनीताल समेत राज्य के हिल स्टेशनों में बिना आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के पर्यटकों को एंट्री देने और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे पर्यटकों के बेरोकटोक आवागमन को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाते हुए वीकेंड पर हिल स्टेशनों में कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है।

चारधाम यात्रा मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला देते हुए किसी तरह का आदेश पारित करने से मना कर दिया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से चारधाम के गर्भगृह से पूजा अर्चना की लाइव स्ट्रीमिंग को शास्त्र सम्मत नहीं होने का जिक्र किया गया तो कोर्ट ने कहा कि उस शास्त्र की जानकारी दो। साथ ही कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग के मामले में चारधाम देवस्थानम बोर्ड के साथ बैठक कर पूजा अर्चना की लाइव स्ट्रीमिंग किए जाने को लेकर विचार करें। जब महाभारत में कुरुक्षेत्र से राजा धृतराष्ट्र के लिए संजय ने युद्ध की लाइव स्ट्रीमिंग की थी तो सरकार क्यों नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि देश संविधान व कानून से चलता है, धर्मग्रंथों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है।

दैनिक जागरण की खबरों पर लिया संज्ञान: बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल, अनु पंत, डीके जोशी तथा अधिवक्ता सुहास रतन जोशी की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दैनिक जागरण के बुधवार सात जुलाई के अंक में प्रकाशित वीकेंड पर बिना मास्क लगाए पर्यटकों की नौकायन करती तथा पंत पार्क में बिना मास्क लगाए पर्यटकों की भीड़ के फोटो तथा इससे संबंधित समाचार का संज्ञान लेते हुए सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि नैनीताल प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। माल रोड में भी कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने कहा कि कोविड कर्फ्यू में ढील देने के बाद पर्यटन स्थलों में खासकर वीकेंड पर भीड़ उमड़ रही है। एसओपी धराशायी हो गई है। पर्यटक न मास्क पहन रहे हैं, ना शारीरिक दूरी का अनुपालन कर रहे हैं।

पर्यटक करें एसओपी का पालन, नहीं तो बरती जाएगी सख्ती : जयराम

जागरण संवाददाता, मंडी : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कोविड-19 के मामलों में कमी आने व मैदानी भागों में गर्मी बढ़ने से देशभर के पर्यटकों ने हिमाचल का रुख किया है। पर्यटकों का हिमाचल में स्वागत है, मगर पर्यटक जिस तरह से पर्यटन स्थलों में भीड़ बढ़ा रहे हैं, वह चिंता का विषय है। पर्यटकों को कोविड एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) का पालन करना होगा, नहीं तो सरकार सख्ती बरतेगी।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 12 करोड़ डोज मिलेंगी

नई दिल्ली, एएनआइ : कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण को गति देने में जुटी केंद्र सरकार जुलाई में केंद्र और केंद्र शासित राज्यों को वैक्सीन की 12 करोड़ डोज उपलब्ध कराएगी। इनमें से अब तक 2.19 करोड़ डोज की आपूर्ति की जा चुकी है। इनको मिलाकर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कुल 37.43 करोड़ डोज दिए हैं, जिनमें से 1.67 करोड़ डोज इनके साथ ही निजी अस्पतालों के बची हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वैक्सीन उत्पादकों के साथ हुई बातचीत के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों बता दिया गया है कि इस महीने उन्हें कुल 12 करोड़ डोज दी जाएंगी।

मंत्रालय ने कहा है कि हर राज्य को पहले ही सूचना दे दी जाती है कि उसे किस महीने में कितनी डोज मिलेंगी। इसके अलावा राज्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि अगर उन्हें ज्यादा डोज की जरूरत हो तो उसके बारे में जानकारी दे दें।

मंत्रालय ने इन खबरों को भी खारिज किया है कि जुलाई के पहले हफ्ते में उसके पहले के हफ्ते की तुलना में टीकाकरण में 32 फीसद की गिरावट आई है। मंत्रालय के मुताबिक राज्यों को बहुत पहले ही बता दिया गया था कि निजी अस्पतालों समेत उन्हें जुलाई में कितनी डोज मिलेंगी, ताकि उसी हिसाब से वो अपनी टीकाकरण की योजना बना सकें।

कोवैक्स के जरिये भारत को 30-40 लाख डोज मिलेंगी

समाचार एजेंसी रायटर के मुताबिक भारत को कोवैक्स व्यवस्था के जरिये अगस्त तक अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और माडर्ना की 30 से 40 लाख डोज मिलने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि वैश्विक वैक्सीन संगठन गवी के नेतृत्व वाले कोवैक्स के माध्यम से भारत को अनुदान के रूप में ये वैक्सीन मिलेंगी।

दावा

आयुष मंत्रालय ने कहा, लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है गिलोय, मेडिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन को अधूरा और तथ्यहीन बताया

गिलोय से लिवर को नहीं होता है नुकसान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना संक्रमित को गिलोय देने के कारण लिवर खराब होने की रिपोर्ट को आयुष मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। आयुष मंत्रालय ने जर्नल आफ क्लीनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेपैटोलाजी में छपे अध्ययन को अधूरा और भ्रामक करार दिया है। हालांकि, आयुष मंत्रालय ने जर्नल और अध्ययन करने वाले डाक्टरों से संपर्क कर सफाई मांगने और खंडन छापने के लिए मजबूर करने के बजाय सिर्फ मीडिया की खबर के आधार पर बयान जारी कर दिया है। आयुष मंत्रालय के इस रवैये से आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की मोदी सरकार की कोशिशों को धक्का लग सकता है।

दरअसल मुंबई में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों पर किए गए अध्ययन में यह दावा किया गया है कि जिन मरीजों के गिलोय दी गई थी, उनके लिवर में खराबी पाई गई। यही नहीं, उनमें से एक मरीज की मौत भी हो गई। आयुष मंत्रालय ने इस निष्कर्ष पर आपत्ति जताते हुए कहा कि स्टडी के लिए तय मापदंडों का पालन नहीं किया गया। इसमें यह साफ नहीं किया गया है कि जिन मरीजों के लिवर में खराबी पाई गई थी, उन्हें गिलोय के साथ-साथ और कौन-कौन सी दवाएं दी गईं थी। यही नहीं, निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले आयुर्वेद के विशेषज्ञ की राय भी नहीं ली गई।



आयुष मंत्रालय का दावा गिलोय आयुर्वेद में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटी। फाइल फोटो

आयुष मंत्रालय ने दावा किया कि गिलोय के लिवर पर दुष्प्रभाव के बजाय सैकड़ों ऐसी स्टडी मौजूद हैं, जो यह साबित करती हैं कि गिलोय लिवर के लिए फायदेमंद है। मंत्रालय के अनुसार गिलोय आयुर्वेद में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटी है और लिवर को सुरक्षित करने के इसके गुण के वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। इसके बावजूद एक अधूरी स्टडी के आधार पर गिलोय को लिवर के लिए खतरनाक बताना भ्रामक है।

आयुष मंत्रालय के अनुसार यह भी स्पष्ट नहीं है कि स्टडी में जिस टीसी की बात कही गई है, वह गिलोय ही है। दरअसल टिनोसपोरोक्रिस्पा भी दिखने में गिलोय जैसा लगता है। लेकिन इसका लिवर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आयुष मंत्रालय ने आशंका जताई कि मरीजों को जो दवा दी गई थी, उसमें गिलोय के स्थान पर टिनोसपोरोक्रिस्पा का इस्तेमाल किया गया होगा।

मंत्रालय के बयान पर भी उठे सवाल: वैसे स्टडी करने वाले डाक्टरों और उसे प्रकाशित करने वाले जर्नल से संपर्क कर सफाई मांगे बिना आयुष मंत्रालय का बयान जारी करना कई सवाल खड़ा करता है। आयुष मंत्रालय को स्डटी को सबूतों के आधार पर चुनौती देते हुए जनरल को इसका खंडन प्रकाशित करने के लिए मजबूर करना चाहिए।

डीएम की डांट से आहत एसीएमओ ने दिया इस्तीफा

संसू, गोंडा : मंगलवार की शाम को कोविड समीक्षा बैठक में आपत्तिजनक टिप्पणी व डांट के मामले ने बुधवार को तूल पकड़ लिया। आहत एसीएमओ डा. एपी सिंह ने जिलाधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। यह पत्र उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के वाट्सएप ग्रुप पर भी वायरल किया है।

एसीएमओ डा.एपी सिंह ने बताया कि मंगलवार की शाम को बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलसर की समीक्षा के दौरान सैंपलिंग कम होने पर डीएम ने उनसे कहा कि क्यों न एसीएमओ को वहां का प्रभारी चिकित्साधिकारी बना दिया जाए। एसीएमओ के मुताबिक इससे पूर्व जिलाधिकारी ने उनका मनोबल तोड़ने के लिए कई आपत्तिजनक शब्द भी कहे हैं। निगरानी समिति के पास मेडिकल किट की समीक्षा के दौरान डीएम ने प्रमाण पत्र मांगा। इस पर दिए गए स्पष्टीकरण पर नाखुशी जताते हुए डीएम ने डांटते हुए उन्हें चुप करा दिया। डीएम के व्यवहार से आहत होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

कोरोना के दौर में 41.7 फीसद बच्चे अवसाद से पीड़ित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ स्कूल व खेलकूद बंद होने से मानसिक स्वास्थ्य हुआ प्रभावित, करीब हर पांचवें बच्चे में देखा गया डर

कोरोना से बच्चे भले ही शारीरिक रूप से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं लेकिन उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर देखा गया है। एम्स के डाक्टरों द्वारा किए गए समीक्षात्मक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कोरोना के कारण 41.7 फीसद बच्चे अवसाद से पीड़ित हुए। वहीं 22.5 फीसद बच्चे गंभीर रूप से डरे सहमे रहे। इस वजह से 21.3 फीसद बच्चों में नींद नहीं आने की परेशानी देखी गई। इस तरह करीब हर पांचवें बच्चे में कोरोना का डर देखा गया। कुछ बच्चों में नींद नहीं आने की परेशानी देखी गई।

एम्स के पीडियाट्रिक विभाग के प्रोफेसर डा. शेफाली गुलाटी के नेतृत्व में यह अध्ययन किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में बच्चों की मानसिक अवस्था पर भारत सहित दुनिया भर में हुए 15 अध्ययनों में शामिल 22,996 बच्चों का डाटा खंगाल कर यह अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि कोरोना के कारण 79.4 फीसद बच्चों के व्यवहार में नकारात्मक भाव आया। स्कूल बंद होने से बच्चे घर में कैद होकर रह गए। उनका बाहर खेलकूद भी बंद हो गया। अध्ययन में पाया गया कि बच्चों के 52.3 फीसद अभिभावक घबराहट व 27.4 फीसद अभिभावक अवसाद से पीड़ित हुए। क्योंकि घर में घबराहट व डर का माहौल था। इसका असर भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा। लिहाजा 34.5 फीसद बच्चों में घबराहट देखी गई। करीब 42.3 फीसद बच्चे चिड़चिड़े रहने लगे। इस वजह से 30.8 फीसद बच्चों में ध्यान भटकाव की समस्या देखी गई है। आटिज्म जैसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों में मानसिक परेशानी अधिक देखी गई। लिहाजा बच्चों की विशेष देखभाल की जरूरत है।

खुदरा और थोक कारोबार एमएसएमई में अधिसूचित

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने खुदरा और थोक कारोबार को एमएसएमई सेक्टर में अधिसूचित कर दिया है। इससे थोक व खुदरा कारोबारियों को भी कर्ज के लिहाज से प्राथमिक सेक्टर के फायदे मिलने लगेंगे। एमएसएमई मंत्रालय ने दो जुलाई को थोक और खुदरा कारोबार को एमएसएमई सेक्टर में शामिल कर लिया था। हालांकि यह सुविधा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत मिलने वाले फायदों तक सीमित रहेगी। (प्रेट्र)



देश ने कारोबार की सुगमता के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे कई मौजूदा नियमों को सरल और औचित्यपूर्ण बनाने में मदद मिली है।
– पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री

सेंसेक्स	53,054.76	▲ 193.58
निफ्टी	15,879.65	▲ 61.40
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 46,903	▼ ₹29
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹68,560	▼ ₹762
डॉलर	₹74.62	▲ ₹0.07
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 75.75	

सहकारिता को क्षेत्रीय विकास का वाहक बनाएगा नवगठित मंत्रालय

सहकार से समृद्धि : गांव, गरीब, किसान, मछुआरे और उपभोक्ता होंगे सशक्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की तर्ज पर सरकारिता मंत्रालय का गठन किया है। यह सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने को एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। निचले स्तर के सहकार सदस्य किसान, बुनकर मछुआरे और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने में सरकार का यह फैसला अहम साबित होगा।

नवगठित सहकारिता मंत्रालय के दायरे में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सेंट्रल रजिस्ट्रार, सहकारी शिक्षण व प्रशिक्षण के साथ सहकारिता संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे। कृषि मंत्रालय के अधीन चल रहे सहकारिता क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखने को अभी कोई संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी तक नियुक्त नहीं है, जबकि देश में आठ लाख सहकारी



बुनकर, डेयरी क्षेत्र, हाउसिंग, स्वास्थ्य व बीमा क्षेत्र में सहकारी संस्थाएं आगे बढ़कर काम कर पाएंगी● फाइल फोटो

संस्थाओं के 40 करोड़ सदस्य हैं। राज्यों में अलग-अलग कानून और नियमों के चलते सहकारिता आंदोलन अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहा है। यही वजह है कि कई राज्यों में सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है। उसे लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस तरह की गड़बड़ियों को दूर करने को संसद से पारित संविधान संशोधन पारित किया गया। इसके मुताबिक सभी राज्यों को इसके अनुसार ही अपनी कार्यप्रणाली रखनी पड़ेगी।

नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआइ) के प्रेसिडेंट दिलीप संघानी का कहना है कि इससे सहकारिता नई ऊंचाई हासिल करेगी। देश में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल बहुत प्रासंगिक है, जहां प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 14,000 से अधिक सहकारी बैंकों की शाखाएं काम कर रही हैं, जो स्थानीय ग्राहकों की जरूरतें पूरी करती हैं।

सहकारी क्षेत्र की फर्टिलाइजर कंपनी कृभको के चेयरमैन डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार की इस पहल से सहकारिता से जुड़ी आबादी का भला होगा। लोगों के जीवन-स्तर में सुधार होगा। देश के लाखों महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी करोड़ों महिलाओं को सहकारी आंदोलन का लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक की आपूर्ति के साथ सहकारी बैंकों से रियायती दर पर कृषि कर्ज प्राप्त होता है। समर्थन मूल्य पर उनकी उपज की सरकारी खरीद, उपभोक्ताओं को खाद्यान्न व अन्य जरूरी वस्तुओं का वितरण करने में सहकारी संस्थाएं और कारगर साबित होंगी। बुनकर, मछुआरे, डेयरी क्षेत्र, हाउसिंग, श्रम, स्वास्थ्य व बीमा क्षेत्र में सहकारी संस्थाएं आगे बढ़कर काम कर पाएंगी।

अलग मंत्रालय से सहकारी बैंकों व अन्य संबंधी संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। नया मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए कारोबार में सुगमता लाने का काम करेगा। साथ ही यह प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और एक से अधिक राज्य में काम कर रही सहकारी समितियों के विकास का मार्गप्रशस्त करेगा।

पहली बार 53,000 के ऊपर बंद हुआ बीएसई सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र : जून के कमजोर जीएसटी संग्रह आंकड़ों के बावजूद बुधवार को बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स पहली बार 53,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर बंद हुआ। मेटल, फाइनेंस और बैंकिंग स्टॉक्स में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। इससे सेंसेक्स 193.58 अंकों यानी 0.37 फीसद सुधार के साथ 53,054.76 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक निफ्टी 61.40 अंक यानी 0.39 फीसद मजबूत होकर 15,879.65 के नए रिकॉर्ड पर स्थिर हुआ।

शेयर बाजारों में दिन के कारोबार की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी। कुछ ही समय में यह अस्थिरता खत्म होती दिखी और फाइनेंस व बैंकिंग सेक्टर में निवेशक लौटते दिखे। सेंसेक्स पैक में बुधवार को सर्वाधिक 4.38% बढ़त टाटा स्टील के शेयरों में दर्ज की गई। बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी, एशियन पेंट्स, सन फार्मा व पावरग्रिड के शेयरों में भी अच्छी मजबूती आई।

दिल्ली में भी पेट्रोल 100 रुपये के पार

जेएनएन, नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमत पर दबाव जारी है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल का दाम 35 पैसे और डीजल का 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया। इसके बाद दिल्ली भी उन महानगरों की सूची में शामिल हो गई है, जहां पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है।

इस वर्ष चार मई के बाद से बुधवार तक 36वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पेट्रोल कुल 9.81 रुपये लीटर महंगा हुआ है। उससे पहले बंगाल और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण 18 दिनों तक दाम नहीं बढ़े थे। इसी अवधि में डीजल का दाम 34 बढ़ाया गया और यह 8.80 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है।

ताजा बढ़ोतरी के साथ नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 100.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल की 89.53 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे में पेट्रोल का भाव 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर चुका है। कोलकाता में भी बुधवार को ही पेट्रोल 100 रुपये लीटर से अधिक हो गया। वहां अब पेट्रोल की कीमत अब 100.23 रुपये लीटर पर पहुंच गई है।

35 पैसे पेट्रोल की और 17 पैसे प्रति लीटर डीजल की बढ़ी कीमत

36 बार दाम बढ़ा है चार मई से अब तक पेट्रोल का

34 बार दाम बढ़ाया जा चुका है डीजल का इस दौरान

9.81 रुपये लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल चार मई से

8.80 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है डीजल इसी अवधि में



राज्यों में स्थानीय शुल्क और सेस की वजह से दामों में अंतर आता है ● फाइल फोटो

बुधवार की बढ़ोतरी के बाद मुंबई में पेट्रोल 106.25 रुपये लीटर और चेन्नई में 101.06 रुपये लीटर पर पहुंच गया है। पिछले दिनों तेल निर्यातकों संगठन (ओपेक) और सहयोगी देशों द्वारा अगले महीने से मासिक उत्पादन में 4,00,000 बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव टाल दिया गया है। भारत के लिए ईरान से ऑयल खरीदना संभव नहीं हो रहा है क्योंकि वह फिलहाल अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का करीब 85 फीसद आयात के जरिये पूरा करता है।

राज्यों में स्थानीय शुल्क और सेस की वजह से पेट्रोल-डीजल के दामों में अंतर आता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, बिहार, पंजाब, लद्दाख, सिक्किम और पुडुचेरी में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है। देश में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला ईंधन डीजल राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर 100 रुपये से ऊपर है।

लोक उद्यम विभाग अब वित्त मंत्रालय का हिस्सा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकारी कंपनियों के विनिवेश में तेजी लाने के लिए पब्लिक इंटरप्राइजेज (लोक उद्यम) विभाग को वित्त मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया है। अब तक यह भारी उद्योग मंत्रालय का हिस्सा था। अब वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक संपदा विभाग को किसी उपक्रम के विनिवेश के लिए अलग से लोक उद्यम विभाग से मंजूरी नहीं लेनी होगी।

वित्त मंत्रालय का हिस्सा बनने से सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सरकार ने पिछले वर्ष ही 34 सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की घोषणा की थी, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है।

इस साल बजट के दौरान वित्त मंत्री ने सार्वजनिक उपक्रमों की संपदाओं के मुद्रीकरण एवं विनिवेश पर विशेष बल दिया था।

चालू वित्त वर्ष में सरकार ने विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार विनिवेश के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई थी। कई उपक्रमों के न्यायिक विवाद में फंस जाने की वजह से भी उनका विनिवेश कार्यक्रम अटक गया है। चालू वित्त वर्ष में सरकार देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी एलआइसी का आइपीओ लाने जा रही है।

वहीं, वह आइडीबीआइ बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाने वाली है। चालू वित्त वर्ष में एयर इंडिया, पवन हंस, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कारपोरेशन जैसे उपक्रमों के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है।

एयरबस इंडिया को देना होगा 18 फीसद जीएसटी

नई दिल्ली, प्रेट्र : अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने एक फैसले में कहा है कि एयरबस इंडिया ने फ्रांस स्थित होल्डिंग कंपनी को जो तकनीकी सलाहकार और खरीद सेवाएं मुहैया कराई हैं, उन्हें इंटरमीडियरी सर्विस माना जाएगा। ऐसी सेवाओं के लिए कंपनी को 18 फीसद की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। एयरबस ग्रुप इंडिया ने एएआर की कर्नाटक पीठ में एक अपील दाखिल की थी। कंपनी ने पूछा था कि क्या उसकी होल्डिंग कंपनी एयरबस इंवेस्ट एसएएस, फ्रांस को दी जाने वाली सेवाएं जीएसटी कानून के तहत सेवा के निर्यात के रूप में मान्य होंगी। एयरबस ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फ्रांस स्थित एयरबस इन्वेस्ट एसएएस की एक सहायक कंपनी है। एयरबस, एसई नीदरलैंड इसकी अंतिम होल्डिंग कंपनी है।

प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीतियों से छोटे कारोबारी असहज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : एमएसएमई सेक्टर का एक बड़ा वर्ग ई-कॉमर्स को लेकर उपभोक्ता मंत्रालय की प्रस्तावित नीतियों के पक्ष में नहीं दिख रहा है। इस वर्ग के छोटे-मझोले कारोबारियों का कहना है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे देशभर में अपने सामानों की बिक्री कर सकते हैं। नए नियम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कारोबार प्रभावित होने की स्थिति में उनके सीधे नुकसान की आशंका है। एमएसएमई फोरम ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है।

इन कंपनियों के अनुसार गांवों व शहरों में सैकड़ों ऐसे छोटे उद्यमी एवं कारोबारी हैं जिनके पास अपने उत्पाद की मार्केटिंग करने या अपनी दुकान शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से गांवों के बुनकर, हस्तशिल्प निर्माता एवं छोटे कारोबारी अच्छी कमाई कर रहे हैं। प्रस्तावित नए नियमों से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हतोत्साहित होने की आशंका है जिससे ये इन छोटे कारोबारियों का विकास थम सकता है। प्रस्तावित नियमों में फ्लैश सेल व डिस्काउंट जैसे प्रविधान पर अंकुश की बात की गई है, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होने वाली बिक्री को प्रभावित करेगी।



प्रस्तावित नए नियमों में फ्लैश सेल और डिस्काउंट जैसे प्रविधान पर अंकुश की बात की गई है● फाइल फोटो

बिजली वितरण कंपनियों को राहत

नई दिल्ली, आइएएनएस : बिजली वितरण कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्हें 25 वर्ष से पुरानी बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ किया गया करार तोड़ने की छूट दे दी है। इस बारे में बिजली मंत्रालय ने सभी राज्यों और सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशंस (सीजीएस) को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि बिजली खरीद करार (पीपीए) के तहत बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को उन उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीद का पूरा करार तोड़ने की पात्रता हासिल है, जो अपने परिचालन के 25 वर्ष पूरे कर चुकी हों।

मंत्रालय ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि अगर वितरण कंपनियां चाहें, तो लंबी अवधि के करार की शर्तों के तहत बिजली खरीद से मना करने के प्रथम अधिकार का उपयोग कर सकती हैं और चाहें तो खरीद जारी भी रख सकती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 बैंकों पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने 14 बैंकों पर कुल 14.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर विभिन्न नियामकीय उल्लंघनों का आरोप है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ), बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक के अलावा 10 अन्य बैंक शामिल हैं।

आरबीआइ के अनुसार नियमों के उल्लंघन में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को कर्ज से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं।

इनन बैंकों में सबसे अधिक दो करोड़ रुपये का जुर्माना बीओबी पर लगाया गया है। आरबीआइ के बयान में कहा गया है कि बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुइस एजी,

इनमें एसबीआइ, बीओबी, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक के अलावा 10 अन्य बैंक शामिल

इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करुर वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक-एक करोड़ रुपये और एसबीआइ पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने कहा कि एक समूह की कंपनियों के खातों की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि बैंक कुछ प्रविधानों का अनुपालन करने में विफल रहे। बैंकों को इस बारे में नोटिस भी जारी किया गया था।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

इसरो जासूसी कांड में अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली

तिरुअनंतपुरम : इसरो जासूसी मामले में अदालत ने बुधवार को केरल के पूर्व डीजीपी सीबी मैथ्यूज की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए टाल दी। सीबीआइ ने पूर्व डीजीपी समेत 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसरो के पूर्व विज्ञानी नंबी नारायणन व अन्य के खिलाफ साजिश रचने पर गिरफ्तार किया था। (प्रेट्र)

पैंगोलिन वेचने के लिए ग्राहक तलाशते हुए चार दबोचे गए

महासमुंद : साइबर सेल और पुलिस दुर्लभ वन्यजीव पैंगोलिन (वज्रशल्क) को बेचने के लिए ग्राहक तलाशते चार आरोपितों खोमन दीवान, ओमप्रकाश थवाइत, रमेश मिश्रा और डागेश्वर साहू को गिरफ्तार किया। एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि खल्लारी थाना क्षेत्र के बोइरगांव चौक के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान चारों पकड़े गए। (नईदुनिया)

उत्तराखंड में आनंद मैरिज एक्ट लागू करने के लिए याचिका

नैनीताल : उत्तराखंड में सिख धर्म में आनंद विवाह अधिनियम को लागू करने व इसके क्रियान्वयन को लेकर ढांचा तैयार करने की मांग करती जनहित याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 11 अगस्त को है। (जासं)

दुधवा की टीम ने बाघ के दांत के साथ तस्कर को पकड़ा

पीलीभीत : दुधवा टाइगर रिजर्व की टीम ने बाघ के अंगों की तस्करी में एक आरोपित राजकुमार उर्फ लल्ला को पकड़ा है। वह हजारा क्षेत्र का रहने वाला है। नेशनल पार्क टीम को सूचना मिली थी कि लखीमपुर खीरी के पलियाकलां नगर में तस्करी का माल बेचा जाएगा। (जासं)

अंटीलिया मामले में आरोपित ने हिरासत को बताया 'गैर कानूनी'

मुंबई, : उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर (अंटीलिया) के पास विस्फोटक लदी कार खड़ी करने व मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपित मनीष सोनी ने जमानत अर्जी दाखिल करते हुए न्यायिक हिरासत को 'गैर कानूनी' बताया है। (प्रेट्र)

खडसे के दामाद गिरीश ईडी की गिरफ्त में

राज्य ब्यूरो, मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खडसे के दामाद गिरीश चौधरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धाराओं के तहत पुणे के एक जमीन घोटाला मामले में हुई है। यह मामला उस समय का है जब खडसे भाजपा की देवेंद्र फड़नवीस सरकार में राजस्व मंत्री थे।

स्थानीय अदालत ने 12 जुलाई तक हिरासत में भेजा, मंगलवार को हुई थी 13 घंटे तक पूछताछ

ईडी के अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार सुबह गिरीश चौधरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। देर शाम तक चली करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक स्थानीय अदालत ने गिरीश को 12 जुलाई तक ईडी हिरासत में भेज दिया। बता दें कि एकनाथ खडसे भाजपा के बहुत वरिष्ठ ओबीसी नेता रहे हैं। उन्हें दिवंगत गोपीनाथ मुंडे का करीबी माना जाता है। फड़नवीस सरकार में वह करीब दो साल राजस्व मंत्री रहे। उसी दौरान पुणे के भोसरी क्षेत्र स्थित महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एमआइडीसी) का एक भूखंड खरीदने के मामले में उन पर अनियमितता का आरोप लगा था। हेमंत गावंडे नामक व्यक्ति ने खडसे पर सरकारी खजाने की लूट का आरोप लगाया था। 2017 में खडसे के साथ-साथ उनकी पत्नी मंदाकिनी, दामाद गिरीश चौधरी और जमीन के मालिक अब्बास अकानी के विरुद्ध महाराष्ट्र की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने मामला दर्ज किया था।



मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खडसे के दामाद गिरीश चौधरी। प्रेट्र

खडसे की सफाई थी कि यह जमीन उनकी पत्नी ने खरीदी है। इस सौदे से उनका कोई लेना-देना नहीं है। खडसे के अनुसार, इस मामले में चार बार उनकी जांच हो चुकी है। उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है। हालांकि आरोप लगने के बाद उन्हें फड़नवीस सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। 2018 में एसीबी ने उन्हें क्लीनचिट दे दी थी। लेकिन ईडी की जांच जारी रही। खडसे से भी ईडी ने इसी साल जनवरी में पूछताछ की थी। उस समय तक वह भाजपा छोड़कर राकांपा में जा चुके थे। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि राकांपा में जाने के कारण केंद्रीय एजेंसी उन्हें परेशान कर रही है। हाल में ईडी ने कोर्ट को बताया था कि जमीन सौदे में खडसे आरोपित नहीं हैं, लेकिन वह पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए गिरफ्तारी की तलवार एकनाथ खडसे पर भी लटक रही है। महाविकास अघाड़ी की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों के जरिये हमारे नेताओं को परेशान कर रही है।

चीन के हैकरों ने स्टेट बैंक के खाताधारकों को बनाया निशाना

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय स्टेट बैंक और उसके खाताधारकों के लिए चीन के हैकरों ने मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की है। हैकर ने खाताधारकों को एक खास वेबसाइट पर जाकर अपना केवाईसी अपडेट करने के लिए मैसेज भेजा। इसके बदले में हैकर ने खाताधारकों को 50 लाख रुपये तक के उपहार देने का झांसा दिया। इसके बाद तो उक्त वेबसाइट पर जाकर अपनी केवाईसी से संबंधित गोपनीय सूचनाएं देने वालों की लाइन लग गई। जब बैंक और अन्य एजेंसियों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने खाताधारकों को इससे जुड़े खतरों के लिए आगाह किया।

नई दिल्ली की संस्था साइबरपीस फाउंडेशन और ऑटोबोट इन्फोसेक प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार स्टेट बैंक ने हाल के दिनों में ऐसे दो हमले झेले हैं। इनमें ज्यादातर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले खाताधारक निशाने पर आए। ऐसे खाताधारकों के पास वाट्सएप के जरिये केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आया। इसके साथ एसबीआइ का ऑनलाइन पेज भी था। मैसेज में ऑनलाइन पेज पर लिखे कंटीन्यू टू लॉगिन बटन को क्लिक कर केवाईसी अपडेट करना था। यहां पर खाताधारक से सामान्य सूचनाओं के साथ यूजरनेम और पासवर्ड जैसी गोपनीय सूचनाएं भी मांगी गईं और कैप्चा के इस्तेमाल से उन्हें फारवर्ड भी कराया गया। इसके बाद ओटीपी भेजकर सारी सूचनाओं को अन्य पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए कहा गया। तमाम खाताधारक समझे कि केवाईसी अपडेट करने के लिए स्टेट बैंक ने ही कोई उपहार योजना निकाली है, इसलिए वे मैसेज के जाल में फंस गए। शोधकर्ताओं को जांच में पता चला कि स्टेट बैंक के नाम का इस्तेमाल कर चीन के हैकरों ने खाताधारकों से उनकी सूचनाएं ले लीं, जिनका किसी अन्य स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेट बैंक ने इस हैकिंग पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है।

ठगी
- केवाईसी अपडेट करने के नाम पर फर्जी वेबपेज पर ले लीं खाताधारकों की सूचनाएं
- उपहार योजना के नाम पर लोगों को जाल में फंसाया, हैक किया फोन

अपने खिलाफ कार्यवाही रद कराने डोमिनिका हाई कोर्ट पहुंचा चोकसी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने रोसो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि डोमिनिका में गैरकानूनी प्रवेश के मामले में उसकी गिरफ्तारी भारत सरकार के प्रतिनिधियों के कहने पर हुई थी। याचिका में उसने अपने खिलाफ जारी कार्यवाही को रद किए जाने की मांग की है।



घोटालेबाज : मेहुल चोकसी। फाइल फोटो

डोमिनिका के स्थानीय मीडिया के मुताबिक, याचिका डोमिनिका के आव्रजन मंत्री, उसके पुलिस प्रमुख और मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ दाखिल की गई है। डोमिनिका में 23 मई को गैरकानूनी प्रवेश के बाद वहां के आव्रजन मंत्रालय ने चोकसी को प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित कर दिया था। चोकसी का आरोप है कि सभी ने तीसरे पक्ष यानी भारत सरकार के प्रतिनिधियों के कहने पर काम किया।

अपने खिलाफ कार्यवाही रद करने की मांग करते हुए चोकसी ने हाई कोर्ट में दलील दी कि गैरकानूनी प्रवेश के लिए उस पर आरोप लगाने का फैसला कानून के खिलाफ और अमान्य है। उसने कहा कि वह एंटीगुआ और बरबुडा का नागरिक है जहां उसने खुद के संभावित प्रत्यर्पण को चुनौती दे रखी है। उसने दावा किया कि एंटीगुआ और बरबुडा से उसका अपहरण करके भारतीय लोगों द्वारा जबरन डोमिनिका लाया गया था। चोकसी ने कहा कि उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में डोमिनिका पुलिस को बताया भी था, लेकिन उन्होंने उसके आरोपों की कोई जांच नहीं की।

3.200 किलो हेरोइन और 40 लाख की ड्रग मनी समेत छह तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, होशियारपुर : दिल्ली से 17 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए चार अफगान नागरिकों से पूछताछ के बाद होशियारपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की टीमों ने छह और नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उसने 3.200 किलो हेरोइन व 40 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। आरोपियों की पहचान किशन लाल निवासी चांदनी चौक थाना लाहौरी गेट दिल्ली, अभय प्रताप सिंह पुत्र दशरथ सिंह निवासी बागवाली कालोनी शांति नगर थाना कवि नगर गाजियाबाद, इम्तयाज अहमद पुत्र मुमताज अहमद निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, इमरान पुत्र अली अहमद निवासी रामपुर, जसवीर सिंह पुत्र प्रकाश निवासी शेखुपुर मोहल्ला जंडियाला गुरु व बलविंदर सिंह पुत्र सज्जन सिंह निवासी जंडियाला गुरु के तौर पर हुई।

देशमुख के खिलाफ अपनी जांच का दायरा बढ़ाए सीबीआइ : हाई कोर्ट

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा, उसे उम्मीद है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दायर एफआइआर के सिलसिले में सीबीआइ अपनी जांच का दायरा बढ़ाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि प्रशासन का प्रमुख निर्दोष होने का दावा नहीं कर सकता और वह समान रूप से जिम्मेदार है।

जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने कहा कि अगर हाई कोर्ट के पांच अप्रैल के आदेश को सही मायनों में देखा जाए तो हर व्यक्ति की भूमिका की जांच करनी होगी। पांच अप्रैल को हाई कोर्ट ने देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ सीबीआइ को प्रारंभिक जांच के आदेश दिए थे। अदालत देशमुख की उस याचिका पर

कहा, प्रशासन का प्रमुख नहीं कर सकता निर्दोष होने का दावा

सुनवाई कर रही थी जिसमें सीबीआइ द्वारा 24 अप्रैल को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप में दर्ज एफआइआर को रद करने की मांग की गई थी। यह एफआइआर हाई कोर्ट के आदेश पर की गई प्रारंभिक जांच के बाद दर्ज की गई थी।

पीठ ने कहा, 'जो भी प्रशासन का प्रमुख हो, यह कहकर निर्दोष होने का दावा नहीं कर सकता कि वह सिर्फ कार्यपालिका के आदेश का पालन कर रहा था। प्रशासन का प्रमुख भी समान रूप से जिम्मेदार है। मंत्री ने सचिन वाझे को बहाल करने के लिए कहा होगा, लेकिन क्या प्रमुख और शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए बगैर सिर्फ आदेशों का पालन कर सकता है।' जस्टिस शिंदे ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि सीबीआइ अपनी जांच का दायरा बढ़ाएगी। उम्मीद है कि सीबीआइ को पता चल गया होगा कि साजिशकर्ता कौन हैं।' पीठ ने कहा, अगर वाझे इतना ही खतरनाक व्यक्ति था तो उन्हें पुलिस में बहाल करने वाली समिति को भी आरोपितों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अदालत ने सवाल किया, 'अभी हम कोई नाम नहीं ले रहे हैं। 15 साल बाद इस इंस्पेक्टर (वाझे) को कितने बहाल किया?' सीबीआइ की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल अमन लेखी ने बताया कि जांच एजेंसी ने पता लगा लिया है कि साजिशकर्ता कौन हैं।

दैनिक जागरण
परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम है

प्रधानमंत्री की नई टीम

आखिरकार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार की प्रतीक्षा पूरी हुई। इस पहले बड़े विस्तार और साथ ही फेरबदल से यही स्पष्ट हुआ कि नए मंत्रियों के चयन में योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता देने के साथ ही क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का भी विशेष ध्यान रखा गया। लोकतंत्र में ऐसा करना आवश्यक होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार के साथ प्रधानमंत्री की टीम कहीं ज्यादा व्यापक आधार वाली और पहले से अधिक सक्षम दिखने लगी है। चूंकि मंत्रिपरिषद में सहयोगी दलों की भागीदारी के साथ ही युवा चेहरों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है इसलिए उसकी औसत आयु पहले से कम दिखने लगी है। खास बात यह भी है कि मंत्रिपरिषद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसके साथ ही वंचित एवं पिछड़े तबकों की भी हिस्सेदारी बढ़ी है। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री सोशल इंजीनियरिंग पर न केवल काम कर रहे हैं, बल्कि उसे बल भी प्रदान कर रहे हैं। यह उनके लिए अचरज का विषय हो सकता है, जो अभी भी भाजपा को पुराने चश्मे से देखने के अभ्यस्त हैं अथवा सामाजिक न्याय के नाम पर जातियों की गोलबंदी को ही सही मानते हैं।

मंत्रिपरिषद के विस्तार में कुछ पुराने मंत्रियों की पदोन्नति यह बताती है कि उन्हें उनके बेहतर काम का पुरस्कार मिला। यह मिलना भी चाहिए था, क्योंकि इससे सभी को यह संदेश जाता है कि बेहतर प्रदर्शन मायने रखता है, न कि मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर मौजूदगी। इसके बाद भी जिन अनेक मंत्रियों की छुट्टी की गई, उनमें से उनका बाहर होना आश्चर्यजनक है जो एक साथ कई मंत्रालय संभाले हुए थे और सरकार का चेहरा भी माने जाते थे। ऐसे मंत्रियों के बाहर होने को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब मिल सके तो बेहतर। चूंकि ऐसे मंत्रियों के बाहर होने का कारण स्पष्ट नहीं, इसलिए कयासबाजी होना स्वाभाविक है। यदि यह कारण स्पष्ट हो सके तो इससे पुराने और साथ ही नए मंत्रियों को संदेश और सबक ग्रहण करने में आसानी होगी। कुछ प्रमुख मंत्रियों को हटाए जाने का कारण जो भी हो, इसमें दो मत नहीं कि नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद को तेजी के साथ अपना काम करना होगा। यह इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि अब मोदी सरकार के कार्यकाल में तीन साल ही बचे हैं। इस शेष कार्यकाल में टीम मोदी को इसलिए और भी तत्परता दिखानी होगा, क्योंकि कोरोना ने बहुत सा समय बर्बाद करने के साथ ही मोदी सरकार के एजेंडे को जमीन पर उतारने में बाधाएं भी खड़ी कर दी हैं। इन बाधाओं को दूर करने में सफलता तभी मिलेगी, जब नए-पुराने मंत्री न केवल सरकार की, बल्कि आम जनता की अपेक्षाओं पर भी खरे उतरेंगे।

तस्करों पर नकेल जरूरी

गरीबी और अशिक्षा का विपरीत प्रभाव क्या हो सकता है, झारखंड में मानव तस्करी इसका उदाहरण है। पैसे की कमी के कारण परिवार को खिलाने-पिलाने, आगे बढ़ाने में परेशानी के कारण कई बार ऐसा फैसला ले लिया जाता है जो मुश्किल खड़ी कर देता है। कई बार स्वजनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहां बात उन बच्चों की हो रही है जिन्हें दलाल बहला-फुसलाकर दूसरे राज्यों में ले जाते हैं और उनका शोषण करते हैं। ऐसे बच्चों के अभिभावकों की गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाया जाता है। कुछ पैसे मिल जाने के लोभ में वो अपने बच्चों का एक तरह से सौदा ही कर देते हैं। हालांकि यह भी सही है कि सभी मामलों में उन्हें वस्तुस्थिति का पता नहीं होता। उनके बच्चों को काम मिल जाए, पैसे मिल जाएं, ठीक से पेट भर सकें-इसी संतोष का दलाल फायदा उठा लेते हैं। झारखंड का संताल परगना का इलाका आदिवासी बहुल है, आदिम जनजाति के लोग भी वहां रहते हैं जो भोले हैं और दुनियादारी से अनजान भी। गरीबी और अशिक्षा का यहां बोलबाला है। पिछले दिनों साहिबगंज में चार बच्चियों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया। मानव तस्कर दंपती इनको काम दिलाने के नाम पर चेन्नई ले जा रहे थे। तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। असल में मानव तस्कर दंपती इनको रांची ले जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। गश्ती पुलिस दल ने बच्चियों को देखा तो उनको शंका हुई। पूछताछ में दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। यह पहला मामला नहीं है। इस इलाके में कई बार बच्चियों, किशोरियों और युवतियों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है। यह अच्छी बात है कि साहिबगंज जिले में पुलिस सक्रिय है और हाल के दिनों में कई मानव तस्करों को गिरफ्तार कर किशोर-किशोरियों को मुक्त कराया गया है। पिछले साल जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी खोली गई है। मानव तस्करों पर नकेल को बेहद कड़ी कार्रवाई जरूरी है ताकि उनमें डर हो। संदेश जाए कि ऐसा किया तो अंजाम बुरा होगा।

> झारखंड के भोले-भाले आदिवासियों और आदिम जनजाति के बच्चों को फुसला कर उनकी तस्करी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए

आपसी झगड़े में उलझी कांग्रेस



प्रदीप सिंह

> जैसे नाव में छेद होने पर एक जगह से पानी रोको तो दूसरी जगह से आने लगता है, वैसा ही हाल कांग्रेस का हो रहा है

कहावत है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। कम से कम चार प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऐसा ही हो रहा है। जैसे नाव में छेद होने पर एक जगह से पानी रोको तो दूसरी जगह से आने लगता है, वैसा ही हाल कांग्रेस का हो रहा है। अचानक जैसे सब क्षत्रपों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। सबको पता चल गया है कि कांग्रेस हाईकमान में अब न तो कुछ हाई रहा है और न ही कमान। तीन लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पार्टी चलाने का उपक्रम कर रहे हैं, पर पार्टी आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रही है। वैसे कांग्रेस की यह हालत कोई अचानक नहीं हुई है। चुनाव दर चुनाव हार से पार्टी अशक्त हो गई है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उम्मीद नहीं रह गई है और सबसे बुरा होता है उम्मीद का मर जाना। जो और इंतजार करने को तैयार नहीं हैं, वे एक-एक करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जो रुके हुए हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्यों रुके हुए हैं? यदि भाजपा बंगाल जीत जाती तो अब तक कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ मच गई होती, पर अब भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है।

लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात हो गई। इससे पहले सिद्धू की राहुल गांधी और प्रियंका से लंबी बातचीत हो चुकी थी। कांग्रेस में चल क्या रहा है, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि राहुल और प्रियंका से मिलने के बाद कैप्टन पर सिद्धू के हमले रुकने के बजाय और बढ़ गए। सारा देश जानता है कि पंजाब में समस्या सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई है, पर सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कैप्टन बाहर आए तो सिद्धू के बारे में पूछने पर कहा कि उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। वह तो कांग्रेस अध्यक्ष से सरकार और राजनीतिक स्थिति पर बात करने आए थे। वह जो तय करेंगी, मानेंगे। मतलब यह कि गेंद अब सोनिया गांधी के पाले में है। समस्या यही है कि पूरा गांधी परिवार मिलकर कुछ तय नहीं कर पा रहा है। पिछले दो महीने में कांग्रेस के नेताओं ने कैप्टन सरकार की जितनी कमियां गिनाई हैं, उतनी तो समूचा विपक्ष भी नहीं गिना पाया। चार साल बाद पार्टी हाईकमान की नींद खुली और कैप्टन को कुछ दिन पहले तीन सदस्यीय कमेटी के मार्फत आदेश दिया गया कि चुनाव घोषणा पत्र के 18 मुद्दों पर सरकार काम करके बताए। अब जो काम सवा चार साल में नहीं हुआ, वह कुछ दिनों में हो जाएगा, ऐसे चमत्कार की उम्मीद कांग्रेसी ही कर सकते हैं। जबसे मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी बनी है, ऐसा लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सरकार नहीं चला रहे, बल्कि कोई मुकदमा लड़ रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस जीती हुई बाजी को हार में बदलने पर आमादा है।

पंजाब की गुत्थी सुलझी नहीं थी कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोर्चा खोल दिया। यहां सरकार नहीं है तो प्रदेश अध्यक्ष ही सही। प्रदेश अध्यक्ष सैलजा को हटाने का अभियान शुरू हो गया है। वह गांधी परिवार की पसंद हैं, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस विधायकों पर पार्टी हाईकमान का नहीं हुड्डा का हुकुम चलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव जिताकर वही लाए थे और वही फिर जिताने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए विधायक कह रहे हैं कि चुनाव जीतना है तो पार्टी की कमान हुड्डा को देनी पड़ेगी। हाईकमान की क्षमता नहीं है कि वह हुड्डा को रोक सके। रोकना चाहे भी तो हुड्डा रुकने वाले नहीं हैं।

राजस्थान में तो अशोक गहलोत का जादू का खेल चल रहा है। हाईकमान से मिलने की बात हो, उनके हरकारों से या असंतुष्टों से, मुख्यमंत्री को डाक्टर घर में रहकर आराम करने की सलाह दे देते हैं, पर राज्यपाल के पुस्तक विमोचन समारोह में जाने के लिए वह बिल्कुल चंगे हैं। सचिन पायलट को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वह किसके पास जाएं? वैसे टेलीफोन टैपिंग की तलवार गहलोत के सिर पर अभी तक लटकी ही हुई है। साथ में बहुजन समाज पार्टी के जिन छह विधायकों का कांग्रेस में विलय कराया था, उन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना है। वहां से झटका लगा तो जादूगर का जादू भी काम नहीं आएगा, पर एक बात तो है कि अशोक गहलोत को कैप्टन की तरह हाईकमान की कोई चिंता नहीं है।

साल 2018 में कांग्रेस को तीन राज्यों-राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दुर्लभ चुनावी सफलता मिली थी। इनमें से मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकर भाजपा के खेमे में चले गए। राजस्थान में नैया डगमग-डगमग कर रही है। सबसे मजबूत जनादेश छत्तीसगढ़ में मिला था। वहां नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री का फैसला बड़ी मुश्किल से हो पाया था। भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव इस बात पर माने थे कि ढाई साल बाद मुख्यमंत्री की गद्दी उन्हें मिलेगी। कहते हैं कि यह वादा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया था। अब राहुल गांधी तो सारी जवाबदेही से मुक्त हो चुके हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याददाश्त उन्हें धोखा दे रही है। उन्हें याद ही नहीं है कि ऐसी कोई बात भी हुई थी।

देश की सबसे पुरानी पार्टी की दुर्दशा का वर्णन करना कठिन है। अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, जो रिटायरमेंट से लौटकर आने को मजबूर हुईं। सिर्फ इसलिए कि बेटे के लिए पद को बचाए रख सकें। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, जो पार्टी चला रहे हैं, पर अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। प्रियंका वाड्रा हैं, जिनकी राजनीतिक उपलब्धि यह है कि महामंत्री के नाते उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला तो पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी परिवार का कोई सदस्य (राहुल गांधी) अमेठी से चुनाव हार गया। उनकी रहनुमाई में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अस्सी में से एक सीट मिली। इसके पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत बचाना मुश्किल हो गया। पंचायत चुनाव में पार्टी का हाल खोजते रह जाओगे वाला है, पर वे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का भविष्य तय करती हैं। फिल्म 'अमर प्रेम' में आनंद बख्शी का लिखा गीत है-चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए, उसे कौन बुझाए। तो कांग्रेस में सावन ही आग लगा रहा है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com



अवधेश राजपूत

हिंदी सिनेमा के एक युग का अवसान



यतीन्द्र मिश्र

> दिलीप साहब इस दुनिया से विदा हुए हैं, मगर भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं

दिलीप कुमार साहब से बेशुमार प्यार की ढेरों वजहें हैं। वह शाइस्तगी, नफासत से कौल कहने का अंदाज और जीवन में बाकमाल अभिनय की सात दशकों की लंबी पारी.. एक सिने पत्रिका से अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा था, 'मैं 'बांबे टॉकीज' में अशोक भईया को अभिनय करते हुए देखता रहता था। जब वह 'किस्मत' (1943) की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताईं, जो मेरी लिए दिशा-निर्देश बन गईं।' उन्होंने कहा, 'अभिनय, अभिनय न करना ही है। मैं जानता हूं यह हतोत्साहित करने वाला कथन है और आपको डराएगा, पर जब आप कैमरे का सामना करोगे, तो अपने आप समझ जाओगे।' यही सीख लेकर दिलीप कुमार सिनेमा के बेताज बादशाह बने। वे उस दौर में अंडरटोन का विचार आगे लेकर आए, जब सिनेमा थियेटर पर आधारित था। उनका संवाद बोलना और अपने फेशियल जेस्चर्स को संजीदगी से उभारना मिसाल बन गया। आज भी आप 'आजाद', 'कोहिनूर' और 'राम और श्याम' में उनकी सहज कॉमेडी, 'मेला', 'देवदास', 'अंदाज', 'आदमी' और 'फुटपाथ' की गंभीर अदायगी, 'मुगल-ए-आजम' का शहजादा, 'अमर' का प्रति-नायक, 'नदिया के पार', 'मधुमती' और 'आन' का दिलेर मस्तमौला उत्साही युवा, 'उड़नखटोला', 'दिल दिया दर्द लिया', 'गोपी' और 'सगीना महतो' के लीक से हटकर चरित्र, 'शक्ति' का असहाय पिता और 'विधाता', 'मशाल', 'कर्मा' और 'सौदागर' के लीजेंड बनने में यह सारी खूबियां देख सकते हैं।

जिंदगी में तीस का पड़ाव पार करने के दौरान ही ढेर सारी फिल्म में ट्रैजेडी रोल करते हुए वह संजीदा किरदारों के बड़े नायकों सर जॉन गिलगुड और सर लॉरेंस आलिवर से प्रभावित थे। जब वह 'देवदास' कर रहे थे, तो उन्हें अपने दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए इंग्लैंड में नाटक कोच की सहायता लेने की सलाह दी गई, जो बाद में उनके बड़े काम आई। उनसे कहा गया कि आपने इतनी संजीदा भूमिकाएं कर ली हैं, इसलिए अब कॉमेडी आजमानी चाहिए, जो आपको आराम देगी और अभिनय में विविधता लाएगी। इसके बाद उन्होंने 'आजाद' (1955) में काम किया और उसकी सफलता ने उन्हें हास्य की बेहतरीन समझ वाला नायक भी बना दिया।

जब मैंने पहली बार 'कोहिनूर' देखी थी, तभी से 'मधुबन में राधिका नाचे रे' पर उनकी सितार बजाने की अदायगी चकित करती थी। इसी तरह 'गंगा जमना' के लिए कहरवा पर नाचते 'नैन लड़ जइहें तो मनवा मा कसक होइबे करी' तो जैसे अवधी-भोजपुरी पट्टी के आम आदमी का सजीव उल्लास रचने वाला गीत बन गया। 'राम और श्याम' में वहीदा रहमान के लिए उनको गाते सुन लीजिए-आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले/कल तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा' या 'लीडर' में वैजयंती माला के प्रति 'तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं...?' तो उनके किरदार के प्रेम में आप आज भी उसी हरारत से पड़ जाएंगे, जब दो पीढ़ी पहले आपके दादा या नाना उनके मुरीद हुए होंगे। वह ऐसे इंसान थे, जिनका जीवन भी सतरंगी कहानियों से भरा पड़ा है। 'नया दौर' फिल्म के लिए अभिनेत्री मधुबाला के साथ हुआ उनका विवाद और मशहूर कोर्ट का किस्सा, अब जैसे 'लैला मजनू' की कहानी की तरह सुना-सुनाया जाता है। ये दिलीप कुमार द्वारा अभिनीत बेहतरीन फिल्मों का मामला है कि उनकी फिल्मों 'गंगा-जमना' से प्रेरित 'दीवार', 'नया दौर' से 'लगान' और 'मधुमती' से 'ओम शांति ओम' जैसी फिल्में बनीं।



जीवन काल में ही किंवदंती बन गए दिलीप कुमार। फाइल

दिलीप कुमार इन उल्लेखनीय फिल्मों, अपने जीवंत संवादों और सदाबहार गीतों पर सलोने रूमान का भरम रचते हुए खुद की शख्सीयत का इतना बड़ा मेयार रचते हुए हर एक हिंदुस्तानी के इतने अजीज हो जाएंगे, ये सिनेमा के इतिहास को आज से 99 साल पहले कहां पता था? पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार सईद अहमद ने उन पर किताब लिखते हुए यह बात उचित ही लक्ष्य की थी, 'कोई आरजू दिल में कैसे टूटती है और किसी ख्वाहिश का दीया कैसे बुझता है, यह सब कुछ हम उनके चेहरे पर पलक झपकते ही पढ़ लेते हैं।' उनकी छोटी बहन जैसी लता मंगेशकर जी ने मुझे बताया था कि अगर किसी अभिनेता के लिए उन्हें पार्श्वगायन करना होता, तो वह निश्चित ही दिलीप कुमार होते, क्योंकि उनसे बेहतरीन अदायगी उनके देखे नहीं मिलती। हालांकि, इन दोनों ने मिलकर सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में 'मुसाफिर' (1957) फिल्म में एक डुएट 'लागी नाहीं छूटे राम' गाया था। अब यह सब इतिहास और धरोहर है। दिलीप कुमार के महाकाव्यात्मक से बड़े जीवन के बारे में लिखते हुए हमें उनकी पत्नी सायरा बानो का भी सम्मान से उल्लेख करना चाहिए, जिन्होंने उनके जीवन को बड़े जतन से सहेजा। इन दोनों पर फिल्माया 'गोपी' (1970) का प्रणय गीत, जैसे उनकी मुहब्बत का कुबूलनामा है-'अकेले ही अकेले चला है कहां?/कहेगा क्या कहेगा ये मौसम जवां/हो नाजा नाजा, हो आजा आजा/ओ राही अलबेले/हमसफर भी कोई साथ ले ले...।'

दिलीप साहब इस फानी दुनिया से विदा हुए हैं, मगर भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। उनके करोड़ों मुरीद अब उनके योगदान को सीख की तरह दोहराते रहेंगे। पिछली सदी के पहले महानायकों की तिकड़ी 'राजकपूर, देवानंद और दिलीप कुमार' के युग का अवसान, हिंदी सिनेमा के लिए क्षति की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा को एक बड़ा मुकाम दिलाया है, जिससे सीखना और नई पीढ़ी को उसे सहेजना ज्यादा मानीखेज होगा। एक जहीन और जीवंत पटकथा, एक बुजुर्ग महानायक हमारे बीच किंवदंती बन चुका है। आज बेशक, शहजादा सलीम नहीं रहा, मगर उनको हमारी स्मृतियों से भला कौन रुखसत कर पाएगा? सलाम दिलीप साहब!

(लेखक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

आस्था और संदेह

देवत्व का भव्य भवन आस्था और विश्वास के मजबूत खंभों पर ही टिका होता है। भाव की पवित्रता से इस भवन में प्रवेश करने से न केवल मन का आस्थामय संसार सुदृढ़ होता है, बल्कि मन में विश्वास का स्वर भी गहराता है। इस भवन-परिसर में प्रवेश करते ही सांसारिक भौतिकता, संदेह, भ्रम, अनास्था और द्वेष के भाव स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। आस्था, भक्ति और सकारात्मकता के मार्ग में संदेह बहुत बड़ा अवरोध है। संदेह आस्था और विश्वास के दुर्ग को तहस-नहस कर देता है। यह पारस्परिक मैत्री, प्रेम, उपलब्धि, विकास, सौहार्द को भी समाप्त करने में भी देर नहीं लगाता। वैचारिक संशय मनुष्य के व्यक्तित्व को न केवल कमजोर और शिथिल बनाता है, बल्कि जीव को जीवन-विकास की मुख्यधारा से भटक जाने को भी विवश करता है। संदेह के रथ का सारथी बन व्यक्ति ऊहापोह, वितृष्णा, संशय, भटकाव और मन की अस्थिरता के साथ अज्ञान के जंगल में गुम हो जाने के लिए विवश होता है, लेकिन आस्था के रथ में पवित्रता के कवच से लैस हो वह आनंद के स्थायी लोक में निर्भय हो निवास करने के लिए स्वतः ही प्रेरित होता है। आस्था का रथ स्वयं प्रभु द्वारा संचालित होता है, जिसमें संदेह, भ्रम और नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं बचता।

मनुष्य रूपी सारथी का रथ अनेक बार चालाकियों और आसक्तियों के दलदल में धंसकर उसे कष्ट, पश्चाताप और पराजय का बोध कराता है, लेकिन प्रभु संचालित रथ मन और हृदय में शांति, आनंद और प्रेम की रचना कर जीवन को धन्य कर देता है। स्वयं को कर्ता और स्वामी भाव से किया गया कार्य अंततः पीड़ा देता है, जबकि प्रभु के नेतृत्व में स्वतः संपन्न हो रहे कार्य सभी को आनंदित करते हैं। अतः पवित्र भाव से प्रभु-भक्ति एवं आस्था के रथ में बैठकर आनंद के स्थायी लोक की सदस्यता ग्रहण करें, क्योंकि प्रदर्शन तो नश्वर और छलावा मात्र है, दर्शन का संसार ही आनंद देने वाला है।

प्रो. दिनेश चमोला 'शैलेश'

जीएसटी का बढ़ता दायरा

अजय कुमार राय

> जब कोई अर्थव्यवस्था संगठित रूप लेती है तो अप्रत्यक्ष कर के साथ-साथ प्रत्यक्ष कर का भी दायरा बढ़ता है। इससे देश को दोहरा फायदा होता है

कोई भी नई व्यवस्था अपने वास्तविक रूप में आने में समय लेती है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के साथ भी यही हो रहा है। एक जून, 2017 को अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार करते हुए देश में इसे लागू किया गया था। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्र और राज्यों के स्तर पर लगने वाले सभी 17 प्रकार के करों-शुल्कों को खत्म कर एक देश-एक कर की व्यवस्था लाई गई थी। तब से चार साल बीत चुके हैं, कर की अलग-अलग दरों को छोड़ दें तो अब तक इसका अनुभव सही रहा है।

इसमें दो मत नहीं कि जीएसटी व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से एक संगठित रूप दे रही है। जब कोई अर्थव्यवस्था संगठित रूप लेती है तो अप्रत्यक्ष कर के साथ-साथ प्रत्यक्ष कर का भी दायरा बढ़ता है। इससे देश को दोहरा फायदा होता है। चार वर्षों में करदाताओं का आधार 66.25 लाख से बढ़कर 1.28 करोड़ हो चुका है। इसके तकनीक आधारित होने से जो भी कर चोरी को अंजाम दे रहा है वह ऑडिट के दौरान आसानी से पकड़ में आ जा रहा है। अब अपने कारोबार को बिना इसके तहत पंजीकरण कराए किसी के लिए कामकाज करना संभव नहीं रह गया है। इससे हर स्तर पर पारदर्शिता बढ़ी है। अब सरकार को पता होता है कि किस कंपनी में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित भविष्य निधि सहित सभी जरूरी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं। पिछले चार साल में दो लाख से अधिक फर्जी कंपनियां अगर पकड़ में आई हैं तो वह इसी जीएसटी की देन है।

जीएसटी का दायरा बढ़े और इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इसके लिए इसमें कई स्तरों पर सुधार की गुंजाइश अभी बनी हुई है। अभी जीएसटी के पांच स्लैब हैं। इससे इसकी संरचना थोड़ी जटिल बनी हुई है। इन्हें कम कर दो या तीन किया जाना चाहिए। जैसे-12 और 18 प्रतिशत वाले स्लैब को मिलाकर एक तार्किक दर बनाई जा सकती है। इसके अलावा पेट्रोलियम, बिजली, रियल एस्टेट और शराब को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग लंबे समय से हो रही है। अब समय आ गया है कि जीएसटी परिषद इस पर गंभीरता से विचार करे। पूरे देश में इन पर समान रूप से कर लगाए जाने से इनकी कीमतों को लेकर विसंगति दूर होगी और वे सस्ते भी होंगे। इसके साथ-साथ जो राज्य जीएसटी संग्रह में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें केंद्र सरकार को कुछ बोनस देना चाहिए। तिमाही रिटर्न भरने और तिमाही पेमेंट की व्यवस्था लाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। उम्मीद है जैसे-जैसे सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जीएसटी का दायरा बढ़ेगा। और फिर देश का टैक्स-जीडीपी अनुपात भी बढ़ेगा। अभी यह अनुपात 9.9 है, जो ओईसीडी (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन) देशों के 34 प्रतिशत से काफी कम है।

मेलबाक्स

नीतियां बनाने में तेजी लाने की जरूरत

'खुद को साबित करने का अवसर' शीर्षक से लिखे अपने लेख में सुजन पाल सिंह ने कहा है कि दुनिया कोविड-19 के बाद के युग में एशिया में नए शक्तिशाली कारोबारी साझीदार ढूंढ रही है। भारत को इस मौके को किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। देखा जाए तो इसमें कोई नई बात नहीं है। कोरोना काल के पहले से ऐसी बातें कही जाती रही हैं। जरूरत है कि अब इस विचार को जमीन पर उतारा जाए। बेहतर होता कि लेखक इसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, इसके उपाय बताते। आज देश की हालत ऐसी है कि एक आइडिया को जमीन पर उतरने में दशकों लग जाते हैं। वस्तु एवं सेवा कर इसका उदाहरण रहा है। वर्षों से शिक्षा नीति बदलने की बात हो रही थी। इसे सामने आए साल भर से अधिक समय बीत गया है, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। देश के कृषि क्षेत्र को बदहाली से निकालकर समृद्धि के रास्ते पर लाने के लिए मोदी सरकार ने तीन कृषि कानून बनाए, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ, यह हम सब भलीभांति जानते हैं। ऐसे दर्जनों उदाहरण गिनाए जा सकते हैं कि देश में नीतियां बनाने उन्हें कानून का दर्जा देने और फिर उन्हें अमल में लाने में कैसे सालोंसाल लगे। वे सही रूप में जमीन पर उतर पाई भी हैं कि नहीं-इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। वास्तविकता यह है कि देश में आज एक कानून बनना शुरू होता है और फिर चार-पांच साल में मुकम्मल होता है, लेकिन तब तक दुनिया काफी बदल चुकी होती है। जाहिर है ऐसे में हमारा कानून समय के साथ तालमेल बैठाने में कमजोर साबित होता है। नीतियां बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में हमारी यह गति तो हमें विश्व गुरु या वैश्विक लीडर बनाने से रही। जब तक हमारे पास किसी क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट कानून नहीं होगा, तब तक विदेशी निवेशक आने में रुचि नहीं दिखाएंगे। इसके अभाव में उनके मन में हमेशा एक डर बैठा रहेगा। जरूरत है इस रणनीति में बदलाव लाने की। हम इसके लिए एक समयसीमा तय कर सकते हैं। जैसे-तीन माह, छह माह या फिर एक साल। वहीं राष्ट्रहित के मुद्दों पर आगे बढ़ने की राह में किसी तरह का राजनीतिक मतभेद सामने न आए इसके लिए देश में कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। संभव है इससे देश का माहौल बदलेगा।

विकास सिंह, गोरखपुर

खामियों भरी वर्चुअल शिक्षा प्रणाली

संपादकीय पेज पर कोरोना ने बदला शिक्षा देने का तरीका पढ़ा। इसमें गिरीश्वर मिश्र ने आभासी अथवा वर्चुल शिक्षा पद्धति को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुनौती माना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि कोरोना के चले जाने के बाद हमें अपनी परंपरागत अथवा फेस टू फेस शिक्षण व्यवस्था को उपयुक्त ढांचे में लाने के लिए पहले की अपेक्षा अपनी शिक्षण व्यवस्था में शामिल घटकों जैसे शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम और अन्य अनुसंधानों पर जोर देना होगा। हालांकि नई शिक्षा नीति अनेकों खामियों को दूर करती हुई शिक्षण व्यवस्था में एक परिवर्तनकारी अथवा सुधारात्मक बदलाव लाने के लिए तत्पर है, लेकिन यह तभी संभव है जब तमाम प्रकार के शिक्षण संस्थान खुलें और कक्षाएं लगनी आरंभ हो जाए। लेकिन अभी तीसरी लहर को लेकर जिस प्रकार से संभावनाएं जताई जा रही हैं उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि अभी प्रत्यक्ष शिक्षण प्रणाली की संभावना कम ही है। ऐसे में हमारे पास दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था अथवा आभासी शिक्षण के अलावा कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं है। हरियाणा, दिल्ली सरीखे राज्यों में तो इसे सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस बात की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अभी भी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि बहुतेरे राज्यों में लाखों विद्यार्थी अभी भी तकनीकी संसाधनों के अभाव में वर्चुअल शिक्षण प्रणाली से कोसों दूर हैं। बीते डेढ़ सालों में कोरोना महामारी ने शिक्षण व्यवस्था पर निश्चित तौर पर एक गहरी चोट मारी है जिसका सीधा नुकसान ग्रामीण अथवा सुदूर क्षेत्रों के साधनहीन छात्रों को ज्यादा हुआ है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम जल्द कोरोना संकट से उबर कर अपनी शिक्षण व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से नई शिक्षा नीति के ढांचे में ढाल पाएंगे।

पवन कुमार मुरली, गुरुग्राम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

37.16 करोड़ लाख डालर की आमदनी हुई थी ट्विटर को वर्ष 2020 में। जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार ट्विटर के लगभग 18.6 करोड़ सक्रिय यूजर्स हैं।



उमेश चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार

आजकल

इंटरनेट मीडिया मंचों पर नियंत्रण आवश्यक

व्यापक यूजर आधार और उसके जरिये हो रही मोटी कमाई ने इंटरनेट मीडिया की कुछ खास कंपनियों को ऐसी ताकत दे दी है, जिसकी वजह से आजकल वे संप्रभु सरकारों तक को चुनौती दे रही हैं। भारत के मौजूदा इंटरनेट मीडिया नियमावली को लागू करने में जिस तरह ट्विटर हीलाहवाली दिखा रहा है, उससे तो यही साबित होता है। ट्विटर जैसी कंपनियां खासकर लोकतांत्रिक देशों में स्थानीय नियमों को धता बताने में आगे रही हैं। समय आ गया है जब इनके साथ सख्ती से निपटने के लिए सभी इंतजाम किए जाने चाहिए



राष्ट्र के नियमों-कानूनों के दायरे में रहकर कार्य करें इंटरनेट मीडिया कंपनियां। प्रतीकात्मक

महज डेढ़ दशक पहले शुरू हुआ ट्विटर क्या राष्ट्रों की संप्रभुता को चुनौती देने लगा है? हाल के दिनों में साइट ट्विटर ने जिस तरह का रवैया दिखाया है, उससे इस आशंका को ही बल मिल रहा है। यह मामूली बात नहीं है कि भारतीय संविधान के तहत शपथ ले चुके उस मंत्री का ट्विटर एकाउंट निलंबित कर दिया, जिन पर सूचना प्रौद्योगिकी को नियमित करने की जिम्मेदारी है।

ट्विटर की हिमाकत यहीं पर नहीं थमी, उसने भारतीय संप्रभुता की गारंटी देने वाली संसद की सूचना और संचार मामलों की समिति के अध्यक्ष तक का ट्विटर एकाउंट बाधित कर दिया। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बारे में उससे स्पष्टीकरण मांगा गया तो उसे देने में भी वह हीलाहवाली कर रहा है। ऐसे अनेक अवसर अभी सामने आए हैं जब उससे संबंधित मामलों के बारे में जवाब मांगा गया तो उसने इसकी अनदेखी तक की। तो क्या यह मान लिया जाए कि अपने भारी-भरकम यूजरों के चलते ये माइक्रोब्लागिंग साइटें खुद को स्थानीय कानूनों से ऊपर मानने लगी हैं?

अगर ऐसा है तो क्या इसकी वजह उसके भारी-भरकम यूजर आधार और उसके जरिये हो रही मोटी कमाई से मिली ताकत तो नहीं है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जो इन दिनों भारतीय समाज और राजनीति को मथ रहे हैं। मौजूदा विभाजनकारी सोच से प्रभावित एक तबके को भले ही ये सवाल परेशान नहीं कर रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है। भारत में यह सवाल पूछा जाने लगा है कि आखिर किसी कंपनी को ऐसी ताकत कहां से मिलती है कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उपराष्ट्रपति तक के इंटरनेट मीडिया हैंडल से छेड़खानी करने की हिम्मत कर सकता है?

उपराष्ट्रपति के साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ के पूर्व सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी समेत संघ के पांच प्रमुख नेताओं के ट्विटर हैंडल से ब्लूटिक उस वक्त हटाया गया, जब नई नियमन व्यवस्था को लागू करने को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच विवाद चल रहा है। इस बात को मानने की कोई वजह नहीं कि ट्विटर के अधिकारी संघ के इन पांच प्रमुख नेताओं की हैसियत को नहीं जानते हों। तो ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि ट्विटर ने एक तरह से भारत सरकार को चुनौती दी है? जिस तरह का उसका व्यवहार दिख रहा है, उससे लगता तो ऐसा ही है कि एक तरह से ट्विटर खुद को संप्रभु राष्ट्र की तरह देख रहा है।

खुद को प्रोमोट करने में सबसे आगे : इंटरनेट मीडिया के मंच स्वयं को प्रोमोट करने के लिए खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार बताते नहीं थकते। लेकिन जब किसी राष्ट्र की स्थानीय संस्कृति और राजनीति की बात होती है तो वे अपने इसी दावे को ही भूल जाते हैं। इसके लिए तब वे अपनी उस आंतरिक नियमावली का सहारा लेते हैं, जो उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वाधीनता, व्यापक जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के दावे के साथ बना रखी है। हालांकि जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों की उनकी अपनी परिभाषा और सोच है। खासकर ट्विटर का जिस तरह का रुख रहा है, उसमें विरोधाभास और पक्षपात दोनों दिखता है। कथित लोकतांत्रिक मूल्य और व्यापक जनहित के नाम पर उसकी पाबंदी या ट्वीट हटाने के दायरे में ज्यादातर राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी ताकतें ही आती रही हैं। भारत के ही संदर्भ में देखें तो ट्विटर का पक्षपाती रवैया ही सामने आया है। इसलिए भारत में तो एक धारणा ऐसी बन गई है कि ट्विटर धुर वामपंथ से प्रभावित ऐसा मंच है, जो अपने कथित दिशा-निर्देशन के नाम पर सिर्फ दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी विचार को ही निशाना बनाता है।

उपराष्ट्रपति और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के ट्विटर हैंडल से ब्लूटिक हटाने को लेकर ट्विटर ने जो तर्क दिए, वे खुद उसके कार्यकलाप की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाते हैं। ट्विटर का कहना था कि चूंकि इन हैंडल पर छह महीनों से कोई ट्वीट नहीं हुआ, इसलिए नियमानुसार ब्लूटिक यानी वैरीफाइड का निशान हटाया गया। ऐसा तर्क देते वक्त ट्विटर यह देखना भूल गया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे एक साल हो गया, पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी भी अरसा पहले दुनिया छोड़ गए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल भी दुनिया में नहीं हैं। लेकिन इनके हैंडल पर ब्लूटिक कैसे चिपका पड़ा है?

यह बात अब छिपी नहीं है कि किसान आंदोलन के दौरान जनवरी में लालकिले पर हमला हो या फिर आंदोलनकारियों को जुटाने की बात हो, हर बार ट्विटर का ज्यादा सहारा लिया गया। तब ट्विटर का अपना अंदरूनी दिशा-निर्देश काम नहीं आया। उसे शायद यह लगता रहा कि आंदोलनकारी दुनिया को सकारात्मक ढंग से बदल रहे हैं।

कुछ दिन पहले ट्विटर ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को मैनपुलेटेड मीडिया हैशटैग के साथ पेश किया था तो इससे विपक्षी दल बेहद खुश थे। इसके बाद जब ट्विटर के दफ्तरों पर दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया तो इसे भारत का ही एक खेमा अभिव्यक्ति की स्वाधीनता मानकर सरकार पर हमलावर हो गया था।

राष्ट्र की अवधारणा को चुनौती : एक बात और नजर आ रही है। इंटरनेट मीडिया के मंच राष्ट्र की अवधारणा को भी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। राष्ट्र के जो चार बुनियादी तत्व भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता माने जाते हैं, इनमें से सिर्फ भूभाग उनके पास नहीं है। अन्यथा उनके पास भारी संख्या वाले यूजरों का आधार है। इनके जरिये मोटी कमाई हो रही है। जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक ट्विटर पर करीब 18.6 करोड़ लोग सक्रिय हैं। अपने भारी यूजर आधार के चलते इंटरनेट मीडिया मंचों में फेसबुक का स्थान पहला है, जिसके करीब 2.74 अरब यूजर हैं। जबकि वाट्सएप के दो अरब यूजर हैं। अमेरिका में लगभग 6.93 करोड़ लोग ट्विटर का नियमित उपयोग करते हैं। भारत में यह संख्या करीब 1.75 करोड़ है और लगातार बढ़ ही रही है। पांच करोड़ से कुछ ज्यादा जापानी भी ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राजील में 1.62 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है कि अपने कथित दिशा-निर्देशों के बहाने ये कंपनियां राष्ट्रों के मामलों में परोक्ष रूप से दखल दे सकती हैं और वहां की व्यवस्था पर असर डाल सकती हैं।

तमाम इंटरनेट मीडिया कंपनियों की भावी मनमानी को संघ के वरिष्ठ प्रचारक और भाजपा के पूर्व संगठन महासचिव गोविंदाचार्य ने भांप लिया था। यही वजह है कि कुछ साल पहले उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी डालकर भारतीय और विदेशी इंटरनेट मीडिया कंपनियों को भारत में सर्वर लगाने का आदेश देने की मांग की थी। उनका तर्क था कि अगर भारत में उनके सर्वर होंगे तो भारत से होने वाली कमाई पर उन्हें नियमानुसार कर देना होगा और उनके यूजर के डाटा तक भारतीय व्यवस्था की पहुंच होगी।

वैसे यह भी कम विरोधाभास नहीं है कि जिस वामपंथी विचारधारा की ओर इंटरनेट मीडिया मंचों की सोच झुकी नजर आती है, उसी वामविचार से शासित देशों मसलन चीन आदि में इनकी पहुंच ही नहीं है। वहां इन पर पाबंदी है। यह भी विरोधाभास ही है कि उदारीकरण को पूंजीवाद के प्रसार का जरिया मानकर उसका विरोध करने वाली वामपंथी विचारधारा विशाल पूंजीवादी व्यवस्था बन चुके इंटरनेट मीडिया के मंचों का समर्थन करने में हिचक नहीं दिखाती। अभिव्यक्ति की सेलेक्टिव स्वाधीनता के समर्थन में इंटरनेट मीडिया का पूंजीवादी मंच उन्हें विरोधी नजर नहीं आता।

अमेरिका में ट्रंप पर पाबंदी के खिलाफ बड़ा विरोध इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि तब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो रहा था और वहां की संप्रभुता की गारंटी संसद पर हमला हो चुका था। लेकिन नाइजीरिया ने राह दिखा दी है कि इंटरनेट मीडिया के मंच व्यापक जनहित और अभिव्यक्ति की स्वाधीनता के स्वघोषित सेल्फ-सेलेक्टिव विचारधारा को संप्रभु राष्ट्रों पर थोप नहीं सकते। इंटरनेट मीडिया मंचों की तुलना में कहीं ज्यादा गहरे तक लोकतांत्रिक हो चुके समाज की प्रतिनिधि भारत सरकार को भी इससे प्रेरणा लेनी ही होगी।

सेलेक्टिव सोच पर उठते सवाल

ट्विटर की सेलेक्टिव सोच वाली ताकत के पहले शिकार ईरान के नेता अली खुमैनी थे। वर्ष 2019 में उन पर ट्विटर ने पांबदी लगाई थी। यह बात और है कि कुछ ही दिनों में उसे बहाल कर दिया। इस साल 20 जनवरी को ट्विटर ने तब दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति रहे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल को भी बंद कर दिया था। उसका तर्क था कि उनके भड़काऊ बयानों से अमेरिका में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण में बाधा आई और संसद पर हमले हुए। हाल के दिनों में फेसबुक ने भी उनके एकाउंट पर पाबंदी लगा दी है। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि उन पर पाबंदी दरअसल अमेरिका के उन साढ़े सात करोड़ लोगों का अपमान है, जिन्होंने उन्हें वोट दिया था।

कुछ इसी तरह की सेलेक्टिव सोच के चलते नाइजीरिया से ट्विटर का बोरिया बिस्तर उठ गया है। नाइजीरिया में ट्विटर के 1.8 करोड़ यूजर थे। खनिज तेल से समृद्ध इस देश के इन यूजरों की सहायता से ट्विटर यहां मोटी कमाई कर रहा था। नाइजीरिया में भी ट्विटर ने अपने कथित लोकतांत्रिक दिशा-निर्देश का खेल खेला। वहां के गृहयुद्ध में विद्रोही गुटों के खिलाफ वहां के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने एक ट्वीट में लिखा था कि 'जो आज बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उन्हें उसी भाषा में समझाया जाना चाहिए, जिसे वो समझते हैं।' ट्विटर ने इस ट्वीट को अपनी गाइडलाइन का उल्लंघन बताते हुए हटा दिया था। इसके बाद सरकार ने अपने यहां ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी है।

अभिव्यक्ति की स्वाधीनता हो या फिर व्यापक जनहित का आधार, ये दोनों ही अवधारणाएं कम से कम इंटरनेट मीडिया कंपनियों की नजर में सब्जेक्टिव नजर आ रही हैं। उनकी नजर में एक पक्ष के लिए जहां इनके मायने कुछ और नजर आते हैं तो दूसरे पक्ष के लिए कुछ और। यही वजह है कि उनके कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं। चूंकि ट्विटर ही इन दिनों विवादों में है। इसलिए यह जान लेना चाहिए कि इन दिनों उसकी कमाई कितनी है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के मुताबिक ट्विटर की कमाई 37 अरब 16 करोड़ 35 लाख डॉलर थी। कई देशों की तो अर्थव्यवस्था भी इतनी नहीं होती।

खरी-खरी

जरा फ्यूज उड़ाओ, चुनावी मौसम है

बीएल आच्छा

चुनाव तो लोकतंत्र का फगुनिया राग है। राग-रंग भी पक्ष-विपक्ष के लिए उलटकर सुलटे और सुलटकर उल्टे। विपक्ष की आवाज ऐसी बुलंद कि उजालों पर घोर अंधेरा न बरपा पाएं तो गहरा भुरभुरा तो कर ही डालें। सत्ता में हों, तो घने अंधेरों को चंपई दिखा दें। मुफ्तिया बरसातों में वोटर भी गाने लगे- आसमां ने खुश होकर रंग बिखेरे हैं।

अब कोई बिजली मुफ्त देकर दूजों पर बिजलियां गिराएगा तो अगला उनका फ्यूज उड़ाएगा कि नहीं? कुछ नई पेशकश से इन बिजलियों की लेजर काट करेगा कि नहीं?

अपने गठबंधन के लिए किसी और गठबंधन से एक तार खींच लिया या अपने तार को छुआ दिया तो डीपी ही उड़ जाती है धमाके के साथ। एक सौगात से बड़ी सौगात का एजेंडा रच दिया तो किए कराए की बिजली गुल। जमाना चला गया, जब योजनाओं के एजेंडे ही वोटरों की निगाह होती थी। बड़े-बड़े बांध, राजमार्ग, बड़े-बड़े कारखाने, पिछड़े-आदिवासी अंचलों को जोड़ती रेलें-सड़कें। सबकुछ होने के बावजूद मुफ्तिया पेच ही सुर्खियों में इतराते हैं।

चुनावी मौसम में लगता है कि आम के बगीचे से आमरस सीधे ऑनलाइन टपकाने की स्वप्न नीति कारगर हो रही है। सबकी अपनी अपनी गुगली। सभी पॉकिटों पर अपने-अपने दांव।

कभी-कभी फेंटेसीनुमा ऐसा बबूल दिख जाता है, जिसमें जितने कांटे हैं, उतने ही फल और खिले-खिले गुलमोहर के फूल। कांटे भीतर में इकदूजे को चुभाते रहें। गठजोड़न-गठतोड़न के खेलों में खेला हो जाए। गुप्त पेच और उखाड़ चालें। मगर चुनावी मौसम में अदृश्य बबूल में फलों की बहार और गुलमोहर के फूलों से लुभाती चुनावी खुश-फेंक।

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस कौशल से दुनिया भर के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हैरत में पड़ जाते हैं। गिरती हुई जीडीपी, महकते हुए आश्वासन। समाजशास्त्र की सारी रिसर्च टूटते गठबंधनों के मर्सिया और विरोधियों के साथ रॉक-एनरोल करते पाणिग्रहण पर भौंचक रह जाते हैं। मगर रौशनी और फ्यूज का गणित। बिगड़ते बजट और मुफ्तवाद के एजेंडे को न अर्थशास्त्र समझ पाता है न समाजशास्त्र।

ट्वीट-ट्वीट

इंटरनेट मीडिया पर जिन-जिन मंत्रियों का बैंड बजा, उनमें से अधिकांश छंट गए। यह है इंटरनेट मीडिया की ताकत और प्रधानमंत्री की इंटरनेट मीडिया पर बारीक नजर।
अभिषेक उपाध्याय@upadhyayabhii

इतनी बड़ी तादाद में केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब तीरथ सिंह रावत शायद कुछ कम तन्हा महसूस कर रहे होंगे।
निस्तुला हेब्बार@nistula



मुझे ऐसा कैबिनेट विस्तार और फेरबदल याद नहीं आता, जहां हटाए गए मंत्री भी नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शिद्दत से प्रतीक्षा कर रहे हों। यह नई टीम संस्कृति, नए राजनीतिक मूल्यों और एकसमान विचारधारा को ही दर्शाता है।
स्मिता प्रकाश@smitaprakash

रविशंकर प्रसाद जी और प्रकाश जावडेकर जी का इस्तीफा इस बात का साफ संकेत है कि मंत्रिमंडल के बाद भाजपा के संगठन में भारी फेरबदल होगा।
अशोक श्रीवास्तव@AshokShrivasta6

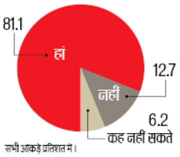
केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो गया है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव का अभी भी इंतजार है।
कपिल कोमिरेड्डी@kapskom

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह एकदम नई कैबिनेट नजर आ रही है। यह मोदी के अगले पड़ाव की शुरुआत लगती है।
रतन शारदा@RatanSharda55

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद ही विधानसभा चुनाव होने चाहिए?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद पहले से अधिक सक्षम दिख रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

निकले नई उड़ान पर नए कलेवर संग,
नया मंत्रिपरिषद बना दिखती नई उमंग।
दिखती नई उमंग संग हैं अनुभव वाले,
दे सकती यह टीम हमें परिणाम निराले।
लक्ष्य बना चौबीस न हाथों से वह फिसले,
यदि मोदी की टीम काम में अव्वल निकले।
- ओमप्रकाश तिवारी



संजय मिश्र
स्थानीय संपादक, नवदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश डायरी

नक्सलियों की चुनौती का नया क्षेत्र

अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए मशहूर मध्य प्रदेश में एक बार फिर नक्सली खतरे की आहट महसूस की जाने लगी है। छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने के बाद माना जाने लगा था कि शेष मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियां समाप्त हो गई हैं, लेकिन समय के साथ यह अनुमान गलत साबित हो रहा है। पिछले लगभग 20 साल के अंदर नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए योजनाएं तो अनेक चलाई गईं, लेकिन वे उतनी कारगर नहीं हो सकीं जितनी उम्मीद की गई थी। इन वर्षों में जहां कई राज्यों में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगी है, वहीं मध्य प्रदेश में तीन ऐसे जिलों की पहचान की गई जहां इनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं।

हाल ही में राज्य पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा डिंडौरी को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है। बीते दो दशकों में यह प्रदेश का तीसरा जिला है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित हुआ है। इससे पहले बालाघाट और मंडला को इस श्रेणी के जिलों में रखा गया था। इन क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को आधार मिलने का मूल कारण यहां के लोगों की गरीबी और अशिक्षा है। यह दलील पूरी तरह सच नहीं है कि सिर्फ विचारधारा से प्रभावित होकर स्थानीय लोग नक्सलियों को मान्यता देते हैं। सच यह है कि आदिवासी बहुल इन क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा से त्रस्त लोगों को नक्सली सुनियोजित ढंग से अपना मोहरा बनाते हैं और उन्हें बरगलाने का प्रयास करते हैं। यद्यपि सरकार ने आदिवासी इलाकों पर काफी ध्यान दिया है, लेकिन रोजगार के साधन सीमित हैं। पुलिस के खुफिया तंत्र को इन क्षेत्रों से कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है। अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए नक्सली इस क्षेत्र की गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। गरीबी से त्रस्त लोगों को उकसाकर वे अपने लिए सुरक्षित ठिकाना बना रहे हैं। इन क्षेत्रों में नक्सलियों की आवाजाही बढ़ने के पीछे विदेशी संस्थाओं से चंदे के रूप में मिल रहा आर्थिक संबल बड़ा कारण है। इसके जरिये वे गरीबों के बीच विश्वास बढ़ाने का प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। हालांकि डिंडौरी में नक्सली समस्या नई नहीं है, लेकिन इसके विस्तार की सूचना चौंकाने वाली जरूर है। लंबे समय से यह क्षेत्र भी नक्सलियों के आने-जाने का प्रमुख मार्ग रहा है।



नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज। फाइल

डिंडौरी का जंगल अमरकंटक से लगा हुआ है। वर्ष 2014 में कोबरा बटालियन को यहां से हटा लिया गया। इसके कुछ महीनों बाद ही फिर से सरकार ने हॉकफोर्स तैनात करने का निर्णय लिया। यह स्थापित तथ्य है कि पुलिस बल की कमी होने के कारण ही बालाघाट, मंडला, अनूपपुर और डिंडौरी में नक्सली बढ़े।

कुछ वर्ष पूर्व नक्सलियों ने विस्तार दलम का गठन कर मध्य प्रदेश में भी अपने विस्तार का खाका खींचा था। वे बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में सक्रिय होने लगे। पुलिस को जानकारी मिली कि वे क्षेत्र में पैठ बनाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। राज्य की पुलिस ने इसे बड़ी चुनौती मानते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजकर डिंडौरी को नक्सल प्रभावित जिला घोषित करने का अनुरोध किया। कुछ दिनों पूर्व ही केंद्र सरकार ने इसे नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल कर लिया है। माना जा रहा है कि अब राज्य पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बल मिलकर नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। केंद्र की ओर से आर्थिक और सुरक्षा संबंधी जरूरी मदद मिल जाएगी।

डिंडौरी जिले की पुलिस को भी नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। नक्सलियों का छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश आने का मार्ग बंद किया जा सकेगा। केंद्र की सूची में शामिल होने के बाद देशभर में होने वाले नक्सली हमलों के तरीकों को यहां की पुलिस से साझा करने में मदद मिलेगी। स्थानीय बल को आधुनिक हथियार मिल सकेंगे। केंद्र की योजनाओं के तहत वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। बालाघाट और मंडला के बाद नक्सलियों के ठिकानों पर व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा सकेगी। जंगलों में सुरक्षा बलों के निगरानी शिविर स्थापित किए जा सकेंगे। साथ ही जिले के दुरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का विश्वास जीतने की योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा सकेगा। यह भी एक तथ्य है कि जिन रास्तों से नक्सलियों की आवाजाही रहती है, वे अधिकतर घने जंगलों वाले इलाकों में हैं। मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और अमरकंटक के बीच नक्सलियों के सुरक्षित कॉरिडोर के बीच कई नदियां हैं। बारिश शुरू होते ही नक्सली इन जंगलों में डेरा डाल लेते थे और बरसात के दिनों में वहीं पर रहते हैं। वे समाजसेवा के नाम पर स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल करने का प्रयास करते हैं, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहती है। अब डिंडौरी में भी पुलिस अपना सूचना तंत्र मजबूत कर रही है। केंद्र सरकार से आर्थिक और सुरक्षा संबंधी सुविधा मिलने से पुलिस लोगों के बीच पुलिस विश्वास पैदा कर सकेगी। इनके लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।

मंथन



प्रदीप
विज्ञान के जानकार

अंतरिक्ष पर्यटन का आनंद

अंतरिक्ष में सैर करने की इंसान की चाहत बहुत पुरानी है। इसे व्यावहारिक रूप से संभव और सुगम बनाने में दुनिया की दो संबंधित दिग्गज कंपनियां जुट गई हैं

इन दिनों अंतरिक्ष की सैर करने के लिए दो दिग्गज अरबपतियों के बीच होड़ लगी हुई है। कुछ समय पहले ही अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने 20 जुलाई को ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेपर्ड की पहली स्पेस फ्लाइट में शामिल होने का एलान किया था। अगर ऐसा होता तो इस साल अंतरिक्ष में जाने वाले बेजोस पहले अरबपति होते, लेकिन अब उन्हें एक दूसरे कारोबारी से चुनौती मिली है। एक अन्य प्राइवेट स्पेस एजेंसी वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन ने बेजोस से पहले 11 जुलाई को ही स्पेसशिप-2 नामक यान से अंतरिक्ष की सैर पर जाने की घोषणा कर दी है।

रिचर्ड ब्रैनसन और जेफ बेजोस की ये उड़ानें सफल हो जाती हैं तो जल्द ही पूरी तस्वीर बदल सकती है। वैसे भी अगले साल तक वर्जिन गैलेक्टिक की अमेरिका में कॉमर्शियल स्पेस ट्रैवल की शुरुआत करने की योजना है, जिसके तहत लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। जब तक परिभाषा में कोई फेरबदल नहीं होता तब तक प्रत्येक अंतरिक्ष पर्यटक को 'अंतरिक्ष यात्री' होने का रुतबा भी हासिल होगा। इस उपलब्धि को पाने के लिए दुनिया भर के रोमांच प्रिय अरबपति लाखों डॉलर खर्च करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। यह उन लोगों के लिए एक वैश्विक 'स्टेटस सिंबल' हासिल करने जैसा ही होगा।

ज्यादातर लोगों के लिए अंतरिक्ष की सैर सपना है। मालूम हो कि 28 अप्रैल 2001 को डेनिस टीटो को पहला अंतरिक्ष पर्यटक होने का गौरव हासिल हुआ। टीटो कोई पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं हैं। वह रूस के एक धनी व्यवसायी हैं, उन्होंने सोयुज अंतरिक्ष यान में एक सीट के लिए रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस और अमेरिकी कंपनी स्पेस एडवेंचर लिमिटेड को दो करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था। अंतरिक्ष की उनकी यात्रा 10 दिनों की रही थी। हालांकि पिछले 20 वर्षों में सिर्फ सात लोगों ने ही पैसे देकर अंतरिक्ष पर्यटन का आनंद लिया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह संख्या एक साल में दोगुनी हो सकती है।

जहां रिचर्ड ब्रैनसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक और जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन पर्यटकों को अंतरिक्ष के छोर तक का सफर कराना चाहती है, वहीं विलियम ई बोइंग द्वारा स्थापित कंपनी बोइंग और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स नासा के सहयोग से बनाए गए स्पेस कैप्सूलों में पर्यटकों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाना चाहती है। वर्ष 2023 तक स्पेसएक्स पैसे लेकर लोगों को चांद की सैर कराना चाहती है। नासा ने भी पर्यटन के उद्देश्य से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2021-22 तक खोलने का निर्णय किया है। इस फैसले के पीछे की वजह यह माना जा रहा है कि स्पेस स्टेशन का रख-रखाव नासा के लिए बहुत खर्चीला साबित हो रहा है, लिहाजा वह वहां पर वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहती है।

अंतरिक्ष नीति विश्लेषक वेंडी व्हिटमैन कोब्बे के मुताबिक वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ऑरिजिन और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों की हालिया घोषणाएं एक ऐसे युग की शुरुआत हैं जिसमें ज्यादा लोग अंतरिक्ष पर्यटन का लुत्फ उठा सकते हैं। अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य का निर्माण करने की उम्मीद में, ये कंपनियां जनसामान्य के लिए अंतरिक्ष यात्रा की सुरक्षा और विश्वसनीयता दोनों को प्रदर्शित करने को इच्छुक हैं। इन कंपनियों का दावा है कि धरती की खूबसूरती के आगे जहां और भी हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़ी अनेक व्यावसायिक कंपनियों को इस क्षेत्र में सिरमौर बनने और अंतरिक्ष पर्यटन पर बेहिचक काम करने के लिए निश्चित रूप से प्रोत्साहित करेगा। फिर बात चाहे पृथ्वी की निचली कक्षा में जाने की हो या अंतरिक्ष यात्रियों को क्षुद्रग्रह, चांद या फिर मंगल तक पहुंचाने की। प्राइवेट स्पेस एजेंसियां इसके लिए कमर कस रही हैं। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब अंतरिक्ष की यात्रा सरकारों के कब्जे से धीरे-धीरे बाहर हो रही है और निजी कंपनियों के जरिये अंतरिक्ष में लोगों को ले जाने की घड़ी भी नजदीक आ गई है। वैसे भी नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम 2012 में ही खत्म हो चुका है। यानी उसके सभी स्पेस शटल रिटायर हो गए हैं। ऐसे में नासा को भी अंतरिक्ष यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए निजी कंपनियों के स्पेसक्राफ्ट्स पर निर्भर रहना होगा।



भविष्य में धरती से इतर अंतरिक्ष पर्यटन की संभावनाएं जोर पकड़ सकती हैं। प्रतीकात्मक

एलेन मस्क का दावा है कि अगर सबकुछ ठीक ठाक रहा तो 2025 तक स्पेसएक्स इस स्थिति में आ जाएगा कि वह एक ही साल में हजारों अमीर पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर करा सके और इसके बदले भारी-भरकम कमाई कर सके। अंतरिक्ष पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए कुछ कंपनियों ने अंतरिक्ष में होटल बनाने की योजनाओं पर भी काम शुरू कर दिया है। ओरायन स्पान नामक कंपनी 2022 तक अपना स्पेस होटल लॉन्च करना चाहती है और 2023 तक उसमें मेहमानों की मेजबानी का इरादा रखती है। गेटवे फाउंडेशन नामक कंपनी चांद पर 2025 तक होटल लॉन्च करना चाहती है।

बहरहाल, हम यह कह सकते हैं कि अंतरिक्ष एक बार फिर इंसान के सपनों की नई मंजिल बन गया है और निजी कंपनियों के कारण मंजिल तक दौड़ तेज होने जा रही है। अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब धरती पर एक से बढ़ कर एक मनोरम स्थलों के सैर-सपाटे की बातें पुरानी हो जाएंगी और लोग अंतरिक्ष भ्रमण का आनंद उठा सकेंगे।

10 हजार शिक्षकों के पदों को जल्द भरा जाएगा ओडिशा में। प्रदेश सरकार 4445 हिंदी, संस्कृत एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षक के साथ छह हजार ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की नियुक्ति करने की योजना बना रही है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 8 जुलाई, 2021

उत्तराखंड

धरातल पर दिखे बदलाव का असर

उत्तराखंड की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौकरशाही को चुस्त बनाने की कवायद शुरू कर दी है। 1988 बैच के आइएएस सुखबीर सिंह संधू को मुख्य सचिव बनाकर उन्होंने आने वाले समय में बड़े बदलाव के संकेत भी दिए हैं। प्रदेश में नौकरशाही की मनमानी को लेकर समय-समय पर सत्ता और विपक्ष दोनों ही सवाल उठाते रहे हैं। मंत्री और विधायक ही नहीं, बल्कि पूर्व में कई मुख्यमंत्री भी अफसरों की कार्यशैली पर आंखे तरेरते रहे हैं। फिर चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हों अथवा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत अन्य मुख्यमंत्री भी अपने-अपने कार्यकाल में नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों को लेकर कई बार नाखुशी जताते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालते ही नौकरशाही में बदलाव की उम्मीद की जाने लगी थी। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और परिवर्तन देखने को मिलेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को बदलकर संकेत दिए हैं कि आने वाले वक्त में बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इस परिवर्तन का असर धरातल पर भी नजर आना चाहिए

दरअसल राज्य गठन के बाद से ही अफसरों की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में नई सरकार का दायित्व है कि अपने कार्य व्यवहार से अधिकारियों को उनके दायित्व का अहसास कराए। क्योंकि नौकरशाही के मनमाने रवैये के लिए कहीं न कहीं नेता भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। नए मुख्यमंत्री युवा होने के साथ ही ऊर्जावान भी हैं। छात्र संगठन से लेकर भारतीय जन युवा मोर्चा में वह अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय भी दे चुके हैं। भले ही उन्हें अभी प्रशासनिक अनुभव नहीं है, लेकिन उनकी क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहली ही कैबिनेट में उन्होंने 22 हजार रिक्त पदों पर भर्ती का एलान कर राज्यवासियों की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वह स्वयं युवा हैं और उन पर युवाओं की अपेक्षाओं का दबाव भी है। मुख्यमंत्री के पास समय कम है और चुनौतियों का पहाड़ मुंह बाये खड़ा है। आगामी विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त शेष नहीं है।

जाहिर है इस अवधि में उन्हें न केवल खुद को साबित करना है, बल्कि आम जन की उम्मीदों पर खरा भी उतरना है। पार्टी ने उन पर भरोसा कर भविष्य की राजनीति के लिए नई राह चुनी है। पलायन से खाली होते पहाड़ों पर रोजगार के अवसर जुटाने के साथ ही उन्हें बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी गंभीरता के साथ कदम उठाने होंगे। आने वाला वक्त मुख्यमंत्री के लिए अग्नि परीक्षा का है और उम्मीद की जानी चाहिए कि वह इसमें खरा उतरेंगे।

पंजाब

उद्यमियों की परेशानी

प्रदेश सरकार की लेटलतीफी के कारण पैदा हुए बिजली संकट से उद्यमियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बिजली संकट के कारण सरकार ने इंडस्ट्री में पहले तीन दिन का अनिवार्य अवकाश घोषित किया था। रविवार को नया आदेश जारी किया गया है कि इंडस्ट्री सिर्फ 30 फीसद क्षमता के साथ चलेगी। हालांकि कुछ उद्योगों को इस शर्त से बाहर रखा गया है, लेकिन इनकी संख्या बहुत सीमित है। नार्थ और सेंट्रल जोन के बाद अब बार्डर जोन के तहत आने वाले उद्योगों में भी कट लगाने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना महामारी की वजह से गत दिनों लगाई गई तमाम पाबंदियों के कारण इंडस्ट्री पहले से ही कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रही है। पाबंदियों में छूट मिलने के बाद आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे पटरी पर आनी शुरू हुई थी, लेकिन इसी बीच बिजली संकट ने उद्यमियों की चिंता फिर से बढ़ा दी है।

हालांकि प्रदेश सरकार यह दावा कर रही है कि शीघ्र ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन उसके दावे पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए, क्योंकि एक दिन पहले ही बार्डर जोन की इंडस्ट्री में 72 घंटे के कट लगाने की बात कही


भविष्य में होने वाली बिजली की संभावित समस्याओं को समय रहते समझना होगा। फाइल

ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिए यदि समय रहते प्रक्रिया शुरू की गई होती तो शायद आज इस तरह के बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ता

गई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बिजली की डिमांड बढ़ी है। धान के सीजन में डिमांड हर साल बढ़ती ही है, लेकिन पर्याप्त बारिश न होने के कारण इस बार सरकार और पावरकाम के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई है। चूंकि ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता के मुताबिक पंजाब दूसरे राज्यों और नेशनल ग्रिड से बिजली ले रहा है, इसलिए फिलहाल और कोई विकल्प उसके पास नजर नहीं आ रहा है। ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिए यदि समय रहते प्रक्रिया शुरू की गई होती तो शायद आज इस विकट स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। सरकार और पावरकाम के ढीले रवैये के कारण ही अभी ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता बढ़ने में कम से कम तीन माह और लगेंगे।

इसी बीच बिजली पर सियासत भी गर्मा गई है। प्रदर्शन करने के साथ ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा और यह देखना होगा कि ऐसे मामलों में भविष्य में किसी भी तरह की लेटलतीफी न हो। उपभोक्ताओं को तो बिजली चाहिए और इसे उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है।

बंगाल

फर्जी अधिकारियों की गिरफ्तारी

बंगाल में पिछले करीब एक माह में कई फर्जी अफसरों की गिरफ्तारी हुई है, जो यह बताने को काफी है कि यहां के पुलिस और प्रशासन कितने सजग और सतर्कता से काम करते हैं। महानगर के कसबा में फर्जी टीकाकरण कैंप आयोजन का भंडाफोड़ नहीं होता और खुद को आइएएस अफसर एवं कोलकाता नगर निगम का संयुक्त आयुक्त बनकर नीली बत्ती लगाकर चलने वाले देबांजन देब की गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो शायद ये सभी जालसाज आराम से नीली बत्ती लगाकर घूमते रहते और लोगों से ठगी करते रहते। सोमवार की रात कोलकाता पुलिस ने एक और फर्जी अफसर को गिरफ्तार किया। हालांकि उसके बारे में जानकारी मिली है कि वह पेशे से वकील है, लेकिन खुद का परिचय सीबीआइ अफसर के रूप में दे रहा था। इस जालसाज का नाम सनातन राय चौधरी है। उस पर पहले से धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज है।

सोमवार की रात कोलकाता पुलिस ने एक फर्जी अफसर को गिरफ्तार किया। वह पेशे से वकील था, लेकिन खुद का परिचय सीबीआइ अफसर के रूप में दे रहा था

ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जब उस पर आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं तो फिर वह नीली बत्ती लगी गाड़ी से कैसे घूम रहा था? उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना परिचय केंद्रीय जांच एजेंसी के उच्च अधिकारी के रूप में दिया, जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आरोपित ने सच्चाई उगल दी, लेकिन उनसे ने ऐसा क्यों किया? यह ऐसा सवाल है जिसे लेकर पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठता है। इससे पहले कोलकाता से फर्जी केंद्रीय सतर्कता अधिकारी बनकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। वह भी नीली बत्ती लगी गाड़ी से घूम रहा था। इसी तरह नदिया से फर्जी सीआइडी अधिकारी बनकर लोगों को ठग रही महिला को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ही अलग-अलग घटनाओं में चार फर्जी अफसरों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुलिस और प्रशासन के बीच किसी प्रकार का समन्वय नहीं है? अगर समन्वय होता तो पुलिस को यह पता होता कि महानगर और आसपास के इलाके में नीली बत्ती लगी गाड़ियों पर चलने वाले कितने अफसर और वीआइपी हैं। उसे यह जानकारी होती कि उनका हर दिन मूवमेंट और कार्य किन-किन इलाकों में अधिक होता है। परंतु कसबा में एक फर्जी आइएएस नगर निगम का अधिकारी बनकर दफ्तर खोलकर बैठता है और पुलिस-प्रशासन को कुछ पता नहीं होता। यह स्थिति देश की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। पुलिस-प्रशासन की सुस्ती का ही यह नतीजा है कि बंगाल आतंकवादियों और घुसपैठियों का केंद्र बनता जा रहा है।

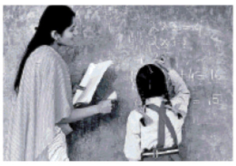
/ हिमाचल प्रदेश /

शिक्षकों की अहमियत

अंततः जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शिक्षकों के विषय में की गई अपनी टिप्पणी को वापस लेकर एक बड़े विवाद को समाप्त कर दिया है। वस्तुतः अवांछित और अनापेक्षित थी उनकी टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में सबसे अधिक आनंद शिक्षकों ने उठाया और फिर प्रथम पंक्ति कार्यकर्ता भी घोषित हो गए। इसके बाद लगभग हर शिक्षक संघ आक्रोशित था और निरंतर आग उगलते बयान दिखाई दे रहे थे। मंत्री ने शिक्षक वर्ग के साथ उक्त टिप्पणी पर खेद जता कर ठीक ही किया, क्योंकि किसी एक वर्ग के लिए ऐसी टिप्पणी किसी भी तरह से उचित नहीं थी।

सच यह है कि वैश्विक महामारी के इस दौर में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहा है। इसमें सरकारी कर्मचारी भी पीछे नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को सभी का सहयोग मिला है। ऐसा ही शिक्षकों ने भी किया। वे सिर्फ शिक्षा के प्रसार के लिए ही नहीं, समाज निर्माण के लिए भी आगे रहे हैं। बेहतर समाज निर्माण में भी शिक्षकों के

जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के शिक्षकों के प्रति खेद जताने के साथ ही प्रदेश एक बड़े विवाद से बच गया है


कोरोना काल में शिक्षकों का रहा उल्लेखनीय योगदान। फाइल

योगदान स्मरणीय है। सरकार की कोई भी योजना हो उसके क्रियान्वयन में भी शिक्षकों की सहभागिता अवश्य रहती है। पंचायत चुनाव से लेकर संसदीय चुनाव और जनगणना तक। कई जिलों में व्यवस्था बनाने से लेकर टीकाकरण में भी शिक्षकों ने भरपूर सहयोग किया है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान स्कूलों में बनाए केंद्रों की व्यवस्था का जिम्मा भी शिक्षकों ने संभाला।

स्कूली बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए शिक्षकों ने आनलाइन पढ़ाई भी जारी रखी। आनलाइन पढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन शिक्षकों ने इसे भी सहजता से लिया और बच्चों से हर समय संपर्क में रहे। जिन स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट नहीं था वहां पर बच्चों को घर तक नोट्स पहुंचाने की व्यवस्था की। समय-समय पर बच्चों से टेलीफोन के माध्यम से भी उनकी समस्याओं का निराकरण किया। परीक्षा परिणाम से लेकर अब परीक्षाएं करवाने में भी शिक्षक संस्थानों में जुटे हैं। समाज के हर वर्ग का दायित्व है कि शिक्षकों के योगदान को देख इनका हमेशा सम्मान किया जाए। आशा की जानी चाहिए कि मंत्री के स्पष्टीकरण के साथ ही यह विवाद समाप्त हो गया है।

डिप्टी कमिश्नर तान्या बैंस ने तोड़ा फर्जी बिलिंग माफिया का नेटवर्क

जागरण संवाददाता, लुधियाना

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के लुधियाना कमिश्नरेट में तैनात डिप्टी कमिश्नर तान्या बैंस जीएसटी धोखाधड़ी के मामलों में देश में सर्वाधिक गिरफ्तारियां करने वाली राजस्व अधिकारी बन गई हैं। फर्जी फर्म बनाकर सरकार के राजस्व को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वाले 18 उद्यमियों को गिरफ्तार कर तान्या ने अपने काम का लोहा मनवाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।

तान्या बैंस यह गौरव पाने वाली चंडीगढ़ जोन की पहली अफसर हैं। इस जोन में चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर तक का क्षेत्र आता है। 2016 बैच की इस भारतीय राजस्व अधिकारी (आइआरएस) ने 1599.91 करोड़ के फर्जी बिलिंग के छह केस पकड़े और सौ से ज्यादा फर्जी कंपनियों को निरस्त किया। 192 करोड़ की राजस्व चोरी बचाई। इसमें से 33 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा कराया जा चुका है।

तान्या बैंस ने पटियाला में पहली तैनाती के दौरान ही मंडी गोबिंदगढ़ में स्टील कारोबार में फर्जी बिलिंग का पर्दाफाश किया था। उनकी कार्यशैली को देखते हुए ही सीजीएसटी कमिश्नरेट लुधियाना के प्रिंसिपल कमिश्नर आशुतोष बरनवाल ने उन्हें लुधियाना में एंटी एविजन विंग में तैनात किया। यहां तान्या ने फर्जी बिलिंग के मामलों की पड़ताल शुरू की और जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश कर वर्षों से सक्रिय चार्टर्ड अकाउंटेंट और माफिया की चेन को तोड़ा।

तान्या कहती हैं, 'लुधियाना के फर्जी बिलिंग माफिया पर नकेल डालना काफी मुश्किल था, लेकिन टीम के सहयोग से कामयाबी मिली। इस कामयाबी ने जिम्मेदारी और बढ़ा दी है।'

बोगस बिलिंग का भंडाफोड़ करने के लिए लुधियाना से नोएडा तक काम करने वाली लुधियाना कमिश्नरेट की टीम में तान्या अकेली महिला अफसर थीं। रात दो बजे नोएडा में रेड करने के संबंध में तान्या कहती हैं, 'चार साल के करियर में यह मेरे लिए अनोखा अनुभव था। मन में कुछ शंकाएं भी थीं, लेकिन टीम के अफसरों ने लगातार प्रोत्साहित किया। हमारी टीम तड़के तीन बजे दिल्ली पहुंची। स्पष्ट निर्देश दिए कि तत्काल क्रैक डाउन करना है। इससे हमें कामयाबी मिली।

खास बात यह है कि इस केस में तान्या का अदालत में सामना देश के पूर्व अटार्नी जनरल और पूर्व सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी से हुआ। आरोपितों की अंतरिम जमानत के लिए मुकुल रोहतगी अदालत में थे और तान्या बैंस अपने केस के पक्ष में उनसे बहस करती रहीं। नतीजा यह हुआ कि हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। तान्या कहती हैं, 'यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।'

दबंग अफसर

- जीएसटी धोखाधड़ी की सर्वाधिक गिरफ्तारियां करने वाली अफसर हैं तान्या बैंस
- करोड़ों की फर्जी बिलिंग के छह केस पकड़े, सौ से ज्यादा फर्जी कंपनियां को निरस्त किया


केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के लुधियाना कमिश्नरेट में तैनात युवा महिला डिप्टी कमिश्नर तान्या बैंस। जागरण

आइआइएम देगा पहाड़ से पलायन रोकने का मंत्र

अभय पांडेय, काशीपुर (ऊधमसिंहनगर): पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने में काशीपुर आइआइएम अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इसके लिए आइआइएम ने प्रोग्राम लांच किए हैं। सक्षम व साहस नाम से संचालित प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड से ही कृषि आधारित 40 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 31 जुलाई तक समय दिया गया है। कृषि मंत्रालय चयनित स्टार्टअप को पांच लाख से 25 लाख रुपये तक का फंड देगा। मंत्रालय स्टार्टअप से अनुबंध भी करेगा, जिससे स्थानीय युवाओं का रोजगार मिल सके और पलायन भी थमे।

आइआइएम की विंग फेडरेशन फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रिन्योरशिप (फीड) के डायरेक्टर सफल बत्रा बताते हैं कि हमारा मकसद कोरोनो के दौरान उत्तराखंड लौटे प्रवासियों का स्किल डेवलपमेंट और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर देना है। एक स्टार्टअप तमाम लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनता है। इसी उद्देश्य से कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 'रफ्तार' प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इसमें दो सेक्शन हैं। पहला सक्षम नाम से है और इसमें एग्रीकल्चर स्किल वाले स्टार्टअप का चयन होगा। दूसरा प्रोग्राम साहस है जो नव उद्यमी बनने के इच्छुक युवाओं के लिए है। 2019 व 2020 में इस प्रोजेक्ट से करीब 60 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और अधिकांश युवा स्टार्टअप्स भी शुरू कर चुके हैं।

याचिका दाखिल करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने अनुशासनात्मक जांच के बाद अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए एक पुलिस कांस्टेबल को अनुकंपा पेंशन देने से संबंधित मामले में गुजरात सरकार द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने में देरी किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है और उसकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने गुजरात सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर करने में राज्य सरकार के बहुत विलंब करने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि जिस परिस्थिति में अनुकंपा पेंशन के लिए निर्देश जारी किया गया, वह यह था कि व्यक्ति का एक बच्चा मानसिक दिव्यांग है और दूसरा पोलियोग्रस्त। हाई कोर्ट के एकल जज ने फरवरी, 2017 में प्राधिकरण को 21 मार्च, 2002 से व्यक्ति को अनुकंपा पेंशन देने और आदेश प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर बकाया भुगतान का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया था।

अपील दायर करने के तरीके को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस उपायुक्त, यातायात शाखा, अहमदाबाद और गुजरात के गृह विभाग द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने में 856 दिनों की देरी हुई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि जिस परिस्थिति में गुजरात सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2002 के नियम 78 और 79 के तहत अनुकंपा पेंशन के लिए निर्देश दिया गया, वह यह था कि व्यक्ति का एक बच्चा मानसिक दिव्यांग और दूसरा पोलियोग्रस्त था।

कड़े तेवर

- गुजरात के जबरन सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी की अनुकंपा पेंशन का है मामला
- राज्य सरकार की लेटलतीफी पर कोर्ट नाराज, 25 हजार का अर्थदंड लगाया


शीर्ष अदालत में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने में 856 दिनों की देरी हुई। फाइल/इंटरनेट मीडिया

हम देरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते : पीठ

पीठ ने पांच जुलाई के आदेश में कहा कि गुजरात राज्य ने खंडपीठ के समक्ष 200 दिनों की देरी के साथ मामले को रखा और अब 856 दिनों की देरी के साथ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका में हमारे सामने है। पीठ ने कहा कि हम देरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इस तरह उस तरीके को अस्वीकार करते हैं जिसमे गुजरात राज्य ने विलंब के साथ इस अदालत का रुख किया और विलंब किए जाने के आधार पर विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता को चार हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के पास 25 हजार रुपये की राशि जमा करनी होगी। एकल न्यायाधीश द्वारा फरवरी, 2017 में दिए गए फैसले के बाद प्राधिकरण ने जुलाई, 2018 में खंडपीठ का रुख किया जिसने 200 दिन की देरी के आधार पर आवदेन खारिज कर दिया था।

'व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जमानत अर्जी सुनना जरूरी'

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों, जिला अदालत के न्याय के दरवाजे जनता की पहुंच से बाहर नहीं रख सकते। ऐसा करना न केवल पहले से जूझ रहे हाई कोर्ट पर बोझ बढ़ाना है अपितु कोविड में आर्थिक संकट का सामना कर रहे लोगों को हाई कोर्ट आने का खर्च उठाने के लिए विवश करना है।

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने फैजान इलाहाबादी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए की है। कोर्ट ने कहा कि जब पुलिस अपराधियों को पकड़कर रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकती है और वह जेल भेज सकते हैं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए अदालत क्यों नहीं बैठ सकती। अलीगढ़ जिला अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करने में असमर्थ याची ने सीधे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुनवाई की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने याची को अपना आपराधिक इतिहास दाखिल करने का समय दिया। राज्य सरकार की तरफ से आपत्ति की गई है।

- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, कितनी भी विषम स्थिति हो न्याय के दरवाजे जनता की पहुंच से बाहर नहीं रख सकते


टिप्पणी की : इलाहाबाद हाई कोर्ट। फाइल

मामले में अगली सुनवाई अब नौ जुलाई को होगी। यह अर्जी 19 मई, 2021 को दाखिल की गई। इसमें कहा गया कि अलीगढ़ जिला अदालत में कोरोना लाकडाउन के कारण केवल आनलाइन वर्चुअल सुनवाई हो रही है, यही कारण बताते हुए अर्जी स्वीकार नहीं की गई। सरकारी वकील ने यह कहते हुए आपत्ति की कि याची ने एक ही अपराध का जिक्र किया है, जबकि उसके खिलाफ पांच आपराधिक केस का इतिहास है। कोर्ट ने याची को दर्ज अपराधों का विवरण देने का निर्देश दिया है।

यात्रियों को मिलेंगी हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं

योग नगरी स्टेशन

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद

योग नगरी (न्यू ऋषिकेश) रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन यहां मिलने वाली कोई भी सुविधा निःशुल्क नहीं होगी। जिस सुविधा का उपयोग करेंगे, उसके लिए भुगतान करना होगा। इस स्टेशन की व्यवस्था इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन (आइआरएसडीसी) के हवाले करने की तैयारी है। मुरादाबाद रेल मंडल प्रशासन ने योग नगरी स्टेशन को आइआरएसडीसी को सौंपे जाने के लिए पत्र भेजा है। माना जा रहा है कि दो से तीन माह में आइआरएसडीसी योग नगरी रेलवे स्टेशन का अधिग्रहण कर लेगी।

चारधाम यात्रा के लिए दो स्थान से रेल मार्ग निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में बद्रीनाथ-केदारनाथ रेल मार्ग का निर्माण शुरू हो गया है। इस मार्ग का पहला स्टेशन न्यू ऋषिकेश में बनाया गया है। इसे योग नगरी स्टेशन नाम दिया है। रेलवे स्टेशन से पिछले साल ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। वर्तमान में इस स्टेशन का संचालन व रखरखाव मुरादाबाद मंडल रेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। योग नगरी स्टेशन की सफाई आदि पर प्रत्येक साल 20 से 25 करोड़ रुपये का खर्च है। इतनी ही राशि रखरखाव पर खर्च की जा रही है। इनके अलावा अन्य खर्च भी हैं। इतना खर्च होने के बावजूद वर्तमान में यात्री सुविधा बेहद कम हैं। मंडल रेल प्रशासन ने योग नगरी स्टेशन का खर्च उठाने से बचने के लिए इसे इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन को सौंपने को पत्र रेलवे बोर्ड को भेजा है।

प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि पिछले सप्ताह योग नगरी स्टेशन को आइआरएसडीसी को सौंपने के संबंध में रेलवे बोर्ड को पत्र भेज दिया है।

आइपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली लगाई गई

नई दिल्ली, एएनआइ : यात्रियों खासकर महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे और उसके सार्वजनिक उद्यम रेलटेल ने 813 बड़े स्टेशनों पर आइपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की है। मार्च, 2022 तक देश के 756 और रेलवे स्टेशनों पर यह प्रणाली लगा दी जाएगी। 47 स्टेशनों पर इसकी स्थापना का कार्य शीघ्र पूरा होने जा रहा है।

रेलटेल की ओर से जारी बयान के अनुसार ए1, ए, बी, सी, डी व ई श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकाल (आइपी) आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिनकी संख्या करीब 5,000 है। इस परियोजना के लिए 25 जून, 2020 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। रेलवे स्टेशनों और राष्ट्रीय सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही इस प्रणाली में सीसीटीवी कैमरे आप्टिकल केबल नेटवर्क के जरिये आपस में जुड़े होंगे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को न सिर्फ संबंधित स्टेशनों के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) पोस्ट पर, बल्कि समानांतर रूप से डिवीजनल और जोनल दफ्तरों के केंद्रीकृत सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष में भी देखा जा सकेगा। इन कैमरों की तीन स्तरों पर निगरानी की जाएगी। इसके लिए रेलटेल की तरफ से 14 जोनल रेलवे में केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा चुकी है। नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम (एनएमएस) के जरिये अधिकृत व्यक्ति कैमरा, सर्वर, यूपीएस व स्वीच की निगरानी कर सकेगा।

विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कराएगी नई ग्लोबल कंसल्टेंट एजेंसी

रविप्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या

रामनगरी को ग्लोबल टूरिज्म हब के रूप में प्रतिष्ठित करने में उप्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अयोध्या को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए जहां ग्लोबल कंसल्टेंट एजेंसी से विजन डाक्युमेंट तैयार कराया गया, वहीं अब इसके क्रियान्वयन के लिए भी विश्वस्तरीय सलाहकार संगठन का चयन होगा। विजन डाक्युमेंट में रामनगरी के लिए समग्र विकास की परिकल्पना तैयार हो चुकी है। अब अगला लक्ष्य इन योजनाओं के क्रियान्वयन का है। शासन स्तर से नीति तय होने लगी है। ली एसोसिएट्स की भांति ही क्रियान्यवन के लिए भी एक नई कंसल्टेंट एजेंसी होगी, जिसके चयन को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण इसी हफ्ते रिक्वेस्ट फार प्रपोजल जारी करेगा। शासन के निर्देशानुसार रामनगरी के विकास कार्य को शीघ्र धरातल पर उतरना है। फरवरी से ली एसोसिएट्स ने विजन डाक्युमेंट तैयार करने का कार्य आरंभ किया था। अगस्त में ली एसोसिएट्स से किया गया अनुबंध पूरा हो रहा है। प्राधिकरण 15 जुलाई से विजन डाक्युमेंट में शामिल मल्टीलेवल पार्किंग सहित अन्य योजनाओं पर कार्य शुरू कराने



की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे पहले कंसल्टेंट एजेंसी का चयन किया जाना है। क्रियान्यवन के लिए चयनित होने वाली एजेंसी का दायित्व विजन डाक्युमेंट की प्लानिंग के अनुसार विभागों से समन्वय बनाकर विकास कार्यों को पूरा कराना होगा। शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह की मंगलवार को लखनऊ में बैठक भी हो चुकी है। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष विशाल सिंह कहते हैं कि रामनगरी के विकास का खाका ग्लोबल कंसल्टेंट एजेंसी ने खींचा है। इसके क्रियान्वयन के लिए भी ग्लोबल कंसल्टेंट एजेंसी की आवश्यकता पड़ेगी।

रामनगरी में मुख्य मार्गों पर स्थित भवनों में एकरूपता लाने के लिए स्कीम तैयार हो रही है। ली एसोसिएट्स की सहयोगी संस्था सीपी कुकरेजा इसकी प्लानिंग कर रही है।

508 घटनाएं इस साल अभी तक दर्ज की गई हैं दुनिया भर में डाक्टरों या स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले की विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। इनमें से 240 हमले सिर्फ म्यांमार में हुए हैं।

अफगानिस्तान में जंग तेज, बादगीस की राजधानी में घुसा तालिबान

संघर्ष ▶ गनी ने कहा, 100 साल में भी सरकार से समर्पण नहीं करा सकते आतंकी

10 हजार कमांडो के साथ ब्लैक हाक हेलिकाप्टर भी किए तैनात

काबुल, एएनआइ : अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच निर्णायक जंग छिड़ गई है। बुधवार को तालिबान के सैकड़ों आतंकी बादगीस प्रांत की राजधानी काला-ए-नव में प्रवेश कर गए और पुलिस मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। संघर्ष के दौरान यहां जेल में बंद कैदी फरार हो गए। पिछले 24 घंटों में तालिबान ने छह जिलों पर कब्जा कर लिया है। वहीं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबान आतंकी अपने इरादों में सफल नहीं होंगे, वे अगले सौ साल में भी सरकार से समर्पण नहीं करा सकते। उन्होंने परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, देश में रक्तपात के लिए तालिबान और उसके हमदर्द देश जिम्मेदार हैं। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब ने बताया कि सुरक्षा बलों की सहायता के लिए सात ब्लैक हाक हेलिकाप्टर तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों के साथ दस हजार अफगान कमांडो आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए सक्रिय हैं।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ से अधिक तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। तालिबान ने दावा किया है कि इसी अवधि में उन्होंने छह जिलों पर कब्जा कर लिया है।



अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच छिड़ी निर्णायक लड़ाई के बीच बादगीस प्रांत की राजधानी काला-ए-नव में तैनात अफगान सुरक्षा बलों के जवान। एएफपी

ईरान ने शुरू की तालिबान और अफगान सरकार के बीच मध्यस्थता

एपी के अनुसार ईरान ने तेहरान में अफगान प्रतिनिधिमंडल और तालिबान के साथ वार्ता शुरू करा दी है। दोनों के बीच दोहा में लंबे समय से वार्ता चल रही थी और इसमें गतिरोध आ रहा था। तालिबान का नेतृत्व शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई कर रहे हैं। अफगान सरकार की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति यूनूस कानूनी नेतृत्व कर रहे हैं।

बीआरआइ का विस्तार करने के लिए निवेश के वहाने अफगानिस्तान में घुसना चाहता है ड्रैगन

एएनआइ के अनुसार, अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही चीन अफगानिस्तान में तेजी से सक्रिय हो रहा है। वह यहां निवेश की संभावना देख रहा है। उसकी योजना यहां बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव(बीआरआइ)का विस्तार करने की है। काबुल की बीजिंग से निरंतर वार्ता चल रही है।

अफगान में बिगड़ती स्थिति के बीच सीमावर्ती देशों को रूस ने दिया सुरक्षा का भरोसा

रायटर के अनुसार रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने मध्य एशिया के सहयोगी देशों की सुरक्षा का वादा किया है। सर्गेई ने कहा है कि अफगानिस्तान की बिगड़ती स्थिति के बीच हम अपने सहयोगी देशों को पूरी सुरक्षा देंगे। रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री एमोमली रहमन से भी वार्ता की।

तीन सौ अफगान सैनिक ताजिकिस्तान से वापस लौटे : कुछ दिन पहले तालिबान के साथ संघर्ष में कमजोर पड़ने के बाद ताजिकिस्तान भाग गए अफगान सैनिक अब वापस लौट रहे हैं। बुधवार को तीन सौ सैनिक वापस लौट आए।

गृहयुद्ध हुआ तो पांच लाख अफगान शरणार्थी पहुंचेंगे पाकिस्तान: पाकिस्तान की सरकार ने अनुमान लगाया है कि अफगानिस्तान में गृहयुद्ध हुआ तो उसकी सीमा में करीब पांच लाख शरणार्थी आ सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि इस बार इन शरणार्थियों को देश के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र में ही शिविर लगा दिए जाएंगे।

अमेरिका की 90 फीसद सेना वापस: अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका की अफगानिस्तान में तैनात 90 फीसद सेना वापस लौट चुकी है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और मित्र देशों की सेना की वापसी का क्रम शुरू होने के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान और सुरक्षाकर्मियों में जंग तेज हो गई है।

आतंकवादियों को अपने और तेरे में बांटकर पुराने युग में न लौटें : भारत

▶ संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को किया आगाह, मिलकर प्रयास करने से ही आतंकवाद का खात्मा संभव

न्यूयार्क, प्रेट्र: भारत ने आगाह किया है कि अमेरिका में 9/11 के हमले के बीस साल बाद फिर आतंकवादियों को हिंसक राष्ट्रवाद और दक्षिणपंथी उग्रवाद जैसी भ्रम फैलाने वाली शब्दावली का प्रयोग कर वास्तविक उद्देश्य से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। हम उस युग में न लौटें, जब मेरे आतंकवादी और तुम्हारे आतंकवादी कहकर गुमराह किया जाता रहा है। वर्तमान में मिलकर आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है।

संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद निरोधी रणनीति पर समीक्षा के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया गया है कि आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है। यह भी तय है कि आतंकवाद को सभी देशों के संयुक्त प्रयासों से ही पराजित किया जा सकता है।



टीएस तिरुमूर्ति। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

संयुक्त प्रयासों से ही आतंकवाद का मुकाबला संभव : उन्होंने कहा कि 9/11 के हमले के बाद ही हमने माना था कि एक हिस्से में पनपा आतंकवाद दुनिया के दूसरे हिस्से को प्रभावित कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह याद रखना होगा कि इस हमले से पहले मेरे आतंकवादी और तुम्हारे आतंकवादी जैसी ही स्थिति थी। जिस तरह से पहले आतंकवाद के मसले पर देश विभाजित थे, एक बार फिर उसी तरह का प्रयास किया जा रहा है। आतंकवाद का मुकाबला संयुक्त प्रयासों से ही संभव होगा।

दलाई लामा के नाम से न्यूयार्क में खोला जाएगा पुस्तकालय

वाशिंगटन, प्रेट्र : तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा की 86 वीं जन्म तिथि पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने उन्हें बधाई दी। ब्लिंकन ने कहा कि दलाई लामा ने पूरी दुनिया को करुणा, समानता और साथ मिलकर चलने का संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने भी दलाई लामा की जन्म तिथि पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी कृपा और करुणा ने हम सभी को प्रेरणा दी है।

उनकी जन्म तिथि पर न्यूयार्क में एक पुस्तकालय स्थापित करने की भी घोषणा की गई। यह घोषणा न्यूयार्क के इथाका में नामग्याल मठ ने की। इस पुस्तकालय की स्थापना में खर्च होने वाले 50 लाख डालर (करीब 37 करोड़ रुपये) के लिए फंड इकट्ठा किया जाएगा। दलाई लामा पुस्तकालय के साथ ही अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इथाका में नामग्याल मठ के अध्यक्ष तेनजिंग चोएसांग ने बताया कि दलाई लामा पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र मानवता के लिए कार्य करेगा। यह पुस्तकालय 9240 वर्ग फीट एरिया में होगा। इसमें पिछले और वर्तमान सभी दलाई लामा के किए गए कार्यों की जानकारी मिल सकेगी। पुस्तकालय आनलाइन भी जनता के लिए उपलब्ध होगा।



दलाई लामा की फाइल फोटो। इंटरनेट मीडिया

स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में पहुंचेंगी जिल बाइडन

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन फ्लोरिडा के आरलैंडो में 8 जुलाई को होने जा रही स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता के फाइनल में बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचेंगी। यह जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है। अमेरिका में बीस साल से आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भारतीय मूल के बच्चों का दबदबा रहता है। इस बार भी फाइनल के लिये चयनित 11 बच्चों में से नौ भारतीय-अमेरिकन हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि स्पेलिंग बी प्रतियोगिता के फाइनल के बाद राष्ट्रपति जो बाइडन विजयी बच्चों और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। प्रतियोगिता आरलैंडो के वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजार्ट में हो रही है। स्पेलिंग बी शब्दों की एक प्रतियोगिता है, जिसमें बच्चों से अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी पूछी जाती है।

न्यूज गैलरी

इजरायल में गूंजा 'केशव माधव हरि-हरि बोल' भजन

तेलअवीव : इजरायल में भारतीय संगीतकारों के साथ आयोजित एक कार्यक्रम में इजरायली नागरिकों ने भारत के साथ एकजुटता का संदेश दिया। तेलअवीव के हबीमा स्क्वायर में आयोजित कार्यक्रम में भजन 'केशव माधव हरि हरि बोल' भी गूंजा। इसको अतीव भंसाली ने वोरफ्रूट समुदाय के आशीष रागवानी के साथ गाया। इजरायल में भारतीय संगीत को बहुत पसंद किया जाता है। (प्रेट्र)

फ्रांस में किशोरी को आनलाइन धमकी में 11 लोगों को सजा

पेरिस : फ्रांस की एक अदालत ने एक किशोरी की इस्लाम के खिलाफ आनलाइन पोस्ट पर धमकी देने वाले 13 में से 11 लोगों को जेल भेज दिया। पेरिस में जनवरी में आनलाइन मामलों में धमकी और उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत में यह अपने तरीके का पहला मामला था। अदालत ने सभी दोषी लोगों को चार से छह माह जेल की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया। (एपी)

शिकागो में तीन अधिकारियों को गोली मारकर घायल किया

शिकागो : शिकागो में तीन कानून प्रवर्तन अधिकारियों को गोली मारकर घायल कर दिया गया। यह घटना शिकागो पुलिस स्टेशन के बाहर हुई। स्थानीय मीडिया के अनुसार इन तीनों ही अधिकारियों के कोई गंभीर चोट नहीं आई है। तीनों खतरे से बाहर हैं। (एपी)

द. अफ्रीका में भारतवंशी रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता का निधन

जोहानिसबर्ग : दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में रंगभेद का विरोध करने वाली वयोवृद्ध कार्यकर्ता मनीबेन सीता का बुधवार को निधन हो गया। उनको कोरोना से संक्रमित होने के बाद अन्य तरह की दिक्कतें हो गई थीं। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। 94 वर्षीय मनीबेन के नाना गांधी जी के साथ रहे थे, जो बाद में प्रिटोरिया आकर बस गए। (प्रेट्र)

परमाणु हथियार बनाने की तैयारी करने लगा ईरान

▶ आइएइए ने कहा, संवर्धित यूरेनियम धातु बनाना किया शुरू

▶ अमेरिका और यूरोपीय देशों में बढ़ने लगी बेचैनी

वियना, रायटर: संयुक्त राष्ट्र की निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएइए) ने कहा है कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम धातु बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम ईरान को परमाणु हथियार बनाने की ताकत देगा। इस जानकारी के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों में चिंता बढ़ गई है।

ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि ईरान का यह कदम 2015 के समझौते पर वापस लौटने में दिक्कत पैदा कर सकता है। इस कदम से अमेरिका से उसकी वार्ता और पेचीदा हो जाएगी। तीनों यूरोपीय देशों ने कहा, ईरान संवर्धित यूरेनियम तैयार करके परमाणु समझौते का उल्लंघन कर रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा, परमाणु समझौते को लेकर वियना में चल रही वार्ता के छह चरण हो चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, वार्ता के लिए अंतिम सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन ईरान के इस कदम से हमारे परमाणु समझौते पर लौटने के विचार पर असर पड़ेगा। रूस ने कहा, इसका एक मात्र हल वियना वार्ता में तेजी लाना है।

ईरान ने कहा, सऊदी अरब के साथ वार्ता में प्रगति : आइएएनएस के अनुसार ईरान सरकार के प्रवक्ता अली रब्बी ने कहा है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रही वार्ता में प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि हम मतभेदों को कम करने के लिए वार्ता जारी रखेंगे।

हैती में राष्ट्रपति मौसे की गोली मारकर हत्या

▶ राजनीतिक अस्थिरता के बीच चला रहे थे सरकार, देश के कई इलाकों में हिंसा, आपातस्थिति लागू

पोर्ट-अऊ-प्रिंस, रायटर : हैती में राष्ट्रपति जोवेनेल मौसे (53) की मंगलवार रात उनके निजी आवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में पत्नी मार्टिनी मौसे गंभीर रूप से घायल हुई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी देश के अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ ने दी है। उन्होंने घटना को घृणास्पद, अमानवीय और बर्बर करार दिया है। विश्वास जताया है कि लोकतंत्र की जीत होगी। देर शाम मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर जोसेफ ने देश में आपातस्थिति की घोषणा कर दी।

अभी तक की जांच में पता चला है कि मध्य रात्रि में स्पेनिश बोल रहे अज्ञात बंदूकधारियों ने आवास में घुसकर फायरिंग की। मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। राष्ट्रपति की हत्या के बाद हालात पर नियंत्रण के लिए नेशनल पैलेस और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। राजधानी पोर्ट-अऊ- प्रिंस में ज्यादातर दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। कुछ जगह तोड़फोड़ और हिंसा होने की खबर है। पड़ोसी देश डोमिनिकन रिपब्लिक ने हैती से लगने वाली अपनी सीमा पर आवागमन रोक दिया है।



जोवेनेल मौसे की फाइल फोटो। एएफपी

बाइडन और जॉनसन ने जताया शोक

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने मौसे की हत्या पर शोक जताया है। कहा है कि उन्हें हैती के राष्ट्रपति की हत्या से आघात लगा है, वह बहुत दुखी हैं। जाहिर तौर पर यह यह जघन्य वारदात है। अमेरिका सुरक्षित और सुखी हैती के लिए सहयोग को तैयार है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी राष्ट्रपति मौसे की हत्या पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

मौसे 2017 में राष्ट्रपति बने थे और पिछले दो साल से राजनीतिक अस्थिरता के बीच सरकार चला रहे थे। फरवरी 2021 में सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाने के बावजूद हैती में चुनाव नहीं हुए। संसद भंग अवस्था में है। विपक्ष ने उन पर अधिकारों में इजाफा कर निरंकुश शासन चलाने का आरोप लगाया था। मौसे पर सरकारी ठेकों में मनमानी करने और स्वतंत्र खुफिया संगठन गठित कर विपक्ष और विरोधियों की खुफियागीरी कराने के आरोप लगे थे। विपक्ष महीनों से उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। वैसे हैती के चुनाव आयोग ने हाल ही में इस साल के अंत में चुनाव कराने की घोषणा की है।

वैसे एक करोड़ दस लाख की आबादी वाले इस कैरेबियाई देश में लंबे समय तक अशांति रही है। हिंसा के चलते देश में गरीबी और भुखमरी की समस्या रही है। 2010 में आए भूकंप और 2016 में आए समुद्री तूफान मैथ्यू की वजह से हालात और बिगड़ गए। देश की 60 प्रतिशत आबादी की आमदनी दो डॉलर (करीब 150 रुपये) से भी कम है। हैती को सबसे ज्यादा अमेरिका से आर्थिक मदद मिलती है। हैती 19 वीं सदी में फ्रांसीसी उपनिवेश से मुक्त हुआ था।

जयशंकर ने ईरान के नए राष्ट्रपति से मुलाकात की

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ मास्को जाते तेहरान में रुक नए राष्ट्रपति को दिया मोदी का संदेश, ईरान में चल रही है तालिबान के साथ शांति वार्ता

ऐसे समय जब ईरान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटाने को लेकर बातचीत चल रही है तब भारत ने भी ईरान के साथ अपने रिश्तों को पटरी पर लाने की पहल शुरू कर दी है। बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर तेहरान पहुंचे और ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री जवाद जरीफ से मुलाकात की और द्विपक्षीय रिश्तों पर अहम चर्चा की। भारत पहला देश हो गया है जिसने ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद अपने विदेश मंत्री को नए राष्ट्रपति से मिलने के लिए भेजा है।

जयशंकर वैसे तो रूस की यात्रा पर हैं और इस बीच उन्होंने तेहरान की कुछ घंटे की यात्रा की। जयशंकर की गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक है। नए राष्ट्रपति रईसी से मुलाकात के बाद जयशंकर ने बताया कि मैंने निर्वाचित राष्ट्रपति रईसी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा काफी अच्छा स्वागत किया। मैंने उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संदेश दिया है। मैं भारत के प्रति उनकी गर्मजोशी की प्रशंसा करता हूं। भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने व क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को प्रगाढ़ करने के प्रति उनके मजबूत प्रतिबद्धता की भी प्रशंसा करता हूं। जयशंकर ने बताया है कि उनकी विदेश मंत्री जरीफ से भी मुलाकात हुई। दोनों ने क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। जयशंकर के अचानक की तेहरान पहुंचने को वहां चल रही तालिबान शांति वार्ता से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। दो दिनों से ईरान सरकार के नेतृत्व में तालिबान व अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है। अफगानिस्तान में बदल रहे हालात के मद्देनजर ईरान का सहयोग भारत के लिए ज्यादा जरूरी हो गया है। भारत अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार पोर्ट से जोड़ने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है। अगर वहां तालिबान सत्ता पर काबिज होता है तो इस योजना में रुकावट आ सकती है।



ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बुधवार को तेहरान में मुलाकात करते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। एएनआइ

अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे डेल्टा वैरिएंट के मरीज

▶ सप्ताह के अंत तक 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक

▶ ब्रिटेन में जनवरी के बाद सबसे ज्यादा मरीज



अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित विननेटका में वैक्सीन लगवाती छात्रा। एएफपी

ह्यूस्टन, प्रेट्र : अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां आधे से ज्यादा मामले सिर्फ डेल्टा के ही हैं। उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि इस सप्ताह के अंत तक 16 करोड़ लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों खुराक दे दी जाएगी।

अमेरिका में सेंटर फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने कहा है कि 51 फीसद लोगों में डेल्टा वैरिएंट मिल रहा है। कुछ राज्यों में तो यह अस्सी फीसद तक फैला हुआ है। जो बाइडन ने कहा है कि जनवरी से अब तक मौतों की संख्या में 90 फीसद तक कमी आई है।

ब्रिटेन में 24 घंटों के दौरान 28 हजार से ज्यादा केस: ब्रिटेन में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटों के दौरान 28 हजार से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। यह संख्या जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा है कि 16 अगस्त के बाद ब्रिटेन में यदि कोई नागरिक वैक्सीन की दो खुराक लेने के बाद संक्रमित मरीज के संपर्क में आ भी जाता है, तो उसे सेल्फ आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं होगी। जो लोग 16 अगस्त के आसपास दोनों खुराक पूरी करेंगे, उन्हें दूसरी खुराक लेने के बाद दो सप्ताह इंतजार करना होगा।

आस्ट्रेलिया : रायटर के अनुसार सिडनी में एक सप्ताह के लिए लाकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब यह 16 जुलाई तक जारी रहेगा।

दक्षिण कोरिया : सियोल में आवाजाही पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। यहां दोबारा पाबंदियां लगाने पर विचार किया जा रहा है।

श्रीलंका : यहां एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अनुपलब्धता पर दूसरी खुराक फाइजर की लेने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि अभी दुनिया में दो अलग अलग वैक्सीन की खुराक लेने के बारे में अध्ययन किया जा रहा है।

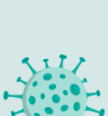
सिंगापुर : कोरोना संक्रमण में कमी के बाद सोमवार से पाबंदियों में ढील दी जाएगी।

तीस देशों में फैला नया स्ट्रेन लैम्डा

एएनआइ के अनुसार ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि डेल्टा से भी खतरनाक स्ट्रेन लैम्डा 30 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह स्ट्रेन पेरू से शुरू हुआ था। पेरू में इसी स्ट्रेन के कारण सबसे ज्यादा मृत्यु दर हो गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार ब्रिटेन में अब तक छह मामले लैम्डा के मिल चुके हैं।

कोरोना को हराना है

टीकों की एक डोज संक्रमण के जोखिम को 81 फीसद तक कम करती है, वैक्सीन लोगों में लक्षणों की गंभीरता और संक्रमण अवधि को भी कम करती हैं



फाइजर, माडर्ना के टीकों ने कोरोना के खतरे को 91 फीसद कम किया

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में किए गए एक अध्ययन के अनुसार जिन लोगों ने फाइजर और माडर्ना के कोरोना टीकों की डोज ली हैं उनमें यह बीमारी होने की संभावना 91 प्रतिशत तक कम होती है। अध्ययन के अनुसार ये टीके लोगों में लक्षणों की गंभीरता और संक्रमण अवधि को भी कम करते हैं।

यह अध्ययन 30 जून को 'न्यू इंग्लैंड जर्नल आफ मेडिसिन' में प्रकाशित हुआ है। फाइजर और माडर्ना के एमआरएनए टीकों में लोगों की कोशिकाओं के लिए सार्स-सीओवी -2 की स्पाइक प्रोटीन बनाने के वास्ते अनुवांशिक शक्ति होती हैं। स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से ही वायरस मानव कोशिकाओं में पहुंचता है और उसे संक्रमित करता है।

अध्ययन में कहा गया है, 'हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली तब स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का निर्माण करती है, और यह सीखती है कि अगर भविष्य में हम संक्रमित होते हैं तो तो कोरोना वायरस से कैसे लड़ें।'

अमेरिका के उताह विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर और अध्ययन के सह-लेखक सारंग यून ने कहा, 'इस अध्ययन के बारे में एक अनोखी बात यह है कि इसने टीकों के दूसरे लाभों के बारे में विचार किया।'

अग्रिम मोर्चे के कर्मियो, चिकित्सकों और नर्सों के बीच संक्रमण के खतरे और दरों को मापने के लिए यह अध्ययन किया गया। यून ने कहा, 'ये वे लोग हैं जो दिन-प्रतिदन वायरस के संपर्क में आ रहे हैं, और टीकों ने उन्हें इस बीमारी से बचा लिया। जो लोग टीकाकरण के बावजूद दुर्भाग्य से कोविड-19 से संक्रमित हुए, वे अभी भी उन लोगों की तुलना में बेहतर थे जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया है।'

अध्ययन में पाया गया कि दूसरी डोज के दो सप्ताह बाद प्रतिभागियों को 'पूरी तरह से' टीका लगाए जाने के बाद एमआरएनए कोविड-19 टीके संक्रमण के जोखिम को कम करने में 91 प्रतिशत प्रभावी थे। अध्ययन में यह भी पाया गया कि टीके की पहली डोज लिए जाने के दो सप्ताह बाद 'आंशिक' टीकाकरण से संक्रमण का जोखिम कम करने में 81 प्रतिशत प्रभावी हैं।

अध्ययन में 3,975 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों ने 13 दिसंबर, 2020 और 10 अप्रैल, 2021 के बीच 17 सप्ताह के लिए साप्ताहिक आधार पर कोविड-19 परीक्षण के लिए नमूने दिये। प्रतिभागियों में से केवल 204 (पांच प्रतिशत) अंततः वायरस सार्स-सीओवी-2 से संक्रमित पाए गए और यही वायरस कोविड-19 का कारण बनता है। इनमें से 156 का टीकाकरण नहीं हुआ था, 32 के बारे में टीका लगाए जाने को लेकर अनिश्चित स्थिति थी, और 16 को पूरी तरह या आंशिक रूप से टीका लगाया गया था।



टीका लेने वालों में हल्के लक्षण

पूरी तरह से या आंशिक रूप से टीका लगाने वाले प्रतिभागियों में उन लोगों की तुलना में हल्के लक्षण थे, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था। जिन लोगों ने टीका लगवाया है और उनके इस वायरस से संक्रमित होने की स्थिति में उनमें बुखार होने की आशंका 58 प्रतिशत कम हो गई और बिस्तर पर बीमार पड़े रहने के दिनों में 60 प्रतिशत की कमी आई।

टीकाकरण के दूसरों में संक्रमण फैलाने की आशंका कम होती है

अध्ययन के निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि पूरी तरह या आंशिक रूप से टीकाकरण कराने वाले लोग यदि कोविड-19 से संक्रमित होते हैं तो उनके दूसरों में वायरस फैलाने की आशंका कम हो सकती है।

मोराता विलेन तो डोनारूमा व जोरगिन्हो बने हीरो

गोलकीपर डोनारूमा ने पेनाल्टी शूट आउट में दो गोल बचाए, जोरगिन्हो ने स्पेन के खिलाफ गोल दागकर इटली को फाइनल में पहुंचाया



गोल करने के बाद खुश जोरगिन्हो • एएफपी

लंदन, एपी : यूरो कप के महत्वपूर्ण सेमीफाइनल में इटली के गोलकीपर जियानलुइगी डोनारूमा और जोरगिन्हो जहां टीम के लिए हीरो साबित हुए तो वहीं, स्पेन के फारवर्ड अल्वारो मोराता टीम के विलेन बन गए। इटली को जीत दिलाने में डोनारूमा ने दो बार टीम को पेनाल्टी में गोल खाने से बचा लिया तो जोरगिन्हो ने टीम के लिए विजयी गोल दागकर अपने प्रशंसकों को जश्न मनाने का मौका दे दिया। उधर, जब मैच में स्पेन की टीम एक गोल से पिछड़ रही थी तब स्थानापन्न खिलाड़ी मोराता ने गोल करके 90 मिनट के खेल में टीम को हारने से बचा लिया लेकिन, शूट आउट में गोल नहीं करने से वह टीम के विलेन साबित हुए।

इटली ने अपने दमदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए शूट आउट में मुकाबला 4-2 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई। वह टूर्नामेंट में अभी तक हारी नहीं है। इस मैच से भी यह देखा जा रहा था कि कौन सी टीम अजेय रहती है और इसमें इटली ने बाजी मार ली। इस मैच से पहले स्पेनिश टीम 13 मैचों से हारी नहीं थी। इटली के लिए यह प्रदर्शन सपने से कम नहीं है क्योंकि टीम 2018 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही थी।

जोरगिन्हो का अंदाज : पेनाल्टी में इटली 3-2 से आगे था और स्कोर बराबर करने के लिए दारोमदार मोराता के कंधों पर था। लेकिन डोनारूमा ने उनकी पेनाल्टी किक को रोका जिसके बाद जोरगिन्हो ने पेनाल्टी को गोल में बदलकर टीम को जीत दिला दी। मोराता से पहले डोनारूमा ने ओल्मो की पेनाल्टी को भी रोका था। चेल्सी के मिडफील्डर जोरगिन्हो का पेनाल्टी पर शाट खेलने का अपना तरीका है। वह धीरे से आगे आते हैं, रुकते हैं और गेंद के पास कूदकर शाट मारते हैं। इटली का सामना इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच होने वाले अन्य सेमीफाइनल के मुकाबले के विजेता से होगा जहां राबर्टो मेनसिनी की टीम इटली दूसरी बार खिताब जीतने की कोशिश करेगी।

ओह मोराता : मोराता को पहली बार टूर्नामेंट के दौरान शुरुआती एकादश में जगह नहीं मिली। मोराता पेनाल्टी पर चूकने से बली का बकरा बन सकते हैं। उन्होंने कहा, 'यह टीम कई चीजें पाने की हकदार है। स्पेन की तरह मेरा भी सपना फाइनल में जाने का था लेकिन, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मुझे इस टीम पर गर्व है।' मोराता की इस टूर्नामेंट में इसलिए आलोचना हो रही थी कि वह गोल पोस्ट के सामने से गोल नहीं कर पा रहे थे। यह पहली बार है जब स्पेनिश टीम यूरो और विश्व कप के सेमीफाइनल में हारी है। मोराता इस टूर्नामेंट में छह मैचों में छह गोल कर चुके हैं लेकिन वह अहम मौकों पर चूके भी हैं। वह स्लोवाकिया के खिलाफ भी पेनाल्टी पर गोल नहीं कर पाए थे जिसके बाद स्पेनिश प्रशंसकों ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने तक की धमकी दी थी। फिर वह पोलैंड के खिलाफ शानदार मौके पर गोल नहीं कर पाए थे।

पहला हाफ गोलरहित रहा : पहले हाफ में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई। स्पेन की टीम के पास गेंद ज्यादा समय तक रही, लेकिन उनके खिलाड़ियों के शाट गोल बाक्स में नहीं जा पाए। 15वें मिनट में स्पेनिश खिलाड़ी टोरेस ने बाक्स के बाहर से गेंद पर किक लगाई लेकिन, उनका शाट गोल पोस्ट के दायीं ओर से चला गया। फिर 20वें मिनट में इटली के पास गोल करने का अच्छा मौका था जब काइरो इमोबिल ने गेंद नाइकोलो बैरेला को पास की लेकिन, वह गेंद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और गोल करने का मौका गंवा दिया।

फिर 1-1 से बराबर : इस हाफ में इटली की टीम ने अपने अंदाज में खेलना शुरू किया। 60वें मिनट में इटली के फेडरिको चिएसा ने शानदार गोल दागकर अपने प्रशंसकों को स्टेडियम में झूमने का मौका दे दिया। चिएसा ने बाक्स के अंदर से दायें पैर से गेंद पर जोरदार किक लगाई और गेंद स्पेनिश गोलकीपर को छकाते हुए पोस्ट के अंदर दायीं ओर चली गई। इटली मैच में 1-0 से आगे हो गया। जब स्पेन एक गोल से पिछड़ रही थी तब एनिरक ने 62वें मिनट उन्हें टोरेस की जगह मोराता को मैदान पर भेजा और उन्होंने 80वें मिनट में गोल दागकर टीम की मैच में शानदार वापसी करा दी और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। ओल्मो ने एक अच्छा पास मोराता की तरफ भेजा और उन्होंने गोल दाग दिया।

गेंद रखी

35% 65%

इटली		स्पेन
22	फ्री किक	34
01	कार्नर किर	06
03	गोलकीपर बचाव	03
02	यलो कार्ड	01
418	कुल पास	932

पेनाल्टी शूटआउट

4 vs 2

इटली		स्पेन	
लोकेटेली	✗	ओल्मो	✗
बेलौटी	✓	मोरेनो	✓
लियोनार्डो	✓	अलसांटरा	✓
बेर्नार्डेशी	✓	मोराता	✗
जोरगिन्हो	✓		

गोल

इटली	स्पेन
1	1
फेडरिको चिएसा (60वां मिनट)	अल्वारो मोराता (80वां मिनट)

इटली 4-2 से पेनाल्टी शूटआउट में जीता

1968 में यूरो चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली इटली की टीम चौथी बार फाइनल में पहुंची है

9 साल बाद इटली फाइनल में पहुंचा है। 2012 उसे स्पेन के हाथों ही फाइनल में शिकस्त मिली थी

10वीं बार इटली किसी बड़े टूर्नामेंट (विश्व कप/यूरो कप) के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। अब तक जर्मनी ने सबसे ज्यादा 14 बार फाइनल खेला है

2 बार स्पेन इस टूर्नामेंट में नाक आउट में शूटआउट में पहुंची। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को शूटआउट में हराया था। यूरो कप में कोई भी टीम लगातार दो शूटआउट मैच नहीं जीती है

दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थीं। इटली ने हालांकि चौथी पेनाल्टी में 3-2 की बढ़त हासिल की और यहीं से स्पेन चूक गया। स्पेन ने चौथी पेनाल्टी मिस की और इटली ने 3-2 की बढ़त बनाई। इटली ने पांचवीं पेनाल्टी भी हासिल कर ली जबकि स्पेन फिर चूक गया। अंत में इटली 4-2 से मुकाबला अपने नाम कर फाइनल में पहुंच गया।

"खिलाड़ियों का यह समूह शानदार है। सभी जीतना चाहते हैं लेकिन, खिलाड़ियों का यह समूह कुछ विशेष करना चाहता है। **राबर्टो मेनसिनी**, कोच, इटली

33 पिछले मैचों से अजेय है इटली की टीम जो राष्ट्रीय रिकार्ड है

एक नजर में

शेफाली-स्नेह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए नामित

दुबई: भारत की आक्रामक युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा और आलराउंडर स्नेह राणा को इंग्लैंड के मौजूदा दौरे पर शानदार प्रदर्शन के बाद जून के लिए आइसीसी के महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। भारतीय की इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा इंग्लैंड की बायें हाथ की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन को भी महिला वर्ग में नामित किया गया है। पुरुष वर्ग में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कोन्वे और तेज गेंदबाज काइल जेमिसन के अलावा दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकाक को नामित किया गया है। (प्रेट्र)

सरे के लिए खेलेंगे अश्विन

लंदन: भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को अगर उनका कार्य वीजा समय से मिल जाता है तो वह इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले सरे की ओर से 11 जुलाई से शुरू होने वाले काउंटी मुकाबले में खेल सकते हैं। (प्रेट्र)

कोहली पांचवें स्थान पर

दुबई : भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आइसीसी की ताजा टी-20 रैंकिंग में अपना पांचवां स्थान बरकरार रखा, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल एक पायदान के फायदे से छठे स्थान पर पहुंच गए। कोहली के 762 अंक हैं और वह इंग्लैंड के डेविड मलान (888 अंक), आस्ट्रेलिया के सफेद गेंद के कप्तान आरोन फिंच (830 अंक), पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (828 अंक) और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कोन्वे (774 अंक) से पीछे हैं। (प्रेट्र)

अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

कोलंबो: सीनियर बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज ने भारत के खिलाफ आगामी सीरीज से नाम वापस ले लिया, जबकि श्रीलंका क्रिकेट ने कहा कि चुने गए 30 में से 29 खिलाड़ियों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह भारत के खिलाफ 13 जुलाई से शुरू हो रही सीमित ओवरों की सीरीज से पहले हुआ है। मैथ्यूज इंग्लैंड का दौरा करके लौटी टीम में नहीं थे। (प्रेट्र)

गिल की जगह भरने इंग्लैंड नहीं जाएंगे शा व पडीक्कल

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीसीसीआइ अभी चोटिल शुभमन गिल की जगह पृथ्वी शा और देवदत्त पडीक्कल को इंग्लैंड नहीं भेजेगा। भारतीय टीम प्रबंधन ने 28 जून को अपने प्रशासनिक मैनेजर गिरीश डोंगरे के जरिये इन दोनों सलामी बल्लेबाजों को भेजने के लिए कहा था। चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा ने दो दिन पहले तक इस मेल का आधिकारिक जवाब नहीं भेजा था। चयन समिति किसी अन्य बल्लेबाज को इंग्लैंड भेजने के मूड में नहीं है क्योंकि चार सलामी बल्लेबाज पहले ही टीम में हैं।

सूत्रों ने कहा, 'पृथ्वी श्रीलंका में ही रहेंगे और 26 जुलाई तक सीमित ओवरों के मैचों में खेलेंगे। उन्हें चुना गया है और उन्हें वह जिम्मेदारी निभानी चाहिए। श्रीलंका सीरीज समाप्त होने के बाद संभावनाओं को तलाशा जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है।' टीम प्रबंधन इसलिए दो ओपनरों को चाहता है क्योंकि वे अभिमन्यु ईश्वरन की तकनीक से प्रभावित नहीं हैं। वह थ्रोडाउन विशेषज्ञ राघवेंद्र का सामना करने में भी खुद को सहज नहीं पाते हैं।

मेसी और नेमार के बीच होगा महामुकाबला

- ब्राजील के बाद अर्जेंटीना भी पहुंचा फाइनल में
- मेसी की टीम ने कोलंबिया को किया पराजित

ब्रासीलिया (ब्राजील), एपी : सुपरस्टार स्ट्राइकर और कप्तान लियोन मेसी अर्जेंटीना को अंतरराष्ट्रीय खिताब दिलाने के लिए कितने बेताब हैं, इसका अंदाजा बुधवार को कोलंबिया के खिलाफ सेमीफाइनल से लगाया जा सकता है। वह चोटिल होने के बाद भी खेलते रहे और जीत दिलाने तक मैदान पर डटे रहे। वहीं, उनकी टीम के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने शूट आउट में तीन अहम पेनाल्टी बचाकर टीम को फाइनल में तक पहुंचाने में अपनी भी अहम भूमिका निभाई। इन दोनों के प्रदर्शन से अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में कोलंबिया को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर कोपा अमेरिका कप के फाइनल का टिकट कटाया। अब फाइनल में मेसी की भिड़ंत नेमार की टीम मेजबान ब्राजील से होगी।

खून निकला लेकिन नहीं टूटी हिम्मत : मेसी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकरों में क्यों गिना जाता है। मैच के दौरान उनका टखने में चोट लगी और खून भी बहने लगा लेकिन इस स्ट्राइकर ने अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी। उन्होंने बहते खून के साथ ही पेनाल्टी शूट आउट में गोल भी दागा। 55वें मिनट में फ्रैंक ने मेसी को टक्कर मारी और वह गिर पड़े। उनकी एड़ी का जोड़ चोटिल हो गया। वहां से खून निकला। रेफरी ने फ्रैंक को यलो कार्ड भी दिखाया।

"एमी (एमिलियानो) शानदार है। हमें उस पर भरोसा था। हमारा लक्ष्य सभी मैचों में खेलना था और अब हम फाइनल जीतने की कोशिश करेंगे। **लियोन मेसी**, कप्तान, अर्जेंटीना

यह भाग्य की बात थी, आज भाग्य मेरे साथ था। ब्राजील की टीम शानदार है, प्रबल दावेदार। लेकिन हमारे पास शानदार कोच, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है और हम जीतने का प्रयास करेंगे।" **मार्टिनेज**, गोलकीपर, अर्जेंटीना

गोलकीपर मार्टिनेज बने नायक : अर्जेंटीना की ओर से लौटारो मार्टिनेज ने सातवें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। मेसी ने बाक्स के अंदर से एक शानदार पास मार्टिनेज को दिया, जिन्होंने इसे गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की। टीम ने इस बढ़त को पहले हाफ तक कायम रखा। दूसरे हाफ में लुइस डियाज ने 61वें मिनट में गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। दोनों टीमों ने फिर बढ़त हासिल करने की कोशिश की लेकिन, अंतिम मिनट तक अन्य गोल नहीं कर सके और मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा। फिर अतिरिक्त समय में भी गोल नहीं हुआ। जिसके बाद पेनाल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज नायक बनकर उभरे जिन्होंने तीन पेनाल्टी बचाई। मार्टिनेज ने शूट आउट में सांचेज, येरी मिल्ना और एडविन कारडोना के शाट रोके। अर्जेंटीना की ओर से रोड्रिगो डि पाल गोल करने में नाकाम रहे लेकिन, मेसी, लियांड्रो पेरेडेस और लाटेरो मार्टिनेज ने अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। कोलंबिया के लिए सिर्फ जुआन कुआड्राडो और मिगुएल बोरजा ही गोल कर पाए।

अब सामने होंगे नेमार : मेसी को कोपा अमेरिका जीतने के लिए नेमार और उनकी मजबूत टीम ब्राजील से भिड़ना होगा जो खिताब की प्रबल दावेदार है। दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे की कमियों को भी अच्छे से जानते होंगे क्योंकि दोनों ही स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के लिए साथ खेल चुके हैं। ऐतिहासिक माराकाना स्टेडियम में रविवार सुबह होने वाला फाइनल महा मुकाबले से कम नहीं होगा। अर्जेंटीना की टीम 1993 में कोपा अमेरिका खिताब जीतने के बाद से कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। उस समय भी अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में निर्धारित समय में मुकाबला गोलरहित बराबर रहने के बाद कोलंबिया को ही पेनाल्टी शूट आउट में 6-5 से हराया था। ब्राजील ने सोमवार को पेरू को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ब्राजील ने स्वदेश में कभी इस टूर्नामेंट का फाइनल नहीं गंवाया है।



पेनाल्टी शूटआउट

2 vs 3

कोलंबिया		अर्जेंटीना	
कुआड्राडो	✓	मेसी	✓
सांचेज	✗	रोड्रिगो	✗
येरी मिल्ना	✗	लियांड्रो	✓
बोरजा	✓	मार्टिनेज	✓
कारडोना	✗		

गोल

कोलंबिया	अर्जेंटीना
1	1
लुइस डियाज (61वां मिनट)	लौटारो मार्टिनेज (07वां मिनट)

अर्जेंटीना पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से जीता

पेनाल्टी शूट आउट में शाट लगाते लियोन मेसी। उनके पैर से निकलता खून (इंसेट में) • एएफपी

विंबलडन में थमा फेडरर का सफर

- 24 साल के हरकाज 39 वर्षीय फेडरर को सीधे सेटों में हराकर पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम के सेमीफाइनल में
- 119 मैच स्विस स्टार रोजर फेडरर ने विंबलडन ग्रैंडस्लैम में खेले हैं जिसमें उनकी यह 14वीं हार है

लंदन, एपी : 20 ग्रैंडस्लैम जीतने वाले रोजर फेडरर का विंबलडन में लड़खड़ाते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाना और वहां पर 18वें नंबर के खिलाड़ी पोलैंड के हुबर्ट हरकाज से सीधे सेटों में हारना यह बताने के लिए काफी है कि कभी दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी रहे स्विस स्टार का रैकेट उम्र के साथ दगा देने लगा है। वह इस क्वार्टर फाइनल मैच में सीधे सेटों में ही हार गए और हरकाज के खिलाफ एक घंटे, 51 मिनट तक ही टिक पाए। अपना नौवां विंबलडन खिताब जीतने पर नजर लगाए फेडरर को हरकाज ने 6-3, 7-6 (7-4), 6-0 से हरा दिया। इसके साथ ही यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या फेडरर युग का अंत हो गया है। पोलैंड के हरकाज ने पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई है।

टूर्नामेंट में संघर्ष : फेडरर ने प्री-क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज करने के बाद कहा था कि जब आप मेरी जितनी उम्र में आ जाते हैं तो आपके सामने तमाम सवाल होते हैं और आप खुद को साबित करना चाहते हैं और आप यह कर सकते हैं। शायद यही सोचकर फेडरर ने इस साल का फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में बीच में छोड़ दिया था और अपने पसंदीदा टूर्नामेंट विंबलडन में उतरे थे लेकिन यहां उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। वह जब अपने पहले मैच में खेल रहे थे तो 2-2 की बराबरी के बाद मैनरिनो को मैच छोड़ना पड़ा और वह आगे बढ़ने में सफल हुए। फिर नूरी के खिलाफ तीसरे दौर के मैच में वह एक सेट हारे तो प्री-क्वार्टर फाइनल में सोनेगो के खिलाफ उनका पहला सेट ही काफी संघर्षपूर्ण रहा था। क्वार्टर फाइनल में वह लय में ही नहीं दिखे और हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

जब हरकाज थे छह साल के : फेडरर ने जब अपना पहला विंबलडन खिताब जीता था तब हरकाज छह साल के थे। अब उन्होंने अपने आदर्श को नौवां और 21वां ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने से वंचित कर दिया। इससे पहले दोनों खिलाड़ियों के बीच भिड़ंत 2019 में इंडियन वेल्स के क्वार्टर फाइनल में हुई थी जहां फेडरर सीधे सेटों में जीते थे। 39 वर्षीय फेडरर दमदार टेनिस खेलते हैं जबकि हरकाज ने इस साल मियामी मास्टर्स जीतकर ग्रैंडस्लैम के लिए अपनी तैयारियां मजबूत की थीं।

नहीं दिखा वो फेडरर : मैच में फेडरर के शाट या तो नेट पर लग रहे थे या कोर्ट से बाहर जा रहे थे। हरकाज के रिटर्न का अच्छा जवाब भी इस खिलाड़ी के पास नहीं था। हरकाज के बैकहैंड क्रास शाट भी दर्शनीय थे। क्वार्टर फाइनल में लगा ही नहीं कि 20 बार का ग्रैंडस्लैम चैंपियन खेल रहा है। जब पहले सेट में फेडरर 1-2 से पीछे थे तो उन्होंने तीन ब्रेक प्वाइंट बचाकर स्कोर 2-2 कर दिया। 2-3 से पिछड़ने के बाद वह अपनी सर्विस गंवा बैठे और स्कोर 2-4 हो गया। 10वें गेम में हरकाज ने पहले सेट प्वाइंट पर यह सेट अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में फेडरर ने हरकाज को थोड़ा परेशान जरूर किया लेकिन टाई ब्रेकर में हार गए।



मैच हारने के बाद निराश फेडरर • रायटर

10वीं बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविक

लंदन : विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके अपने छठे विंबलडन खिताब की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए। सर्बिया के जोकोविक ने सेंटर कोर्ट में हंगरी के गैर वरीयता प्राप्त मार्टन मार्टन फुकसोविक्स को 6-3, 6-4, 6-4 से हराया। यह 10वां अवसर है जबकि वह विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंटों में 41वीं बार अंतिम-चार में प्रवेश किया। जोकोविक ने सहजता से अंक बटोरे और अब वह 20वां ग्रैंडस्लैम खिताब जीतकर रिकार्ड की बराबरी करने की कवायद में हैं। 34 वर्षीय जोकोविक ने इस सत्र में ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंटों में 19 मैच जीते हैं और वह कैलेंडर ग्रैंडस्लैम पूरा करने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। राड लावेर (1969) के बाद कोई भी पुरुष खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाया। पहली बार ग्रैंडस्लैम क्वार्टर फाइनल में खेल रहे फुकसोविक्स के खिलाफ जोकोविक ने 18 मिनट के अंदर 5-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद जोकोविक ने तीन गेम गंवाए और पहला सेट छठे सेट प्वाइंट पर अपने नाम किया। दूसरा और तीसरा सेट जीतने में उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई।

मां ने दूसरे घरों में किया काम, बेटी टोक्यो में चमकाएगी नाम

भूपेंदर सिंह भाटिया • लुधियाना

लुधियाना के गांव चकर के एक सामान्य घर की 14 साल की लड़की सिमरनजीत कौर भट्ट गांव में स्थित शेर-ए-पंजाब अकादमी में बड़े भाई-बहन को मुक्केबाजी करते देखती थी तो उसमें भी इस खेल के प्रति उत्साह जागा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गरीब घर की यह बेटी शौक से मुक्केबाजी के रिंग में उतरने के बाद टोक्यो ओलंपिक का सफर तय कर लेगी। शुरू में पिता कमलजीत सिंह ने मुक्केबाजी में बेटी को भेजने का विरोध किया था, लेकिन मां ने उसका उत्साह बढ़ाया और कामयाबी उसके कदम चूमने लगी। 11 साल के कड़े अभ्यास के बाद सिमरन का एक ही लक्ष्य है, टोक्यो ओलंपिक में राष्ट्रगान की धुन पर तिरंगा फहराना।

मां ने किया प्रोत्साहित : सिमरन का परिवार आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं था कि उनकी डाइट पर अच्छा खासा खर्च कर पाता, लेकिन अकादमी के कोच ने इस छोटी लड़की की प्रतिभा को देखा और उसे तराशना शुरू किया। सिमरन के पिता कमलजीत सिंह 3000 रुपये महीने के वेतन पर सेल्समैन का काम करते थे और मां अन्य घरों में काम कर परिवार चलाती थी। वर्ष 2018 में पिता के गुजर जाने के बाद परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मां ने सिमरन को हर तरह से प्रोत्साहित किया। पिता की मौत के बाद उसी साल तुर्की में हुई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सिमरन ने पदक जीतकर उन्हें समर्पित किया।

नहीं मिल पाती थी डाइट : सिमरन कहती हैं, मां मेरे लिए पिता से भी झगड़ पड़ती थीं। मां ने परिवार चलाने और मेरा शौक पूरा करने के लिए लोगों के घरों में काम किया। मां से मिले हौसले के बाद मेरे अंदर अजीब सी शक्ति का संचार हो जाता। मैं रोजाना घंटों अभ्यास करती। हालांकि मुझे अन्य मुक्केबाजों की तरह अच्छी डाइट नहीं मिल पाती थी।

तैयारी में जुटीं

पांच फुट छह इंच की सिमरन ने वर्ष 2020 में ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था। टोक्यो ओलंपिक में वह लाइटवेट (57-60 किग्रा) वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। अभी वह एएसआइ पुणे में इटली के कोच रैफाएले बर्गामास्को की देखरेख में ओलंपिक पदक जीतने के सपने को साकार करने के लिए तैयारी में जुटी हैं।

उपलब्धियां

2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक

2021 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक

2018 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक



सिमरनजीत कौर • फाइल फोटो, ट्विटर

40 साल के हुए धौनी बधाइयों का तांता लगा

जासं, रांची : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी बुधवार को 40 साल के हो गए। रांची के सिमलिया स्थित अपने फार्म हाउस में माही ने परिवार के लोगों व कुछ अन्य साथियों व शुभचिंतकों के साथ जन्मदिन मनाया। वहीं, रांची समेत पूरे झारखंड में उनके प्रशंसकों ने अलग-अलग तरीके से कैप्टन कूल का जन्मदिन मनाया।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि झारखंडी सपूत और कैप्टन कूल के नाम से दुनिया भर में मशहूर महेंद्र सिंह धौनी झारखंड सहित पूरे देश के लिए गौरव हैं। धौनी झारखंड की शान हैं। उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा की तरह ईश्वर से आपकी लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इंटरनेट मीडिया पर भी उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देने का तांता लगा रहा।

खल गया आजाद भारत के हीरो का जाना

लंदन व हेलसिंकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हाकी टीम के सदस्य केशव दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : आजाद भारत में हाकी के स्वर्णिम युग का आगाज करने वाली भारतीय हाकी टीम का आखिरी स्तंभ भी ढह गया। 1948 में लंदन ओलंपिक और 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हाकी टीम के सदस्य केशव दत्त का 95 वर्ष की उम्र में मंगलवार देर रात कोलकाता के संतोषपुर इलाके में स्थित उनके निवास स्थल पर निधन हो गया। वह काफी समय से बीमार थे।

पिछले साल बलबीर सिंह सीनियर के निधन के बाद केशव स्वतंत्र भारत की पहली ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हाकी टीम के आखिरी जीवित सदस्य बचे थे। भारत ने लंदन के वेंबले स्टेडियम में ब्रिटेन को 4-0 से हराकर इतिहास रचा था। यह वह ऐतिहासिक दिन था, जब आजादी मिलने के एक साल बाद भारतीय हाकी टीम ने अंग्रेजों की सरजमी पर तिरंगा लहराया था और राष्ट्रगान बजाया था।



केशव दत्त • फाइल फोटो, ट्विटर

इसके चार साल बाद हेलसिंकी में भारत ने नीदरलैंड्स को 6-1 से हराया था। केशव दत्त उस भारतीय टीम के उप कप्तान थे। इससे पहले ध्यानचंद के उम्दा खेल के दम पर भारत ने तीन बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन वह आजादी से पहले की भारतीय टीम थी। लंदन ओलंपिक से पहले केशव दत्त ने ध्यानचंद की कप्तानी में पूर्वी अफ्रीका का दौरा किया था। मेजर ध्यानचंद और केडी सिंह बाबू जैसे दिग्गजों से हाकी का ककहरा सीखने वाले केशव दत्त ने पश्चिमी पंजाब शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की।

1925 में लाहौर में जन्मे केशव दत्त अविभाजित भारत में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पंजाब के लिए खेलते थे। विभाजन के बाद वह बांबे (मुंबई) आ गए और उसके बाद 1950 में कोलकाता में बस गए। वह राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बांबे और बंगाल के लिए खेले। मोहन बगान के लिए हाकी खेलते हुए उन्होंने कलकत्ता लीग छह बार और बेटन कप तीन बार जीता। उन्हें 2019 में मोहन बगान रत्न से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले वह पहले गैर-फुटबालर थे।

यादों की दुनिया का



गुरुवार, 8 जुलाई, 2021

दिलीप कुमार... एक ऐसे अभिनेता, जो अपने किरदार में डूब जाते थे। अपने अभिनय और संवाद अदायगी के बल पर उन्होंने हर तरह की भूमिका को पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म मुगल-ए-आजम का शहजादा सलीम हो या नया दौर का तांगेवाला शंकर या शक्ति का पुलिस अफसर अश्विनी, सभी किरदार में वे उसके ही रंग में नजर आते थे। उनका अभिनय बहुरंगी था, जिसने हिंदी सिनेमा को समृद्ध किया।

हम रह गए अकेले...

स्मृति-शेष / दिलीप कुमार

(11 दिसंबर, 1922 – 7 जुलाई, 2021)





1922 में पेशावर में जन्मे थे दिलीप कुमार, उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ सरवर खान था।

चर्चित फिल्में

- मेला (1948) • शहीद (1948)
- आन (1953) • अंदाज (1949)
- देवदास (1955) • नया दौर (1957)
- मधुमती (1958) • यहूदी (1958)
- पैगाम (1959) • कोहिनूर (1960)
- मुगल-ए-आजम (1960)
- गंगा जमुना (1961) • लीडर (1964)
- दिल दिया दर्द लिया (1966)
- राम और श्याम (1967)
- आदमी (1968) • क्रांति (1981)
- कर्मा (1986)

जो रिलीज नहीं हो पाई

- फिल्म : चाणक्य चंद्रगुप्त, निर्देशक : बीआर चोपड़ा
- फिल्म : ताजमहल और आखिरी मुगल, निर्देशक : के आसिफ
- फिल्म : जानवर, निर्देशक : के आसिफ
- फिल्म : कलिंगा, निर्देशक : दिलीप कुमार
- फिल्म : आग का दरिया, निर्देशक : एसवी राजेंद्र सिंह

1944 में फिल्म ज्वार भाटा से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की थी दिलीप कुमार ने। यह फिल्म बाम्बे टाकीज द्वारा बनाई गई थी।



पुरस्कार और सम्मान

- पद्मभूषण (1991)
- दादा साहब फाल्के पुरस्कार (1994)
- निशान ए इम्तियाज (पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 1998)
- किशोर कुमार सम्मान (2014)
- पद्मविभूषण (2015)
- रिकॉर्ड आठ बार 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का फिल्म फेयर पुरस्कार

60 फिल्में की दिलीप कुमार ने अपने अभिनय सफर में, जिनमें दो में वे मेहमान भूमिका में थे। उनका अभिनय सफर 1998 तक चला। उनकी अंतिम रिलीज फिल्म थी 'किला', जिसमें उनका डबल रोल था।

लोकप्रिय सदाबहार गीत

(जो दिलीप कुमार पर फिल्माये गए)

- मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का (बाबुल, 1950)
- ये मेरा दीवानापन है या मुहब्बत का सुरूर... (यहूदी, 1958)
- सुहाना सफर और ये मौसम हंसीं (मधुमती, 1958)
- मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार (नया दौर, 1958)
- ये देश है वीर जवानों का... (नया दौर, 1958)
- अपनी आजादी को हम हरगिज... (लीडर, 1964)
- दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या-क्या ना किया (दिल दिया दर्द लिया, 1966)
- आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले (राम और श्याम, 1967)
- मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले (संघर्ष, 1968)
- आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे (आदमी, 1968)
- सुख के सब साथी दुख में न कोय (गोपी, 1970)
- न तू जमीं के लिए है न आसमां के लिए (दास्तान, 1972)
- हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए (कर्मा, 1986)

पिछली सदी के पांचवें दशक में तीन अभिनेताओं का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा था। राजकपूर, देव आनंद और दिलीप कुमार। राज मसखरे और भोलेपन को जीने वाले तथा दर्द को हंसते हुए पी लेने वाले कलाकार माने गए, तो देव सही में लोगों के लिए आनंद के देव बने। तीसरे दिलीप कुमार ट्रेजडी किंग कहलाए। सही में देखा जाए तो सबसे अधिक मुश्किल काम है दर्द को चेहरे पर लाना और उससे दर्शकों को दर्द में डुबोना। यह काम अपने पूरे अभिनय करियर की अधिकतर फिल्मों में करने वाले दिलीप कुमार को करते हुए तो लंबा अरसा हो गया था। लोगों को उम्मीद थी कि वे अब लोगों को नहीं रुलाएंगे, लेकिन वक्त के आगे किसी की चली है भला...? वह तो अपना काम करता आगे बढ़ता जाता है। जाते-जाते दिलीप साहब एक बार फिर अपने चाहने वालों को रुला और बता गए, ठीक उसी तरह, जैसे वे फिल्म 'आदमी' में गाते हैं, 'न आदमी का कोई भरोसा न जिंदगी का कोई ठिकाना...'। अब उन्हें हम सिर्फ महसूस करेंगे। वे हमारी यादों में जिंदा रहेंगे, अपनी फिल्मों के जरिए, अभिनय के जरिए...।

आशंका तो तभी से तैरने लगी थी, जब देव आनंद की फिल्म 'हम दोनों' रंगीन होकर फिर से रिलीज हो रही थी। तब देव साहब जीवित थे। उन्होंने यूसुफ साहब को फोन मिलाया। सायरा जी ने फोन उठाया, तो दुआ-सलाम हुई, फिर हाल-चाल पूछने के बाद उन्होंने बताया कि मेरी फिल्म रंगीन होकर फिर से रिलीज हो रही है, इसलिए वे प्रीमियर में जरूर तशरीफ लाएं। यह बात सुनने के बाद सायरा जी ने फोन यूसुफ साहब को दे दिया और बताया कि देव साहब का फोन है। उन्होंने फोन हाथ में तो लिया, पर कुछ कहने-सुनने के बजाय सिर्फ और सिर्फ हंसते रहे। वे कुछ समय तक लगातार हंसते ही रहे। कुछ पल ऐसे ही बीता, तो सायरा जी ने उनसे फोन ले लिया और देव साहब से कहा कि मैं कुछ समय बाद उनसे आपकी बात बता दूंगी। उसी वक्त देव साहब को लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है।

पढ़ने का था गजब का शौक

बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरे शौहर दिलीप कुमार को पढ़ने का कितना जबरदस्त शौक रहा। कोई उपन्यास हो, नाटक हो या जीवनी, क्लासिक साहित्य से उनका प्यार हर चीज से बढ़कर था। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी साहित्य की किताबें हमारे बुकशेल्फों की शोभा बढ़ाती रही हैं। मुझे आदत-सी पड़ गई कि उन्हें हर रात टेबल लैंप की रोशनी में बड़े चाव से कुछ न कुछ पढ़ते देखूं, कई बार तो भोर तक। हम मुंबई के अपने घर में हों या दूरदराज के किसी डाक बंगले में या कुल्लू-मनाली या दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में, वे पढ़ने का अपना शौक नहीं छोड़ते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई बच्चा अपने मनपसंद खेल में मगन हो। मेरे बार-बार कहने और बहुत पीछे पड़ने के बाद ही वे हाथ की किताब छोड़ने के लिए राजी होते थे। यूजीन ओ नील, जोसेफ कोनराड, फ्योदोर दास्तोव्यस्की, टेनिसन विलियम्स उनके सबसे पसंदीदा लेखक थे। अगर उनके हाथ में कोई किताब नहीं होती थी तो पक्का मानिए



कि वे किसी स्क्रिप्ट को पढ़ने में डूबे होते थे, जिसकी अगली सुबह शूटिंग होने वाली थी।

सायरा बानो

दिलीप कुमार ने ख्याति पाई ट्रेजडी किंग की, लेकिन सही मायने में वे अभिनय के हर रंग को जीने में माहिर थे। उनकी इन्हीं खासियतों की वजह से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी कहा कि यदि उनके साथ और बाद की पीढ़ी का कोई अभिनेता यह कहता है कि मैं दिलीप साहब की कॉपी नहीं करता, तो वह झूठ बोलता है राजकपूर ने 'प्रेम रोग' के एक सीन में ऋषि कपूर से कहा, यूसुफ की नकल भर कर दो, हमारा काम हो जाएगा। अपने अभिनय सफर में दिलीप कुमार ने कुल साठ फिल्में कीं, जिनमें दो में वे मेहमान भूमिका में थे। 1944 से शुरू हुआ उनका अभिनय सफर 1998 तक चला। उनकी अंतिम रिलीज फिल्म थी 'किला', जिसमें उनका डबल रोल था। इसके बाद वे निर्देशन में आए। लॉरेंस डिसूजा की फिल्म 'कलिंगा' का निर्देशन किया, लेकिन काफी कम समय होने के बावजूद उनका यह ख्वाब अधूरा रह गया। उन्होंने 'कर्मा' और 'मुसाफिर' में गीत गाये, 'गंगा जमुना' के निर्माता बने। 'गंगा जमुना' और 'लीडर' के लेखक वही थे। अपने लंबे अभिनय सफर में कुल साठ फिल्में करके ही वे अभिनय की पाठशाला हो गए। उन्हें फिल्म में खुद को दोहराना पसंद नहीं था। वे अच्छी तरह जानते थे कि एक अभिनेता की पूंजी उसकी प्रतिभा, शरीर और व्यावहारिक बुद्धि होती है। अभिनेता के रूप में ही नहीं, इंसान के रूप में भी उनकी ख्याति दुनिया भर में रही है।

दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ सरवर खान था। उनके पिता फलों के व्यापारी थे। सीमाप्रांत के राज्यों से कारोबार बढ़कर दूर तक जा पहुंचा। वे बंबई (अब मुंबई) आ गए, लेकिन कुछ समस्या थी तो परिवार नासिक के देवलाली में बसा। वहां मुसीबत आई, तो परिवार फिर बंबई आ गया। यहां अंजुम-ए-इस्लाम हाईस्कूल, विल्सन और खालसा कॉलेज में पढ़े।

एक बार काम के सिलसिले में यूसुफ साहब को नैनीताल जाना पड़ा। वहीं उनकी मुलाकात मशहूर अभिनेत्री और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से हुई। संयोग से देविका रानी के पारिवारिक मित्र डा. मसानी उन्हें लेकर देविका रानी के पास गए। थोड़ी देर की मुलाकात में ही यूसुफ खान बन गए अभिनेता दिलीप कुमार और कुछ ही वर्षों में छा गए अभिनय की दुनिया में।

पिछले कई वर्षों से दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ती बनती रही और आखिरकार काल के क्रूर हाथों ने इस अजीम शख्सियत को हमसे छीन दिया। दिलीप कुमार तो चले गये, लेकिन रुपहले पर्दे पर निभाई गई उनकी भूमिकाएं आने वाली पीढ़ियों को हिंदी फिल्मों की समृद्धि का एहसास कराती रहेंगी।



एक संस्थान की समाप्ति। जब भी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा, वह दिलीप कुमार से पहले शुरू होकर दिलीप कुमार के बाद खत्म हो जाएगा।
अमिताभ बच्चन



यूसुफ भाई आज अपनी छोटी-सी बहन को छोड़कर चले गये। युसूफ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। बहुत दुखी हूं। नि:शब्द हूं। कई बातें, कई यादें हमें देकर चले गए।
लता मंगेशकर



फिल्म इंडस्ट्री में अपने सबसे दुलारे भाई को खोने से बहुत दुखी हूं। उन्हें जन्नत नसीब हो।
धर्मेंद्र



दुनियावालों के लिए कई लोग हीरो हो सकते हैं, लेकिन हम कलाकारों के लिए दिलीप कुमार सर हीरो थे। वे अपने साथ भारतीय सिनेमा का एक पूरा काल लेकर चले गए।
अक्षय कुमार



आपके जैसा कोई नहीं मास्टर, यहां से शुरू होता है आपका नया सफर।
मनोज बाजपेयी

जिंदगी सीखने के लिए है...



सुभाष घई
मशहूर निर्माता

दिलीप साहब मेरे सबसे बड़े गुरु और आदर्श रहे हैं। उन्होंने जीवन, समाज और सिनेमा को देखने का मेरा नजरिया बदला है। वह हर तरह से एक मुकम्मल इंसान थे। वह सिर्फ देश के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी इंस्टीट्यूशन रहे हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में विभाजित करूं तो एक है प्री दिलीप कुमार, दूसरा पोस्ट दिलीप कुमार। दिलीप कुमार के संपर्क में आने के बाद फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ अच्छी फिल्म बनाने पर केंद्रित हुआ। विधाता से जुड़ा एक किस्सा साझा करना चाहूंगा। जब फिल्म हिट हुई तो मैंने उन्हें बहुत एक्साइटमेंट में फोन किया। उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मैंने दो दिन बाद दोबारा फिल्म के हिट होने की सूचना देने के लिए उन्हें फोन किया, ताकि इसकी खुशी में पार्टी करें। तब उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि चलो अच्छा हुआ खुदा ने एक गलती और माफ कर दी। मैंने उनसे इसका अर्थ पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि फिल्में चल जाती हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आगे हम पर बेहतर फिल्म बनाने का दबाव होता है। कोशिश ये रहनी चाहिए उसके बाद भी छात्रों की माफिक सीखने का मिजाज बना रहे। जिंदगी सीखने के लिए है। आखिर तक सीखते रहो। दिलीप साहब अपने देश से बेहद प्यार करते थे। विदेश में भी आमंत्रण पर चैरिटी शो में जाया करते थे। उसके लिए वह कभी कोई फीस नहीं लेते थे। एक बार किसी ब्लाइंड एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। किसी प्रशंसक ने उन्हें भेंटस्वरूप दस लाख रुपये का चेक दिया। उन्होंने तुरंत एसोसिएशन के अध्यक्ष को बुलाकर वह धनराशि उन्हें देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने इतने लंबे करियर में कभी विज्ञापन नहीं किया। वह चाहते तो इसके माध्यम से पैसा कमा सकते थे। वह कभी स्टार की तरह व्यवहार नहीं करते थे। वह कहते थे कि मेरे लिए छोटा-सा कमरा और ओढ़ने के लिए साफ चादर काफी है।

चर्चा में रहे संवाद

जिसके दिल में दगा आ जाती है न... उसकी आंखों में दया कभी नहीं आती।
(नया दौर, 1957)

कौन कम्बख्त है जो बरदाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं।
(देवदास, 1955)

तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं... मगर इस बदलती दुनिया में मुहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है... वो इंसान नहीं बदलता।
(मुगल-ए-आजम, 1960)

कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता... तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता।
(क्रांति, 1981)

मुल्क का हर सिपाही जानता है कि उसके जिस्म पर वो खाकी वर्दी... जो उसका मान है.. वो वर्दी उसका कफन भी बन सकती है।
(कर्मा, 1986)

उनके द्वारा की गई तारीफ आजीवन याद रहेगी



शत्रुघ्न सिन्हा
अभिनेता

हम लोग फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आते हैं। यह भी कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का आखिरी मुगल चला गया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी छाप आज भी दिखाई पड़ती है। बड़े-बड़े कलाकार उनकी अदायगी की उपज हैं। मैंने उनके साथ क्रांति फिल्म में काम किया था। मुझे दिलीप साहब ने एक बार बहुत बड़ा काम्प्लिमेंट दिया था क्रांति की शूटिंग के दौरान। उन्हें लंबा-चौड़ा डायलाग दे दिया गया था। मैं उनके पीछे ही बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि मैं इतने लंबे डायलाग इतनी जल्दी याद कर लूंगा। क्या मैं शत्रुघ्न सिन्हा हूं, जो दस पेज का डायलाग याद कर लूं। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा कि सर यह आपने बहुत बड़ा काम्प्लिमेंट दिया है। मैं तो बच्चा हूं आपके सामने। इसे आजीवन याद रखूंगा।

मेरे साथ सीन के मुताबिक कपड़े खरीदते थे

दिलीप कुमार के कपड़ों की खूब तारीफ हुआ करती थी। वे अपने कपड़े मुझसे ही सिलवाया करते थे। 45 वर्षों तक उनके निजी दर्जी रहे इब्राहिम कहते हैं कि यूसुफ साहब के कपड़े आखिर तक मैंने ही बनाए थे। जब वह किसी फिल्म को साइन करते थे, तो मेरे साथ जाकर सीन के मुताबिक कपड़े खुद खरीदते थे। जब विधाता फिल्म आई, तब उसमें उनका और शम्मी कपूर का कोयले वाला इंजन चलाते हुए एक गाना था। निर्माता गुलशन राय ने कहा कि शम्मी कपूर के कपड़े उनका दर्जी बनाएगा, तुम बस नीले रंग का कपड़ा लाकर दे दो। मैंने कपड़ा दे दिया और साहब की ड्रेस बनाकर ले आया। यूसुफ साहब ने उस नई ड्रेस को सड़क पर, ईंटों पर मुझसे रगड़वाया, फिर उसे धोकर पहना। रगड़ने की वजह से ड्रेस पर काले रंग के दाग लग गए थे, जैसे कोयला लगा हो। वहीं शम्मी साहब की ड्रेस एकदम नई लग रही थी।

इब्राहिम खान (दिलीप कुमार के दर्जी)

कड़ी मेहनत के प्रोडक्ट



मनोज कुमार
अभिनेता

दिलीप साहब की खासियत यह थी कि आप उनका दिल अच्छे काम से जीत सकते थे, न कि चमचागिरी से। वह कड़ी मेहनत के प्रोडक्ट रहे। स्टारडम और कड़ी मेहनत का प्रोडक्ट होना दो अलग चीजें हैं। मैं जब भगत सिंह पर आधारित फिल्म शहीद पर रिसर्च कर रहा था उस समय क्रांति का आइडिया मेरे दिमाग में आया। मुझे पता चला था कि मराठा साम्राज्य की नौसेना के प्रथम सेनानायक कान्होजी आंग्रे समंदर में अंग्रेजों और पुर्तगालियों को टिकने नहीं देते थे। इसे ध्यान में रखते हुए दिलीप साहब के किरदार को कान्होजी आंग्रे जैसा बनाया। उस दौरान दिलीप साहब पांच-छह साल से कोई फिल्म नहीं कर रहे थे। एक दिन मैंने उन्हें फोन करके कहा कि साहब एक बोगस-सी कहानी है, जिसके लिए आप फिट हैं। उन्होंने कहा- करते हैं। फिल्म लिखने के बाद फोन किया तो उन्होंने अगले दिन बुला लिया। उनके बड़े भाई नूर साहब की तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब बीमार हैं, मुझे अस्पताल जाना है। कहानी को सुनने में तो तीन घंटे लगेंगे। मैंने कहा- दिलीप साहब जिस कहानी को सुनाने में तीन घंटे लगे, वह कहानी नहीं होती। कहानी वह होती है, जो दो मिनट में सुनाई जाए। मैंने उन्हें दो-ढाई मिनट में आइडिया सुना दिया। थोड़ी देर खामोश रहे। फिर बोले जमीन बड़ी उपजाऊ है। मैंने कहा फिर मेहनत से हल चलाएंगे, तो फसल भी अच्छी होगी। रिलीज के बाद फिल्म सुपरहिट रही।

इनपुट : मुंबई से स्मिता श्रीवास्तव, प्रियंका सिंह, दीपेश पांडेय

नोट : इस विशेष पन्ने के कारण आज सप्तरंग संयम और संकल्प का नहीं दिया जा रहा है।

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 8 जुलाई, 2021 गुरुवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का राशिफल।
आज का राहुकाल: दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक।
आज का दिशाशूल: दक्षिण।
आज की भद्रा: शाम 04:22 बजे तक।

कल 9 जुलाई का पंचांग



कल का दिशाशूल: पश्चिम।
कल का पर्व एवं त्योहार: श्राद्ध की अमावस्या।
विशेष: चतुर्दशी तिथि वृद्धि।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 उत्तरायन, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 05 घंटे 18 मिनट तक, तत्पश्चात् अमावस्या आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात् पुनर्वसु नक्षत्र ध्रुव योग, तत्पश्चात् व्याघात योग मिथुन में चंद्रमा।

मेष: किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उच्च अधिकारी का सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नए संबंध बनेंगे।

वृष: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जीवनसाथी का सहयोग और सान्निध्य मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रगति होगी।

मिथुन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी रखें। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।

कर्क: जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

सिंह: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। दायित्व की पूर्ति में व्यस्त हो सकते हैं।

कन्या: रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा।

तुला: भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी।

वृश्चिक: सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी। पुरुषार्थ सार्थक होगा।

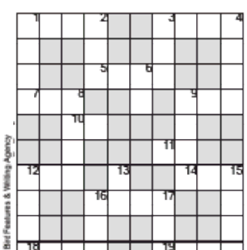
धनु: कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपके हित में न हो। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। बुद्धि कौशल से किए गए कार्य में सफलता मिलेगी।

मकर: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी। दायित्व की पूर्ति होगी।

कुंभ: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नए संबंध बनेंगे।

मीन: व्यावसायिक प्रयास सार्थक होगा। पारिवारिक महिला के कारण तनाव मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में परेशानी मिलेगी। संयम से काम लें।

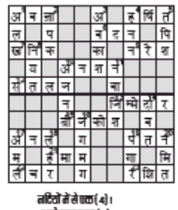
वर्ग पहेली-1630



बाएं से दाएं
[illegible]

ऊपर से नीचे
[illegible]

कल का हल



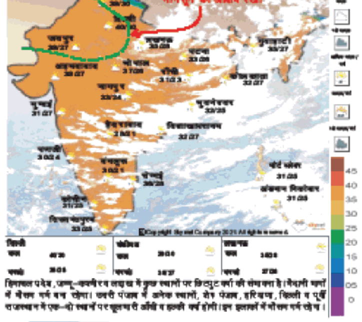
जागरण सुडोकू-1630

		5		2		6		3
	1				7			5
7		4	6		5		1	
3			7			5		4
		7			9		8	
	5		3	4				6
6			5	7		1		
	7	8		1				2
1			4		2		5	7

कल का हल

3	8	7	9	2	4	6	1	5
2	9	6	8	5	1	3	4	7
1	5	4	6	3	7	2	9	8
5	2	9	1	8	6	7	3	4
4	6	1	2	7	3	5	8	9
8	7	3	5	4	9	1	2	6
6	4	2	7	1	8	9	5	3
7	1	8	3	9	5	4	6	2
9	3	5	4	6	2	8	7	1

मौसम



[illegible]

कल पढ़ें

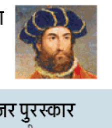


ये बारिश है बूंदों की...

[illegible]

आज ही भारत के लिए रवाना हुए थे पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा

वर्ष 1497 में आज ही के दिन पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की यात्रा के लिए रवाना हुए थे। उनके साथ चार जहाजों में 170 नाविकों का दल आया था, लेकिन लौटने के दौरान मात्र 55 लोग ही दो जहाजों संग लिस्बन पहुंच सके। भारत में हरी मिर्च को पुर्तगाली ही लेकर आए थे।





वॉल स्ट्रीट जर्नल को मिल चुके हैं 35 पुलित्जर पुरस्कार

वर्ष 1889 में आज ही के दिन वॉल स्ट्रीट जर्नल का प्रकाशन शुरू हुआ था। इसकी स्थापना डाउ जोंस एंड कंपनी के चार्ल्स एच डाउ ने की थी। वर्ष 2007 में रूपर्ट मर्डोक ने इसका अधिग्रहण कर लिया। अखबार को अब तक 35 पुलित्जर पुरस्कार मिल चुके हैं।

प्रधानमंत्री बनते-बनते रह गए थे ज्योति बसु

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे ज्योति बसु का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1914 में कोलकाता में हुआ था। वह 1957 में बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। 1967 में बनी संयुक्त मोर्चा सरकार में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 23 सालों तक सत्ता की कमान अपने पास रखी। जब 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार में उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया तो उनकी पार्टी ने इस पर सहमति नहीं दी। इस तरह से उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रह गया। 17 जनवरी, 2010 को उनका निधन हो गया।



...इस तरह बढ़ा सकते हैं बच्चों के आहार में पोषक तत्व

वाशिंगटन, (एएनआइ): माता-पिता को हमेशा यह चिंता रहती है कि बच्चे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं लेते। पोषक तत्वों के सबसे अच्छे माध्यमों में से एक है सब्जियां। बच्चे इन सब्जियों से ही दूर भागते हैं। यदि आप भी यह चिंता सताती है तो यह नया अध्ययन आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इसमें अध्ययनकर्ताओं ने ऐसे तरीके बताए हैं, जिनसे बच्चों को ज्यादा सब्जियां खिलाई जा सकती हैं। इससे न केवल उन्हें इस उम्र में पर्याप्त पोषण मिलेगा, बल्कि इम्यून सिस्टम मजबूत होने से बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम होंगे।

अमेरिका की पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया है, जिसे एपेटाइट नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि बच्चों की थाली में खाना परोसते समय तय मात्रा से अधिक सब्जियां रख दें। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में देखा कि ऐसा करने से बच्चों ने सब्जियों की अधिक मात्रा ग्रहण की। शोधकर्ताओं के मुताबिक, उन्होंने पाया कि जब बच्चों की थाली में कॉर्न और ब्रोकोली की मात्रा दो गुनी कर दी गई (60 ग्राम के स्थान पर 120 ग्राम) तो बच्चों ने 68 फीसद ज्यादा सब्जियों (21 ग्राम अधिक) का सेवन किया।

रखें ख्याल

अध्ययनकर्ताओं ने बताया, सब्जियों से दूर भागने वाले बच्चों को कैसे दें सकते हैं इसकी पर्याप्त मात्रा



स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व लेना जरूरी है। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

उनकी पसंद का खाना भी परोसें

पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में इंसानों के खान-पान के व्यवहार का अध्ययन करने वाले बारबरा रोल्स, हेलेन ए गुथरी के मुताबिक, इस अध्ययन की मदद से बच्चों को उतनी मात्रा में पोषक तत्व दिए जा सकते हैं, जितनी उन्हें इस उम्र में जरूरत होती है। उनके मुताबिक, यह बेहद जरूरी है कि बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर खाना ही परोसा जाए, लेकिन बीच-बीच में उन्हें उनकी पसंद का खाना भी दें। केवल सब्जियां परोसने से यह भी संभव है कि वे उन्हें खाने से इन्कार कर दें। ऐसे में उनकी रुचि का खाना देना भी जरूरी है।

इन बातों का भी रखें ध्यान: शोधकर्ताओं ने इसके अलावा भी कुछ सुझाव दिए हैं, जिससे बच्चों को अधिक सब्जियां खिलाई जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि मक्खन और नमक के जरिये सब्जियों को मसालेदार बना देने से उनकी खपत पर कोई असर नहीं पड़ता है। जरूरी यह है कि जो सब्जियां बच्चों की थाली में परोसी जाएं, वे अन्य चीजों से ज्यादा लजीज हों। साथ ही बच्चों को वे ही सब्जियां दें, जिन्हें वे पसंद करते हैं। इसके अलावा खाने के वक्त थाली में ऐसी चीजें न रखें जो बच्चे इतनी ज्यादा पसंद करते हों कि उनको खाकर ही पेट भर लें और सब्जियां छोड़ दें। दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चों को ज्यादा सब्जियां खिलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों की थाली कैसे तैयार की जाए। एक अच्छी थाली उन्हें न केवल ज्यादा सब्जियों को खाने के लिए प्रेरित कर सकती है, बल्कि लगातार ज्यादा सब्जियां खाने की आदत भी उनमें डाल सकती है। पोषण विज्ञान से स्नातक कर रहे हनीम डिक्सस के मुताबिक, हमने देखा कि इन बदलावों के जरिये बच्चों ने 12 फीसद अधिक सब्जियां ग्रहण कीं। इस तरह की युक्ति से अभिभावकों की यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है कि उनके बच्चे सब्जियां नहीं खाते। शोधकर्ताओं ने उपरोक्त सुझाव एक अध्ययन के आधार पर दिए हैं। उन्होंने बच्चों की थाली में इस प्रकार के बदलाव देखे और पाया कि 76 फीसद बच्चों को यह परिवर्तन पसंद आया और उनमें सब्जियों के ग्रहण करने की मात्रा में इजाफा हो गया।

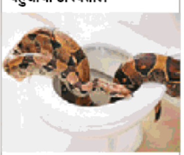


श्वान का भी बचाव...

कोरोना महामारी से लोग सिर्फ स्वयं को ही नहीं बचा रहे, बल्कि अपने पालतू जानवरों को भी सुरक्षित रख रहे हैं। आस्ट्रेलिया के सिडनी में कोरोना संक्रमण से अपने श्वान को बचाने के लिए उसे पारदर्शी बैग में रखकर सिटी सेंटर से होकर गुजरता एक व्यक्ति। रायटर

इधर-उधर की

पड़ोसी के पालतू सांप ने पहुंचाया अस्पताल



नाली के रास्ते बुजुर्ग के बाथरूम में घुसा अजगर ● इंटरनेट मीडिया

आस्ट्रिया, एजेंसी: आपने पड़ोसी के कुत्ते के काटने से किसी को अस्पताल में भर्ती कराने की बात सुनी होगी, लेकिन आस्ट्रिया के ग्राज से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 65 साल के बुजुर्ग को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जब टॉयलेट में निकले अजगर ने उसे काट लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि बुजुर्ग के पड़ोस में रहने वाले 24 वर्षीय युवक ने 11 सांप पाल रखे हैं। हालांकि, इनमें से कोई भी जहरीला नहीं है। जांच से पता चला कि युवक का पालतू अजगर ही नाली के रास्ते बुजुर्ग के बाथरूम में घुसा था। युवक पर लापरवाही और नुकसान पहुंचाने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

कैंसर के इलाज में मददगार 'संरचना' खोजी

तलाशी राह ▸ स्वीडन के अपसला यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को मिली कामयाबी

स्टाकहोम (स्वीडन), एएनआइ: ब्रेन ट्यूमर का इलाज आज भी काफी जोखिम भरा और जटिल बना हुआ है। इसे आसान बनाने के लिए विज्ञानी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में स्वीडन के अपसला यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई उम्मीद जगाई है। उन्होंने ब्रेन कैंसर के रोगियों में ट्यूमर के निकट लिंफ नोड (लसिका ग्रंथि) जैसी एक संरचना की खोज की है, जहां इम्यून सेल को सक्रिय कर ट्यूमर पर हमला किया जा सकता है।

बता दें कि लिंफ नोड (लसिका ग्रंथि) शरीर के इम्यून सिस्टम में सेंस के आकार जैसी एक संरचना होती है। यह समूह या एक चेन में होती हैं, जो लिंफ के जरिये बहने वाले पदार्थों को फिल्टर करते हैं। इसमें लिंफोसाइट (व्हाइट ब्लड सेल) पाए जाते हैं और ये संक्रमण या रोगों से लड़ने में मदद करते हैं।

'नेचर कम्युनिकेशंस' जर्नल में प्रकाशित आलेख के मुताबिक, शोधकर्ताओं ने पाया है कि इम्यूनोथेरेपी से चूहों में उस संरचना का निर्माण तेज हुआ। इस खोज से यह उम्मीद जगी है कि इम्यून सिस्टम में एंटी-ट्यूमर रिस्पांस को रेगुलेट करने का नया अवसर मिल सकता है।

इस वजह से इम्यून सिस्टम नहीं कर पाता अपना काम

ग्लियोमा एक ऐसा जानलेवा ब्रेन ट्यूमर है, जो करीब-करीब लाइलाज है। ब्रेन ट्यूमर का इलाज कठिन होने का एक कारण यह भी है कि हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह का है कि वह कैंसर सेल समेत किसी भी बाहरी सेल को पहचान कर उसे नष्ट कर देता है, लेकिन ट्यूमर के स्थान पर बने कुछ अवरोधों के कारण वह वहां तक पहुंच नहीं पाता।

यह है रास्ता: बढ़ते हुए ट्यूमर से लड़ने के लिए, जरूरी है कि टी-लिंफोसाइट्स जैसे मारक इम्यून सेल को सक्रिय किया जाए और वह लिंफ नोड्स से होते हुए ट्यूमर तक पहुंच सके, लेकिन ब्रेन के चारों ओर बने अवरोधों के कारण टी-लिंफोसाइट्स के लिए ट्यूमर तक पहुंचने की प्रक्रिया एक चुनौती है। अब शोधकर्ताओं ने बताया है कि उन्होंने ब्रेन में लिंफ नोड्स जैसी जिस संरचना की खोज की है, वहां टी-लिंफोसाइट्स को सक्रिय किया जा सकता है।

उत्साहजनक है यह खोज: डिपार्टमेंट आफ इम्यूनोलाजी, जीनेटिक्स एंड पैथोलाजी के शोध छात्र एलेसेंड्रा वैकारो ने बताया कि ग्लियोमा के रोगियों में लिंफ नोड्स जैसी संरचना की मौजूदगी की खोज बहुत ही उत्साहजनक रहा। ये संरचना टर्शरी लिंफायड स्ट्रक्चर (टीएलएस) कहलाती है, जो स्वस्थ इंसान में नहीं पाई जाती है। इन संरचना में वे सभी अवयव हैं, जो एंटी-ट्यूमर इम्यून रिस्पांस पर सकारात्मक प्रभाव डालकर लिंफोसाइट्स को सक्रिय करने में मदद कर सकता है।

यह भी आया सामने: शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि ग्लियोमा ग्रस्त चूहों के ब्रेन में एक विशिष्ट प्रकार की इम्यूनोथेरेपी से टीएलएस के बनने की गति को बढ़ाया जा सकता है। यह भी देखा गया कि रोगग्रस्त चूहों को जब एसडी40 जैसे इम्यूनो उद्दीपक एंडीबाडीज दिया गया तो टीएलएस का निर्माण बढ़ गया और यह ट्यूमर के इर्दगिर्द ही रहा। एक अन्य शोधकर्ता एना डिंबर्ग ने बताया कि यह इस बात का संकेत है कि इम्यूनोथेरेपी के जरिये टीएलएस के निर्माण को व्यवस्थित किया जा सकता है। इससे ग्लियोमा में एंटी-ट्यूमर इम्यून रेस्पांस को रेगुलेट करने का नया तरीका मिल सकता है। फिलहाल ब्रेन ट्यूमर के इलाज में एसडी40 के कई क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। एसडी40 से टीएलएस के बनने में तीव्रता तो आती है, लेकिन इसका नकारात्मक असर यह भी हो रहा है कि टी-लिंफोसाइट्स की ट्यूमर मारक क्षमता कमजोर होती है।

▸ ट्यूमर के निकट खोजी लिंफ नोड जैसी एक नई संरचना

▸ इम्यून सेल को वहां सक्रिय कर ट्यूमर पर किया जा सकता है हमला

▸ चूहों पर किए शोध में विज्ञानियों को मिली सफलता



'नेचर कम्युनिकेशंस' जर्नल में प्रकाशित हुआ है अध्ययन। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

पूरी नींद नहीं लेने पर बढ़ती हैं शारीरिक-मानसिक समस्याएं

अनुसंधान



अच्छी सेहत के लिए पर्याप्त नींद बेहद जरूरी है। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

ठीक तरह से नींद लेना बहुत जरूरी है। एक अध्ययन में सामने आया है कि लगातार तीन दिन तक ठीक से नींद न लेने से आपका शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वास्थ्य खराब होने लगता है। एनल्स आफ बिहेवियरल मेडिसिन में प्रकाशित एक नए अध्ययन में नींद के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। अध्ययन लगातार आठ रातों तक न्यूनतम छह घंटे तक सोने वाले लोगों पर किया गया। आमतौर पर विशेषज्ञ कम से कम छह घंटे की नींद को जरूरी मानते हैं।

अध्ययन करने वालों का नेतृत्व कर रहीं दक्षिण फ्लोरिडा के स्कूल आफ एजिंग स्टडीज की असिस्टेंट प्रोफेसर सूमी ली ने बताया कि एक रात में ही ठीक से नींद न लेने पर खराब लक्षणों का दिखना शुरू हो गया। तीन दिनों के बाद तो शारीरिक और मानसिक रूप से दिक्कतें चिंताजनक स्थिति में पहुंचने लगीं। उस समय शोध के दौरान लगा कि मानव शरीर को कम नींद लेने की आदत पड़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। छह दिन बाद शारीरिक रूप से दिक्कतें गंभीर स्थिति में पहुंच गईं। अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सप्ताहांत में एक दिन भरपूर नींद लेने से सप्ताह के अन्य दिनों में तरोताजा होकर कार्य कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक रात भी कम नींद लेने पर रोजमर्रा के काम पर उसका असर पड़ सकता है।

यह अध्ययन दो हजार लोगों पर किया गया। अध्ययन में देखा गया कि नींद की कमी से गुस्सा, घबराहट, बेचैनी के साथ ही पाचन क्रिया का प्रभावित होना और सांस संबंधी समस्याएं भी बढ़ने लगीं। -एएनआइ

नए टूल से गंभीर रोगियों की बात समझना होगा आसान

▸ रोगियों की बेहतर देखभाल में मिलेगी मदद

वाशिंगटन, एएनआइ: गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की व्यथा व जरूरतों को समझना हमेशा ही एक बड़ी समस्या रही है। यह स्थिति तब और भी जटिल हो जाती है, जब रोगी, डाक्टर या देखभाल करने वाले सांस्कृतिक रूप से अलग-अलग समझ वाले हों, लेकिन यदि इनके बीच संवाद की सटीकता बढ़ जाए तो इलाज और देखभाल को बेहतर किया जा सकता है। इस दिशा में शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर आधारित एक ऐसा टूल विकसित किया है, जिससे संवाद की जटिलताएं कम की जा सकेंगी और रोगी अपना भाव प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त कर सकेगा। यह कंप्यूटर माडल व्यापक स्तर पर वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आटोमेटिक और मान्य टूल उपलब्ध कराता है। इस माडल के प्रयोग का परिणाम 'पीएलओएस वन' जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

यूनिवर्सिटी आफ वरमांट के कंप्यूटर विज्ञानियों, डाक्टरों तथा इंजीनियरों की टीम द्वारा विकसित इस टूल को कोडम (कान्वर्सेशनल डायनामिक्स माडल) एनालिसिस नाम दिया गया है। इसमें सामान्य व्यवहार जन्य माडल (मार्कोव माडल्स) का इस्तेमाल विभिन्न वार्तालाप में सूचना प्रवाह को स्पीकर के बोलने के पैटर्न और फिर से मौका मिलने के अंतराल के आधार पर कैप्चर किया जाता है। अब तक वार्तालाप का विश्लेषण पुराने तरीके से किया जाता रहा है, जिसमें मैनुअल ट्रांसक्रिप्शन और खास टीका-टिप्पणी को शामिल किए जाने कारण ज्यादा समय लगता है। साथ ही इस प्रक्रिया में निजी वार्तालाप के सामग्री तक पहुंचने की भी जरूरत होती है। शोध के प्रमुख लेखक तथा यूनिवर्सिटी आफ वरमांट में पोस्टडाक्टरल एसोसिएट लारेंस क्लारफेल्ड ने बताया कि कोडम पहला मार्कोव माडल है, जिसमें स्पीकर की बारी आने के अंतराल को सूचना की बुनियादी इकाई के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस माडल में वार्तालाप के ट्रांसक्रिप्शन या स्टार किए गए आडियो को शामिल किए बिना रियल टाइम में विश्लेषण हो सकेगा। इससे बातचीत के कंटेंट की निजता भी बनी रहेगी। यूनिवर्सिटी आफ वरमांट में फैमिली मेडिसिन के प्रोफेसर तथा शोध के सह लेखक राबर्ट ग्रैमलिंग ने बताया कि हमने गंभीर रूप से बीमार लोगों से सूचना के प्रवाह को समझने के लिए, एक कंप्यूटर माडल विकसित किया है। यह भावनात्मक अभिव्यक्ति तथा स्पीकर की बारी के पैटर्न जैसे अहम तथा जटिल प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगा सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि सूचना प्रवाह के व्यवहार जन्य प्रवाह के दौरान बात बताने का समय किस प्रकार से गुस्सा, डर और दुख में बदलता है। इतना ही नहीं, इस माडल से भाषा और सांस्कृतिक संदर्भों के संवाद के डायनामिक्स की तुलना की जा सकती है। इससे हेल्थकेयर कर्मियों को प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी और वे व्यापक समझ बना सकेंगे।



झील में सील की अठखेलियां...

फिनलैंड के पुमाला स्थित साइमा झील के पानी में ईया नाम की एक सील मछुआरों के जाल के पास अठखेलियां करती दिखी। यह यहां अक्सर दिख जाती है। साइमा यूरोप के मीठे पानी वाली झीलों में से एक है। यहां दुर्लभ और लुप्तप्राय सील की प्रजाति (साइमा रिंग्ड) पाई जाती है। स्थानीय लोग इसका शिकार नहीं करते। मछुआरे भी इनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। फिनलैंड की झीलों का देश भी कहा जाता है। यहां बड़ी संख्या में छोटी-बड़ी झीलें हैं। एएफपी





मुंबई में बुधवार को अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर उनकी पत्नी सायरा बानो को ढाढस बंधाते अभिनेता शाह रुख खान (बाएं)। राजकीय सम्मान के साथ दिलीप कुमार को अंतिम विदाई दी गई। प्रेट/मिड-डे

दिल्ली... दिलीप कुमार की यादगली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सुपरस्टार दिलीप कुमार से दिल्ली की पुरानी यारी रही। यही कारण है कि आज उनकी विदाई पर राजधानी के साथ यादगारों के कई किस्से ताजा हो गए। कई पुरानी तस्वीरें के किरदार जीवंत हुए तो यहां के सिनेमाघरों के पर्दे नम हो गए। कुछ यादें चांदनी चौक स्थित केदारनाथ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के मालिक केदारनाथ बंसल के साथ भी जुड़ी हैं। उनके साथ दिलीप साहब की निकटता का आलम ये था कि वह सिर्फ इन्हीं की फिल्मों के वितरण का जिम्मा लेते थे। चांदनी चौक में पहले बीआर फिल्म का भी दफ्तर होता था। बीआर चोपड़ा के छोटे भाई फिल्म वितरण का कार्य संभालते थे। दिल्ली में नया दौर फिल्म के वितरण का जिम्मा इन्हीं ने ही संभाला था। इसके अलावा अभिनेता का यहां के सिनेमाघरों से भी खास लगाव था। उनकी फिल्म किस सिनेमाघर में लगेगी यह वही तय करते थे। पुरानी दिल्ली के नावेल्टी, जगत, रिट्ज और मैजेस्टिक उनके पसंदीदा सिनेमाघर थे। जगत सिनेमा के मालिक लाला जगत नारायण सेठ से मिलने दिलीप कुमार आते रहते थे। खास बात यह है कि अपने जश्न में वो यारों को भी शामिल किया करते थे। वर्ष 1961 में रिलीज हुई फिल्म गंगा-जमुना की कश्मीरी गेट स्थित मिनर्वा सिनेमाहाल में सिल्वर जुबली हुई। इसका जश्न मनाने दिलीप कुमार, अभिनेत्री वैजयंती माला सिनेमाहाल आए थे। उस समय अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बेशुमार दर्शक उमड़े थे। आपके लिए दिलीप कुमार से जुड़ीं कुछ यादें...



फिल्म गंगा जमुना के सिल्वर जुबली पर कश्मीरी गेट के पास मिनर्वा सिनेमा में पहुंचे अभिनेता दिलीप कुमार (बाएं) व अभिनेत्री वैजयंती माला। सौ. दिल्ली 4 शो

हर व्यक्ति को नाम से पहचानते थे : संतोष आनंद

दिलीप कुमार जैसा अभिनेता न पहले कभी हुआ है और न होगा। उनमें भारत के असली नायक की छवि दिखती थी। यह कहना है प्रसिद्ध गीतकार संतोष आनंद का। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म क्रांति के गीत लिखने वाले संतोष आनंद ने बताया कि जिंदगी की न टूटे लड़ी... व चना जोर गरम... की शूटिंग के दौरान वह खुद भी सेट पर मौजूद रहे थे। शूटिंग के दौरान शॉट देने के बाद दिलीप कुमार उनके पास आते और बोलते... कैसा शॉट दिया। उनके जैसे महान अभिनेता के इस सवाल पर मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। दैनिक जागरण से बातचीत में दक्षिणी दिल्ली के सुखदेव विहार निवासी संतोष आनंद ने बताया कि शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार के लिए घर का बना खाना आता था। उन्हें पता था कि मुझे भी घर का खाना पसंद है। इसलिए वह अक्सर अपने टिफिन से मुझे भी खाना खिलाते थे। लता मंगेशकर के गीत ये मेरे वतन के लोगों... की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दिलीप कुमार भी पहुंचे थे। वहां मैं भी गया था। उन्होंने मुझे भीड़ के बीच में भी पहचान लिया और आकर गले लगा लिया। यह उनके व्यक्तित्व व व्यवहार का ही कमाल है कि वह हर छोटे-बड़े व्यक्ति को नाम से पहचानते व पुकारते थे।



गीतकार संतोष आनंद। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

मौर्या शेरेटन में होता था नए साल का जश्न

लेखिका जीनत कौसर देहलवी पुराने दिनों को याद करते हुए भावुक हो जाती हैं। कहती हैं सरदार पटेल मार्ग पर हमारा आवास था, जहां दिलीप कुमार आते थे। वह नए साल के उपलक्ष्य में मौर्या शेरेटन होटल में पार्टी देते थे, जिसमें वह दोस्तों व शुभचिंतकों को बुलाते थे। उनके व बाकी साथियों के साथ चांदनी चौक घूमने भी गए थे। वकील जीनत, उन्हें पुरानी दिल्ली का खाना बहुत पसंद था। करीम के कबाब तो वह मंगाकर खाते थे। सायरा बानो से शादी के बाद भी उन्होंने दिल्ली में एक पार्टी दी थी।

पसंद था उनका शायराना अंदाज

दिलीप कुमार गालिब इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी थे। इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी प्रो सादिक-उर-रहमान किदवई ने बताया कि दिलीप कुमार 30 मार्च, 1995 से 27 मार्च, 1999 तक ट्रस्टी थे। इंस्टीट्यूट से संबंधित कई अहम फैसले लिए। वकौल प्रो. सादिक दिलीप कुमार बातचीत के दौरान अक्सर गालिब और मीर की शायरी प्रयोग करते थे। जो लोगों को आकर्षित करती थी।

जब लता का गाना सुनकर भर आई थीं आंखें

दिलीप कुमार की आत्मकथा वजूद और परछाईं, उदयतारा नायर ने लिखी है। किताब में दिलीप कुमार के हवाले से लिखा गया है कि जिंदगी में एक लम्हा ऐसा था, जब गर्व महसूस किया, मेरा गला भर आया। कुछ देर के लिए कुछ कहते नहीं बन रहा था। वह खूबसूरत और यादगार लम्हा 26 जनवरी, 1963 से जुड़ा है। जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में एक विशाल जनसभा में लता मंगेशकर ने ...ऐ मेरे वतन के लोगों... गाना गाकर भारत-चीन लड़ाई के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यह मर्मस्पर्शी गीत सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ही नहीं, दिल्ली कुमार समेत अन्य अतिथि भी रो पड़े थे। किताब में जिक्र है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अशोका होटल में दिलीप साहब लता मंगेशकर से मिले। बाद में होटल में गए तो लता जी को फोन करके पसंदीदा भजन सुनाने की गुजारिश की। लता मंगेशकर ने इन्कार नहीं किया और फोन पर ही अल्ला तेरो नाम सुनाया।

दिलीप कुमार सिल्वर स्क्रीन के वास्तविक लीजेंड थे, उनके रूप में भारतीय सिनेमा ने एक महान अभिनेता खो दिया। उन्होंने अपने अविस्मरणीय अभिनय और प्रतिष्ठित भूमिकाओं से सिनेप्रेमियों की कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया। दिलीप जी के परिवार व प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। **- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री**



दिलीप कुमार के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। आने वाली पीढ़ियां भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान को याद करेंगी। **- राहुल गांधी, कांग्रेस नेता**

एक अपूरणीय क्षति। मेरी पीढ़ी हमारी चेतना को आकार देने वाली उनकी भूमिकाओं के साथ बड़ी हुई। मुझे संसद में उनका सहयोगी होने का सौभाग्य मिला और मैंने चरित्र की ताकत का अर्थ (उनसे) सीखा। सायरा जी और उनके करोड़ों प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। **- सीताराम येचुरी, माकपा महासचिव**

ज्वार भाटा थी पहली फिल्म

प्रथम पृष्ठ से आगे

दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा थी। फिल्म तो खास नहीं चली, लेकिन उनका काम नोटिस हुआ। 25 साल की उम्र में वह देश के श्रेष्ठ कलाकारों में शुमार हो गए थे। वर्ष 1947 में आई फिल्म जुगनू उनकी पहली हिट फिल्म थी। इसके बाद अंदाज, दीदार, नया दौर, मधुमति, देवदास में उनका काम काफी पसंद किया गया। पिछली सदी का छठा दशक उनके करियर में महत्वपूर्ण रहा। उस समय रिलीज फिल्म मुगल-ए-आजम ने उन्हें अलग मुकाम दिलाया। इसी दौर में 1966 में उन्होंने खुद से 22 साल छोटी सायरा बानो के साथ शादी की थी। आखिरी बार वह वर्ष 1998 में रिलीज फिल्म किला में नजर आए थे।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति बोले, दिलीप कुमार एक असाधारण अभिनेता, विनम्र व्यक्ति थे : राष्ट्रपति अल्वी ने अपने ट्वीट में कहा कि दिलीप कुमार एक असाधारण अभिनेता, विनम्र व्यक्ति और सम्मानित शख्सियत थे। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अपनी मां की याद में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए स्थापित ट्रस्ट के लिए धन जुटाने में मदद करने में उनकी उदारता को वह कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान सरकार के कई मंत्रियों, प्रमुख नेताओं, फिल्मी हस्तियों और क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया।